

CHANGING SOCIOECONOMIC BASE OF HUMAN SETTLEMENT SYSTEM IN PRATAPGARH DISTRICT, U.P.



A THESIS
Submitted to the
University of Allahabad
For the Degree of
Doctor of Philosophy
in
Geography

By
POONAM PANDEY

Under the supervision of
Prof. H. N. MISRA

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ALLAHABAD

1992

अनुक्रमिका

	पृष्ठ संख्या
आभार	I-II
सारिणी सूची	III-VI
मानचित्र सूची	VII-VIII
अध्याय 1	सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि
अध्याय 2	अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय पृष्ठभूमि
अध्याय 3	मानव अधिवास तंत्र
अध्याय 4	सेवाकेन्द्रों का स्थानिक विश्लेषण
अध्याय 5	सामाजिक-आर्थिक कारक एवं रूपान्तरण
अध्याय 6	विकास विषमता प्रतिरूप
अध्याय 7	निष्कर्ष तथा नीतिपरक सस्तुतियाँ
साहित्य सागरी	194-210
परिशिष्ट	211-215

आभार

अमृत शोध - प्रबन्ध के प्रस्तुतीकरण के लिये मैं अपने निदेशक परम श्रेष्ठ गुरुवर डा० एच० एन० मिश्रा, रीडर भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय (सम्प्रति प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भूगोल विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला) के प्रति अपना विनम्र आभार प्रकट करती हूँ जो शोध की दिशा में मेरी प्रेरणा के श्रोत रहे हैं एवं जिनके अमूल्य निदेशन, अक्षुण्ण प्रेम, अनवरत प्रयास एवं प्रोत्साहन से ही वर्तमान शोध प्रबन्ध का यह स्वरूप सम्भव हो सका है । साथ ही मैं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सौजन्य से आर्थिक सहयोग के रूप में अवतारल फेलोशिप मिली और शोध प्रबन्ध का अन्तिम रूप पूरा हो पाया । मैं भूगोल विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो० आर० एन० तिवारी एवं वर्तमान अध्यक्ष डा० एस० सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध की रचना में विश्व विद्यालयी आर्थिक सहयोग दिलाकर मेरे प्रयास को सफलता प्रदान की है ।

मैं शान्ति की प्राप्ति श्रीमती शान्ति मिश्रा एवं उनके बच्चों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से मुझे सदैव प्रोत्साहन दिया एवं शोधकार्य की प्राप्ति में अनन्य सहयोगी बनी रही है ।

मैं डा० जेसराम शुक्ला, प्रवक्ता साकेत महाविद्यालय फैजाबाद एवं कनिष्ठ अनुसंधान सहयोगी श्री विनाद तिवारी के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य में अपना सहयोग निरन्तर दिया है । शोध परियोजना के टकण के लिये मो० राशिद एवं मानाचित्र आरेखन के लिए मेरा राजश्रीवास्तव एवं अनवर को बगैर धन्यवाद दिये नहीं रह सकती जिन्होंने शोध प्रबन्ध के वर्तमान स्वरूप को तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान किया है । साथ ही मैं अपने अन्य अनुसंधान सहयोगियों और मित्रों के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने शोध प्रबन्ध के समापन में कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार का सहयोग दिया है ।

अन्त मे मे अपने पूज्य पिताजी, माताजी, तथा भाइयों एवं बहनों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शोध कार्य की लम्बी अवधि मे भी मेरे मनोबल को ऊँचा रखने मे निरन्तर सहयोग प्रदान किया है । साथ ही मे अपने पिता श्री दीपक पाण्डेय एवं परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करना अपना परम कर्तव्य समझती हूँ जिनके सहयोग से शोध प्रबन्ध का यह रूप सम्भव हो सका ।

शुक्ल पक्ष, 1992

पूनाम पाण्डेय
पूनाम पाण्डेय

सारिणी सूची

अध्याय - 2

- 1 1 अध्ययन क्षेत्र का तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व
- 2 2 जनपद में विकास खण्डवार जनसंख्या का घनत्व
- 2 3 जनपद में विकास खण्डवार ग्रामीण - जनसंख्या घनत्व
- 2 4 प्रतापगढ़ जनपद में लिंग अनुपात (1901 - 81)

अध्याय - 3

- 3 1 प्रतापगढ़ जनपद में जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण अधिवासों का प्रतिशत
- 3 2 प्रतापगढ़ जनपद में जनसंख्या वर्ग के अनुसार ग्रामीण अधिवासों में वृद्धि
- 3 3 जनसंख्या वर्ग के अनुसार गावों की संख्या एवं उनमें निवास करने वाली जनसंख्या
- 3 4 प्रतापगढ़ जनपद में अधिवासों का वितरण प्रतिरूप
- 3 5 जनसंख्या वर्ग के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद में नगरीय अधिवासों का वितरण प्रतिरूप
- 3 6 प्रतापगढ़ जनपद में नगरीय अधिवासों की संख्या
- 3 7 प्रतापगढ़ जनपद में नगरीय जनसंख्या एवं लिंग अनुपात
- 3 8 कोटि आकार नियम के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद के नगरीय अधिवासों की जनसंख्या व वास्तविकता से विचलन

अध्याय - 4

- 4 1 प्रतापगढ़ जनपद के सेवा केन्द्रों में उपलब्ध सेवाएँ एवं उनके प्रकार

- 4 2 अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का कार्यात्मक भार
- 4 3 प्रतापगढ़ जनपद के सेवाकेन्द्रों का अधिवारा सूचकांक
- 4 4 प्रतापगढ़ जनपद में तहसील स्तर पर सेवाकेन्द्रों की कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक प्रकार, अधिवास सूचकांक तथा उनकी जनसंख्या का सह-सम्बन्ध गुणांक
- 4 5 सेवाकेन्द्रों में जनसंख्या वृद्धि (1961-81)
- 4 6 सेवाकेन्द्रों में साक्षरता (1961-81)

अध्याय - 5

- 5 1 प्रतापगढ़ जनपद में जनसंख्या वृद्धि
- 5 2 अध्ययन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा भारत वर्ष की जनसंख्या वृद्धि की दिशा
- 5 3 जनपद में विकास खण्डवार जनसंख्या वृद्धि
- 5 4 जनपद में विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि
- 5 5 प्रतापगढ़ जनपद में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या की वृद्धि
- 5 6 प्रतापगढ़ जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
- 5 7 प्रतापगढ़ जनपद में साक्षरता का तुलनात्मक स्वरूप
- 5 8 प्रतापगढ़ जनपद में विकास-खण्ड स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत (ग्रामीण)
- 5 9 प्रतापगढ़ जनपद में व्यावसायिक वर्गों में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत
- 5 10 जनपद में विकासखण्ड स्तर पर जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण (प्रतिशत)
- 5 11 प्रतापगढ़ जनपद में भूमि उपयोग
- 5 12 जनपद में विकासखण्डवार भूमि उपयोग का प्रतिशत (1986-81)
- 5 13 प्रतापगढ़ जनपद में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर/प्रतिशत)

- 5 14 प्रतापगढ जनपद मे विकास खण्डवार फसलों के अतर्गत क्षेत्रफल
- 5 15 प्रतापगढ जनपद मे विकास खण्ड स्तर पर फसल गहनता
- 5 16 प्रतापगढ जनपद मे मुख्य फसलों का उत्पादन (मी० टन)
- 5 17 प्रतापगढ जनपद मे सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
- 5 18 प्रतापगढ जनपद मे सिंचित साधनों की संख्या
- 5 19 प्रतापगढ जनपद मे विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र (प्रतिशत)
- 5 20 प्रतापगढ जनपद मे विकासखण्डवार विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
- 5 21 जनपद मे विकास खण्ड स्तर पर सिंचाई गहनता
- 5 22 विकासखण्ड स्तर पर चुने हुये सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण चर और सह-सम्बन्ध
- 5 23 प्रतापगढ जनपद मे क्रियात्क जेतो की संख्या

अध्याय - 6

- 6 1 प्रतापगढ जनपद मे 22 चरों का सह-सम्बन्ध गुणांक

अध्याय - 7

- 7 1 जनपद मे विकास खण्डवार औद्योगिक इकाइयों
- 7 2 अध्ययन क्षेत्र मे विभिन्न सेवाओं की जनसंख्या सीमा (थ्रेसहोल्ड)

परिशिष्ट संख्या

- 1 भारतवर्ष की जनसंख्या वृद्धिदर तथा मृत्युदर
- 2 प्रतापगढ जनपद मे लिंग अनुपात

- 3 प्रतापगढ जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण जनसख्या मे लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर)
- 4 प्रतापगढ जनपद मे व्यावसायिक वर्गों मे कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत
- 5 प्रतापगढ जनपद मे उद्योगों की सख्या

LIST OF ILLUSTRATIONS

CHAPTER – 1

- 1.1 Hypothetical Relations Between City-Size And Rank
- 1.2 Models of Settlement System Losch's Model
- 1.3 Models of Settlement System Christaller's Model

CHAPTER – 2

- 2.1 Location Map of the Study Area
- 2.2 Administrative Division of Pratapgarh District
- 2.3 Categories of Soil
- 2.4 Physiographic Divisions
- 2.5 Drainage
- 2.6 Climatic Characteristics
- 2.7 Distributional Pattern of Rural and Urban Population
- 2.8 Population Density, 1961-81

CHAPTER – 3

- 3.1 Ancient Sites of Settlements
- 3.2 Evolutionary Model of Service Centres
- 3.3 Distributional Pattern of Settlements

CHAPTER – 4

- 4.1 Rank-Size Relationship of Service Centres

- 4.2 Rank-Size Relationship of Service Centres at Tehsil Level
- 4.3 Relationship Between Size and Settlement Index of Service Centres, 1961-81
- 4.4 Hierarchy of Service Centres
- 4.5 Service Centres, Size and Functional Relationships
- 4.6 Changing Relationships Between Service Centres and their occupational structure 1961-81

CHAPTER – 5

- 5.1 Population Growth in Pratapgarh, U P and India
- 5.2 Population Growth Rate at Block Level
- 5.3 Pattern of Literacy Distribution
- 5.4 Sectoral Composition of Workers at Block Level, 1961
- 5.5 Sectoral Employment of Workers at Block Level, 1981
- 5.6 Land Use Pattern, 1986-87
- 5.7 Area Under Major Crops, 1986-87
- 5.8 Land Use and Irrigation Intensity Differentials, 1979-87
- 5.9 Pattern of Land Holdings, 1980-81
- 5.10 Relationships Among Select Socioeconomic variables at Block Level

CHAPTER –6

- 6.1 The Rostow Model of Economic Development
- 6.2 Myrdal's Process of Cumulative Causation
- 6.3 Spatial Pattern of Development Disparity at Block Level

अध्याय ।

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

मानव अधिवास सांस्कृतिक भूदृश्य के सबसे आकर्षक केन्द्र है (हैमड, 1982) तथा स्थानिक संगठन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। विकास की समस्त योजनाओं का प्रभाव मानव अधिवास के क्रोड में ही प्रस्फुटित होता है। ये मुख्यतः प्रादेशिक अर्थव्यवस्था की उपज है और प्रादेशिक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन मानव अधिवास के सामाजिक व आर्थिक आधार में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। लगभग विगत चार दशकों में मुख्यरूप से पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ कई सामाजिक - आर्थिक परिवर्तन हुये हैं। इस परिवर्तन से क्षेत्रीय संरचना एवं संस्था - दोनों की स्थिति में सुधार हुआ है जिसका अधिवास तंत्र पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। किन्तु परिवर्तन लाने वाले कारकों एवं परिवर्तन से उद्भूत प्रभावों का अध्ययन उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं किया गया है। वास्तव में मानव अधिवास के अध्ययन को उस समय समुचित स्थान प्राप्त हुआ जब 1976 में वैकूबर में अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिवास सम्मेलन सम्पन्न हुआ और विश्व के 138 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया (हरडोय तथा सैटर्थविट 1981)।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य लक्ष्य मानव अधिवास के सामाजिक व आर्थिक आधारों में होने वाले परिवर्तन की गति, दिशा तथा कारकों का स्थानिक एवं कालिक दृष्टि से अध्ययन करना है। अध्ययन के मुख्य लक्ष्य बिन्दु इस प्रकार हैं -

- 1 मानव अधिवास तंत्र का विश्लेषण करना
- 2 मानव अधिवास के सामाजिक - आर्थिक आधारों के रूपान्तरण में लगे हुये प्रक्रमों को स्पष्ट करना।
- 3 सामाजिक - आर्थिक रूपान्तरण से उद्भूत विकास विषमता के प्रतिरूप का सीमांकन एवं विश्लेषण करना।
- 4 मानव अधिवास व क्षेत्रीय संगठन सम्बन्धी कुछ नीतिपरक प्रस्तुतियों का उल्लेख करना।

अध्ययन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत शोध में अधिवास सम्बन्धी सिद्धान्तों का उल्लेख आवश्यक है क्योंकि इनकी समीक्षा से सकल्पनाओं के विकास एवं परीक्षण में सुविधा होती है। अधिवास सम्बन्धी कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का यहाँ पर संक्षिप्त अवलोकन किया गया है

(1) वर्गीकरण का सिद्धान्त - अधिवास के वर्गीकरण का आधार अलग अलग है। सामान्यतः अधिवासों को ग्रामीण अथवा नगरीय अधिवासों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है किन्तु यह वर्गीकरण अपने आप में बहुत ही अपर्याप्त है। अधिवासों के वर्गीकरण के लिए कतिपय विद्वानों ने कुछ विधियों का प्रयोग किया है। कुछ विद्वान उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण करते हैं। बस्तियों के आकार के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिये पुरवा, लघु ग्राम, दीर्घ ग्राम, कस्बा, नगर, नगरमाल अथवा मेगालोपोलिस इसी प्रकार के वर्गीकरण हैं। किन्तु यह सभी प्रकार के वर्गीकरण चाहे वह जनसंख्या के आधार पर हों अथवा अवस्थिति के आधार पर हों - मुख्य रूप से गुणात्मक प्रकार के वर्गीकरण कहलाते हैं। अधिवासों के वर्गीकरण को परिमाणात्मक आवरण प्रदान करने के लिये वर्गीकरण के कई उपागम प्रयोग में लाये गये हैं। यह उपागम वास्तव में सिद्धान्त के रूप में स्थापित हो चुके हैं (हैमण्ड, 1982)। हैरिस (1943) ने व्यवसाय के आँकड़ों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिवासों का विभाजन किया है। और इसके लिये उन्होंने व्यवसाय में लगी हुई जनसंख्या का कुछ प्रतिशत निश्चित किया जो वर्ग विशेष के नगर के लिये आवश्यक था। किन्तु हैरिस का यह वर्गीकरण कई कारणों से उचित नहीं प्रतीत होता। इससे अधिवासों के कार्यों के महत्व का न तो सही उद्घाटन हो पाता है और न ही सभी प्रकार के नगरीय कार्यों का यथोचित मूल्यांकन हो पाता है, क्योंकि यह वर्गीकरण मुख्य रूप से एक समय विशेष के सीमित आँकड़ों पर आधारित है। पावनाल (1953) ने व्यवसाय में लगी हुयी जनसंख्या के औसत के आधार पर नगरीय अधिवास का वर्गीकरण प्रस्तुत किया।

नेल्सन (1955) ने गणितीय औसत एवं प्रामाणिक विचलन के आधार पर एक अन्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो काफी प्रचलित हुआ। किन्तु मोसर तथा स्काट (1961) ने एक अत्यन्त व्यापक स्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसमें विविध प्रकार के सामाजिक व आर्थिक आकड़ों को आधार बनाया गया है। इस वर्गीकरण में उन्होंने 57 चरों का प्रयोग कर प्रिंसिपल कम्पोनेन्ट विश्लेषण विधि के आधार पर ब्रिटेन के नगरों को 14 वर्गों में विभाजित किया। नगरीय अधिवासों के अधिकांश कार्यात्मक वर्गीकरण इन्हीं में से किन्हीं एक विधि का अनुसरण करते हैं।

(2) अधिवास - आकार सिद्धान्त - अधिवास आकार का सिद्धान्त मुख्यतः अधिवासों में रहने वाली जनसंख्या पर आधारित है। अधिवासों की जनसंख्या एक प्रकार से पदानुक्रम की द्योतक है और इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से दो सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं

(अ) कोटि-आकार नियम - यद्यपि की ओरवास महोदय ने सन् 1913 में सर्वप्रथम अधिवास की जनसंख्या और उस पर आधारित कोटि में सम्बन्ध देखा, किन्तु इस नियम का विशद प्रतिपादन एवं प्रयोग सर्वप्रथम जिफ महोदय (1949) ने किया। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि एक क्षेत्र विशेष के सभी ग्रामीण अथवा नगरीय अधिवासों का उनकी जनसंख्या के आधार पर कोटिक्रम निर्धारित की जाये तो 'न' कस्बे अथवा अधिवास की जनसंख्या उस क्षेत्र में पाये जाने वाले सबसे बड़े अधिवास की जनसंख्या का $1/n$ वाँ भाग होगी। क्षेत्र विशेष के दूसरे महत्वपूर्ण अधिवास की जनसंख्या सबसे बड़े अधिवास की जनसंख्या की आधी होगी। वास्तविकता यह है कि इस पदानुक्रम के ऊपरी सतह पर अधिवासों की संख्या कम होगी और निचली सतह पर यह संख्या बढ़ती जायेगी। यह भी देखा गया कि कभी कभी यह वितरण सीढ़ी के आकार का भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर कई अधिवास हो सकते हैं। इस संदर्भ में कोटि-आकार क्रम के कई प्रतिरूप (चित्र 1.1) देखे जा सकते हैं। वास्तविकता यह है कि यह प्रतिरूप वास्तविक धरातल पर बहुत कम खरे उतरते हैं। फिर भी यह नियम बहुत उपयोगी है, क्योंकि वास्तविकता एवं आदर्श का विचलन इससे स्पष्ट होता है और उसके लिये प्रक्रम एवं कारणों का स्पष्टीकरण खोजा जा सकता है (एच0 एन0

HYPOTHETICAL RELATIONS BETWEEN CITY SIZE AND RANK

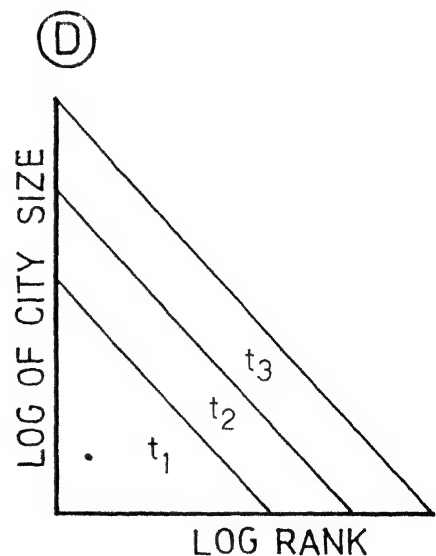
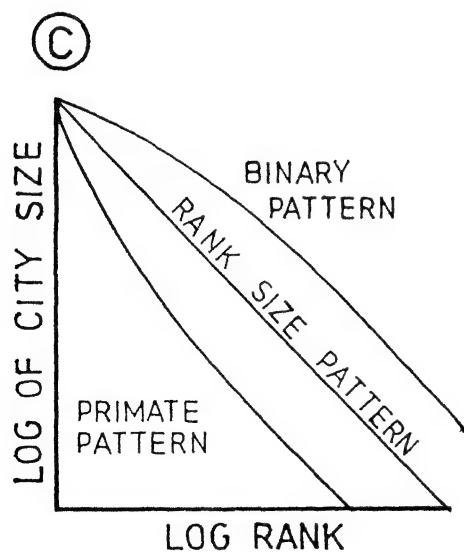
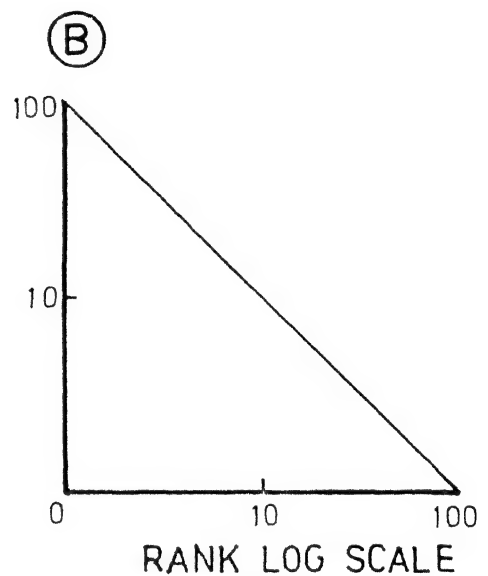
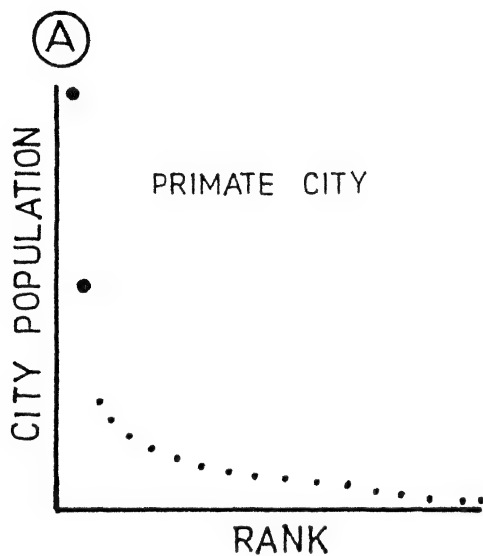


Fig 11

मिश्रा 1975)। कोटि - आकार नियम को प्रदर्शित करने के लिये अधालिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है

$$P_n = \frac{P_1}{n^q}$$

जहाँ P_1 - जनसंख्या कोटि - क्रम ।

P_1 = सबसे बड़े अधिवास की जनसंख्या, तथा

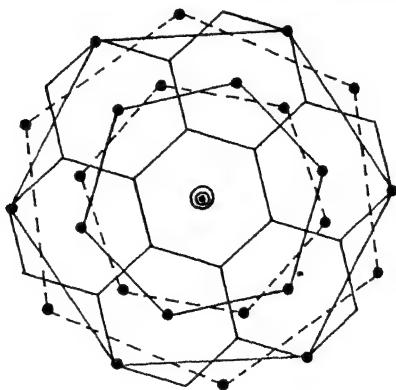
P_n = n क्रम पर अधिवास की जनसंख्या

(ब) प्राथमिक नगर का नियम - प्रस्तुत नियम का प्रतिपादन जैफरसन महोदय (1939) ने किया था । इस नियम को स्पष्ट करते हुये उनका विचार था कि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक कारकों के फलस्वरूप कोई एक नगर बहुत अधिक बड़ा हो जाता है । वह इतना अधिक बढ़ जाता है कि आस पास के अधिवास आकार और कार्य में उससे बहुत छोटे हो जाते हैं । यह सबसे बड़ा नगर ही उस क्षेत्र का प्राथमिक नगर कहलाता है । अनेक विकासशील देशों में इसी प्रकार का प्रतिरूप दिखाई पड़ता है । स्वयं भारतवर्ष में और भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों एवं औद्योगिक प्रदेशों में यह प्रतिरूप दिखाई पड़ता है । कुछ भूगोलविदों में जिनमें लिन्सकी (हैमन्ड 1982) का नाम प्रमुख है, का विचार है कि विकासोन्मुख देशों में वाणिज्य एवं औद्योगिक विकास के फलस्वरूप कोटि आकार नियम ही लागू होता है । किन्तु कई देशों में उदाहरणार्थ, ईरान, कोलम्बिया, पेरू, बनेजुयेला, नाइजीरिया तथा अल्जीरिया में प्राथमिक नगर की संकल्पना ही अधिक वास्तविक प्रतीत होती है । इन नियमों को कहीं भी सामान्यीकरण के आधार पर प्रस्तुत करना उचित नहीं है । भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनके उपयोग का परिणाम भी भिन्न भिन्न होता है ।

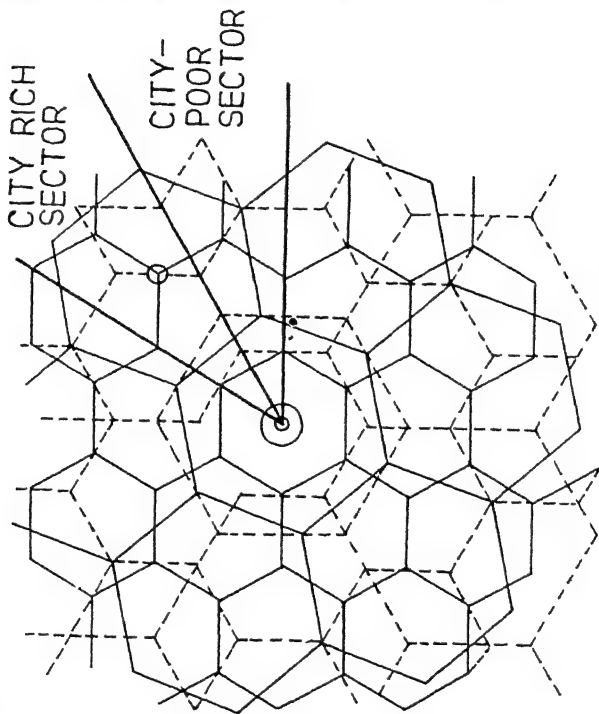
(3) अधिवास, अवस्थिति तथा वितरण सम्बन्धी सिद्धान्त - अधिवास अवस्थिति तथा वितरण सम्बन्धी समस्त सिद्धान्तों में क्रिस्ट्रालर तथा आगस्ट लॉश महोदय के सिद्धान्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं । यद्यपि क्रिस्ट्रालर ने मुख्य रूप से सेवा केन्द्रों के वितरण का सैद्धान्तिक प्रतिरूप प्रस्तुत किया है तथापि उनका यह सिद्धान्त समस्त अधिवासों के वितरण के

MODELS OF SETTLEMENT SYSTEM LOSCH'S MODEL

(A)



(B)



(C)

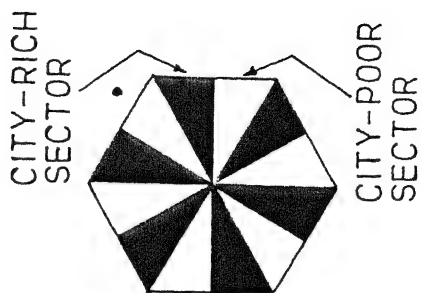


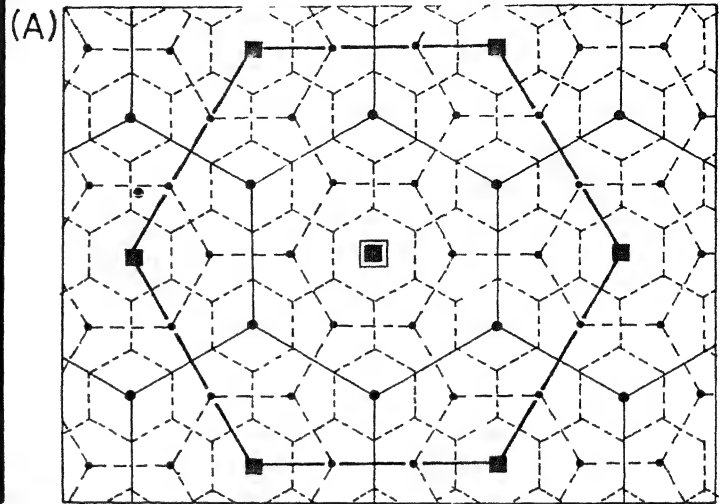
Fig 12

विश्लेषण में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका प्रस्तुत करता है । एक अधिवास जब एक या एक से अधिक सेवाएँ प्रदान करता है, तो उसे सेवाकेन्द्र कहते हैं । सेवाकेन्द्र अथवा अधिवास की जनसंख्या और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सामान्यतः धनात्मक सम्बन्ध होता है । इस प्रकार यदि सेवाकेन्द्र छोटा होता है तो उसमें सेवाएँ कम होती हैं और यदि सेवाकेन्द्र बड़ा होता है तो उसमें अधिक सेवाएँ उपलब्ध होती हैं । और यह ही पदानुक्रम का प्रतीक है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी सेवा के लिये कुछ निश्चित जनसंख्या का होना आवश्यक है । वह जनसंख्या जो किसी सेवा को जीवित रखने के लिये आवश्यक है उसे "मिनिमम थ्रेसहोल्ड" के नाम से जाना जाता है ।

क्रिस्टालर महोदय ने दक्षिणी जर्मनी के अनुभव के आधार पर सन् 1933 में एक सिद्धान्त विशेष का प्रतिपादन किया था जिसे केन्द्रीय स्थल - सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है । यह सिद्धान्त वॉन थ्यूनन (1826) तथा गालपिन (1915) द्वारा प्रतिपादित सकल्पनाओं को अपने में समाहित किये हुये है । इस सिद्धान्त की रूपरेखा प्रस्तुत करने में उन्होंने एक ऐसे धरातल की कल्पना की जहाँ की धरातलीय बनावट, सरचना, ससाधन, मिट्टी, जलवायु तथा जनसंख्या इत्यादि सर्वत्र समान है । इस धरातल को उन्होंने 'आइसोट्रापिक' धरातल की संज्ञा दी है । क्रिस्टालर महोदय ने यह भी माना कि इस प्रकार के धरातल पर पाये जाने वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ, रुचि इत्यादि समान हैं तथा किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिये वे कम से कम दूरी तय करना चाहेंगे । क्रिस्टालर महोदय ने षटभुजीय विपणन क्षेत्र की भी परिकल्पना की है क्योंकि यह सबसे उपयुक्त आकार है, जिसमें धरातल का सम्पूर्ण भाग पूरी तौर पर बिना किसी "ओवरलैप" अथवा "गैप" के अच्छी तरह से सेवा प्राप्त कर सकता है । उनका यह भी विचार है कि अधिवास सेवाकेन्द्र के रूप में जो वस्तु अथवा सेवाएँ प्रदान करते हैं, उनका सेवा क्षेत्र या विपणन क्षेत्र अलग-अलग आकार का होता है । छोटी वस्तु का बाजार क्षेत्र छोटा होगा और मूल्यवान वस्तु का बाजार क्षेत्र बड़ा होगा । अधिवास जितना बड़ा होगा उसकी सेवाएँ भी उतनी ही अधिक होंगी । परिणामस्वरूप अधिवासों में एक प्रकार का सोपानक्रम पाया जाता है एवं षटभुजीय सेवा केन्द्र भी इस सोपान

MODEL OF SETTLEMENT SYSTEM CHRISTALLER'S MODEL

- (A) MARKET PRINCIPLE ($K=3$)
(B) TRAFFIC PRINCIPLE ($K=4$)
(C) ADMINISTRATIVE PRINCIPLE ($K=7$)



KEY

- | | | | |
|--|---------|--|----------------------------------|
| | City | | Boundary of city market area |
| | Town | | Boundary of town market area |
| | Village | | Boundary of village trading area |
| | Hamlet | | Boundary of hamlet market area |

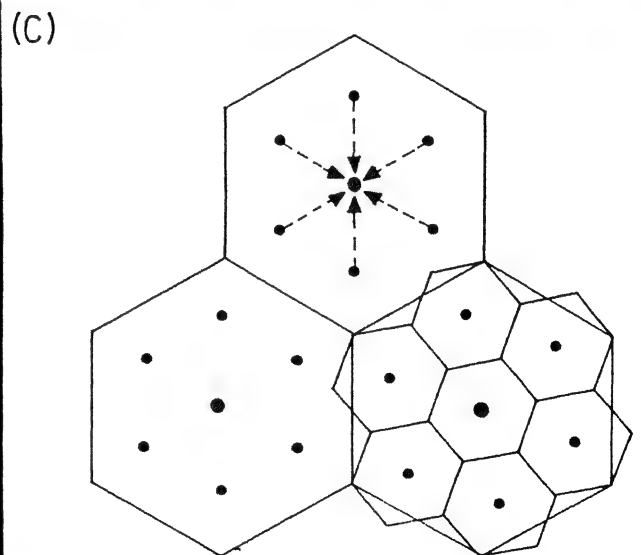
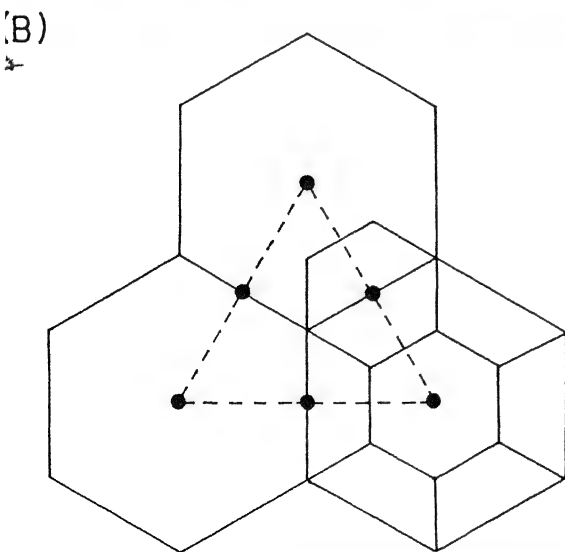


Fig 13

कम की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। निश्चित प्रकार के अधिवास एक निश्चित प्रकार के कार्य और सेवाये सम्पादित करते हैं। उनका सेवाकेन्द्र भी समान होता है और उन सेवा क्षेत्रों में अन्तर भी समान होता है। क्रिस्ट्रालर महोदय ने अधिवासों के सात क्रम निश्चित किये हैं। उन्होंने अधिवासों के सोपानक्रम के निर्धारण में तीन नियम प्रतिपादित किये हैं (अ) विपणन अथवा बाजार नियम के अन्तर्गत अधिवासों का वितरण $k = 3$ सिद्धान्त के आधार पर होगा, जिसमें एक क्षेत्र विशेष में वितरण का क्रम 1,3,9,27 ----- होगा। (ब) यातायात नियम जिसे $k = 4$ से उद्बोधित किया जाता है। इसके अनुसार सोपानक्रम की श्रेणी 1,4,16, 64 ---- होगी, (स) शासकीय नियम जिसे $k = 7$ भी कहा जाता है, के अनुसार अधिवासों का सोपानक्रम 1,7,49,343 इत्यादि होगा। इन तीनों नियमों के अनुसार अधिवासों का वितरण तथा उनका सेवा क्षेत्र चित्र सख्या 1.2 द्वारा स्पष्ट किया गया है। लॉश (1954) ने क्रिस्ट्रालर की इस सकल्पना को सशोधित और परिमार्जित करने का प्रयत्न किया। यद्यपि उन्होंने षट्भुजीय आकार के सेवाकेन्द्र की परिकल्पना की किन्तु वे जनसख्या के समान वितरण की सकल्पना तथा अधिवासों के वितरण में क्रिस्ट्रालर द्वारा प्रतिपादित स्थिर सोपानक्रम से सहमत नहीं थे। उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का आर्थिक भूदृश्य प्रस्तुत किया (चित्र 1.3)। क्रिस्ट्रालर और लॉश महोदय के सिद्धान्तों की अनेक आलोचनाये और प्रत्यालोचनाये हुयी, क्योंकि जिस प्रतिरूप की परिकल्पना इन दो विद्वानों ने की है वास्तविक धरातल पर वह खरी नहीं उतरती। किन्तु फिर भी जिस आदर्श प्रतिरूप को इन दो विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, उससे वास्तविक मापन को बहुत महत्वपूर्ण आधार मिलता है। अधिवास सम्बन्धी विभिन्न आयामों को सैद्धान्तिक प्रारूप प्रदान कर इन दोनों विद्वानों ने विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की नीतियों को प्रतिपादित करने का आधार प्रदान किया है।

क्रिस्ट्रालर द्वारा प्रतिपादित केन्द्र - स्थल सिद्धान्त को कुछ विद्वानों ने परिमार्जित एवं सशोधित कर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है जिसमें बेकमैन (1958), बेरी तथा गैरीसन (1958), डेसी (1966), बेकमैन एवं मैकफरसन (1970) एवं बेर्गुईन (1972) का विशेष स्थान है। अनेक विद्वानों ने क्रिस्ट्रालर के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श एवं वास्तविक वितरण

प्रांतरूपों के विचलन का अध्ययन करने का सराहनीय कार्य किया है जिनका उल्लेख करना ही अपने आप में एक शोध प्रबन्ध होगा (मिश्रा, 1984) ।

4 कार्यात्मक-सम्बन्ध सिद्धान्त - यह सिद्धान्त इस सकल्पना पर आधारित है कि कोई भी सेवाकेन्द्र अथवा नगर पृथक् रह कर जीवित नहीं रह सकता है (जेफरसन 1931) । वह किसी क्षेत्र के कार्यात्मक परिधि में ही रह सकता है और वह अपने चारों ओर विस्तृत क्षेत्र से भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सम्बन्धित होगा । कृषि, उद्योग, व्यापार तथा यातायात पर आधारित अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध कार्यात्मक प्रदेशों को जन्म देते हैं । यह कार्यात्मक प्रदेश अमलैण्ड, प्रभाव क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, नगर प्रभाव क्षेत्र इत्यादि जैसे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं । सम्बन्धों के निर्धारण एवं सीमांकन में विद्वानों ने विविध विधियों का प्रयोग किया है । मूलतया इन्हें गुणात्मक एवं परिणात्मक उपागमों के अन्तर्गत रखा जा सकता है । सामान्यतया नगरों के कार्यात्मक प्रदेशों का सीमांकन गुणात्मक विधियों से किया जाता है, किन्तु कुछ परिमाणात्मक विधियाँ भी प्रयोग में लाई गयी हैं, जिसमें 'ब्रेकिंग प्वाइन्ट समीकरण' एवं 'गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त' पर आधारित 'माडल' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं (मिश्रा, 1971 तथा 1984) । यह उल्लेखनीय है कि क्रिस्टलर तथा लॉश द्वारा प्रतिपादित षटभुजीय क्षेत्र ही कार्यात्मक क्षेत्र नहीं हो सकते, बल्कि उनका आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है । नगर अधिवासों के कार्यात्मक क्षेत्र का आकार वहाँ पर पाई जाने वाली सुविधाओं, व्यावसायिक संरचना, प्रदेश अथवा प्रभाव क्षेत्र की जनसंख्या के घनत्व की विशेषताओं पर आधारित होता है । अधिवासों के कार्यात्मक प्रदेश के सम्बन्ध में बेसिक तथा नानबेसिक सकल्पना का उल्लेख आवश्यक है क्योंकि किसी भी नगर की बेसिक जनसंख्या पर ही उसका कार्यात्मक प्रदेश आधारित होता है । यदि बेसिक जनसंख्या अधिक होगी तो कार्यात्मक प्रदेश बड़ा होगा और यदि बेसिक जनसंख्या छोटी होगी तो कार्यात्मक प्रदेश छोटा होगा । बेसिक तथा नानबेसिक सकल्पना मुख्य रूप से नगर की व्यावसायिक संरचना में लगी हुयी जनसंख्या पर आधारित होती है । इस सकल्पना का सर्वप्रथम उल्लेख अलैक्जैण्डरसन (1956) तथा उलमैन व डेसी (1960) ने किया । इसका सविस्तार उल्लेख एच० एन० मिश्रा

(1986) ने अपने एक लेख में किया है । इस सकल्पना के अनुसार किसी भी व्यावसायिक नगर में मुख्य रूप से दो तत्वों का विश्लेषण होता है -

(अ) बेसिक जनसंख्या व्यावसायिक जनसंख्या का भाग है जिसे आधारभूत जनसंख्या कहते हैं । यह वह जनसंख्या है जो वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में लगी हुयी है तथा जिसके फलस्वरूप आस पास के क्षेत्र से नगर को आर्थिक आधार प्राप्त होता है ।

(ब) नानबेसिक जनसंख्या - व्यावसायिक संरचना का दूसरा वर्ग होता है जो कि केवल नगर में रहने वाली जनसंख्या को ही सेवाएँ प्रदान करता है । नगर के विकास एवं वृद्धि में इस जनसंख्या की भूमिका अधिक नहीं होती है । अतः इसे नानबेसिक जनसंख्या कहा जाता है ।

5 विकास केन्द्र सिद्धान्त - अधिवास तंत्र एवं प्रादेशिक विकास में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर विकास केन्द्र सकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ है । यद्यपि इस सकल्पना की कठोर आलोचना हुयी है, किन्तु फिर भी तृतीय विश्व के विकास की विचार धारा में विकास केन्द्र की सकल्पना सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सकल्पना है । पेराउक्स महोदय (1950, 1955) द्वारा प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धान्त मुख्य रूप से आर्थिक सिद्धान्त है और अस्थानिक है । किन्तु सन् 1966 में वोल्डविली ने इस सकल्पना का न केवल अनुवाद किया अपितु भौगोलिक सकल्पना के रूप में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया । कालान्तर में इस विचारधारा को नियोजकों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला । भारतवर्ष, जैसे देशों में तो इसे एक वैचारिक दर्शन और क्रियात्मक भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में कई विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसमें जानसन (1970), आर० पी० मिश्रा (1974, 1978), हरमनसेन (1971), कुकलिनस्की (1971), मोसली (1971) इत्यादि के कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इस सिद्धान्त की मुख्य विचार धारा यह है कि केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया से विकास सम्भव है । यदि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र में विकास केन्द्र होंगे तो अपने द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक, सुविधाओं के द्वारा आस पास के क्षेत्रों के विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे । अन्तर - प्रादेशिक एवं ग्रामीण -

नगरीय विषमता को दूर करने में इस सिद्धान्त का अनेक भूगोलवेत्ताओं ने बिल्कुल रामबाण के रूप में प्रस्तुत किया है । ऐसा समझा जाता है कि विकास - ध्रुव, विकास केन्द्र, सेवा केन्द्र तथा बाजार केन्द्र का पदानुक्रम मिलकर विकास की एक ऐसी श्रृंखला उत्पन्न करेगा जिससे कि प्रादेशिक विकास को गति मिलेगी (मिश्रा, 1984) । किन्तु इस सिद्धान्त की कटु आलोचना हुयी । विभिन्न स्तर पर अधिवास केन्द्रों की स्थापना में लगने वाला धन कहाँ से मिलेगा ? यह एक महत्पूर्ण प्रश्न है । यह भी मूल प्रश्न है कि यदि इस प्रकार के केन्द्रों की आवश्यकता है तो वह केन्द्र स्वयं क्यों नहीं उत्पन्न होंगे । अधिवासों का विकास क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संरचना पर आधारित है, और जब तक उस प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या की आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं होगी कि वह इन केन्द्रों में स्थित विभिन्न प्रकार की सेवाओं को आश्रय दे सके, इस प्रकार के सेवाकेन्द्र कभी भी विकसित नहीं होंगे । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के केन्द्रों की उत्पत्ति एवं विकास मांग और आपूर्ति पर आधारित है । इसके अतिरिक्त विकास ध्रुव सिद्धान्त "टाप डाऊन उपागम" को प्रश्रय देता है जिसमें विकास की संकल्पना ऊपर से नीचे की ओर की गयी है ।

विकास केन्द्र से मिलती जुलती कई अन्य संकल्पनाएँ भी हैं जिनमें की छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगर पर आधारित विकास तथा झुरमुट अथवा एग्लोपोलिटिन संकल्पनाएँ मुख्य हैं । छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों के विकास के सन्दर्भ में दत्ता (1981), रान्डेनली (1983) तथा मिश्रा (1986) के कार्य उल्लेखनीय हैं । इस संकल्पना के अनुसार प्रादेशिक विकास के लिये छोटें नगरों का विकास यदि किया जाय तो विकास की गति तीव्र होगी ।

साहित्य सामग्री की संक्षिप्त समीक्षा

ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों का अध्ययन, वर्णन की दृष्टि से तो नवीन नहीं है, किन्तु भूगोल में इनका क्रमबद्ध अध्ययन मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण से ही प्रारम्भ हुआ । जहाँ पहले ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन को विशेष बल दिया जाता था वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् नगरीय बस्तियों के अध्ययन को विशेष महत्व मिलने लगा (जानसन 1987, मिश्रा 1989) । अधिवासों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध

से पूर्व अध्ययन का आधार केवल वर्णनात्मक था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् मात्रात्मक एवं विश्लेषणात्मक आधार अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं। किन्तु सन् 1960 और 1970 के बीच आचरणात्मक अध्ययन को अधिक बल मिला। वास्तव में भूगोल के विकास का यह निर्णायक दौर था, जबकि पहली बार यह आवश्यकता समझी गयी कि अधिवासों का अध्ययन एवं वर्णन ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उनकी सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का उल्लेख भी परम आवश्यक है। डेविड स्मिथ (1977) के "सामाजिक कल्याण क्षेत्र उपागम" तथा प्रादेशिक समस्याओं के चित्राकन ने एक नये भूगोल को जन्म दिया जिसे "लिबरल भूगोल" के नाम से जाना जाता है। सन् 1970 के आस पास साम्यवादी भूगोल (मार्क्सवादी) को प्रोत्साहन मिला। मार्क्स का सिद्धान्त ही प्रादेशिक, मानवीय तथा अधिवासी समस्याओं के निराकरण का मुख्य आधार हो गया। डेविड हार्वे (1976) ने इसे "रैडिकल ज्योग्राफी" की सजा दी है। वर्तमान में "संरचनात्मक उपागम" को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिसके विभिन्न पहलुओं पर डेरिक ग्रेगरी महोदय (1978) ने विस्तार पूर्वक विचार किया है। भूगोल की इस विधा में मानवीय निर्णय को निश्चित करने वाले कारकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन ही नहीं अपितु वितरण प्रतिरूप को जन्म देने वाले कारकों का अध्ययन होना चाहिये। वर्तमान संदर्भों में अधिवासों के अध्ययन में नीतिपरक आयामों पर विशेष बल दिया जा रहा है। यद्यपि कि यहाँ पर संविस्तार समीक्षा प्रस्तुत करना कठिन है तथापि इतना तो स्पष्ट ही है कि अधिवासों के अध्ययन में पाश्चात्य भूगोलविदों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि पृष्ठभूमि के रूप में उल्लिखित सैद्धान्तिक योगदानों से स्पष्ट है।

भारतीय भूगोलविदों के अधिवास सम्बन्धी अध्ययन को अधोलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है

1. उत्पत्ति एवं विकास सम्बन्धी अध्ययन - प्रारम्भ में अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन अनेक विद्वानों ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया। कुछ विद्वानों ने एक ही नगर अथवा ग्राम को केन्द्र मान कर उसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा है, किन्तु अधिकांश विद्वानों

ने अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक परिवेश में किया है और उसके आधार पर यथासम्भव भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का उल्लेख भी करने का प्रयत्न किया है । किन्तु इस प्रकार के अध्ययन में मूलतया स्थान एवं स्थिति को विशेष महत्व दिया गया है ।

2 सेवाकेन्द्र सम्बन्धी अध्ययन - इस प्रकार के शोध अथवा अधिवास सम्बन्धी अध्ययन मुख्य रूप से क्रिस्टलर के "केन्द्र स्थल सिद्धान्त" पर आधारित है । इस प्रकार के अधिवास सम्बन्धी अध्ययन में नगरों अथवा ग्रामों को उनके द्वारा प्रदान की गयी विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के आधार पर मूल्यांकित किया गया है । अधिवासों के वर्गीकरण, वितरण, पदानुक्रम, कोटि - आकार सम्बन्ध, सेवा क्षेत्र इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण पक्षों का उद्घाटन इसके अन्तर्गत किया गया है ।

3 प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी अध्ययन -

इस प्रकार का अध्ययन मुख्य रूप से प्रदेश अथवा क्षेत्र विशेष के योजनाबद्ध विकास की दृष्टि से किया गया है । किन्तु इस प्रकार के अध्ययन में ग्रामीण अथवा नगरीय अधिवासों को महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा गया है । इस प्रकार के अध्ययन मुख्य रूप से ध्रुव विकास सिद्धान्त समन्वित ग्रामीण विकास तथा समन्वित क्षेत्र विकास द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं नियमों को ध्यान में रखकर किये गये हैं ।

4 अधिवास समस्या सम्बन्धी अध्ययन - अधिवासों के अध्ययन में कुछ ऐसे भी अध्ययन आते हैं जो ग्रामीण अथवा नगरीय अधिवासों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को उजागर करते हैं । गन्दी बस्तियों का अध्ययन, स्वास्थ्य एवं आवास का अध्ययन तथा स्वास्थ्य एवं पोषक तत्व सम्बन्धी अध्ययन इसके अन्तर्गत आते हैं । वर्तमान में इस प्रकार के अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अधिवासों के सम्यक विकास के लिये इन पक्षों का विश्लेषण परम आवश्यक है । ग्राम एवं नगरों का परिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय अध्ययन भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो गया है । इस प्रकार के अध्ययन नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण

आयाम का कार्य कर सकते हैं ।

भारत के जिन भूगोलविदों ने अधिवास एवं प्रादेशिक विकास सम्बन्धी अध्ययन को आगे बढ़ाने तथा नयी दिशा देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है उनमें मन्जूर आलम (1965), इनायत अहमद (1956), बी० एल० एस० पी० राव (1981, 84), आर० एल० सिंह (1975), आर० पी० मिश्रा (1974, 1978, 1979, 1980), आर० एल० द्विवेदी (1963, 65), एस० एल० कायस्था (1978, 1980, 1981), ए० रमेश (1964), उजागर सिंह (1961), पी० डी० महादेव (1980), के० एन० सिंह (1981), के० वी० सुन्दरम् (1977), एल० आर० सिंह (1958), ए० के० तिवारी (1982), जगदीश सिंह (1971), एच० एन० मिश्रा (1981, 1984, 1987, 1988), वी० के० कुमरा (1980) का कार्य उल्लेखनीय एवं विशेष रूप से सराहनीय है ।

प्रमुख संकल्पनाएं -

अधिवास सम्बन्धी सिद्धान्तों व शोधों की प्रवृत्ति की समीक्षा तथा पर्यवेक्षण के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन में कई संकल्पनाओं का विश्लेषण एवं परीक्षण किया गया है । किन्तु उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं -

1. प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ अधिवासों के सामाजिक-आर्थिक आधार में भी परिवर्तन हो रहा है ।
2. अधिवासों का आकार और उनके सामाजिक-आर्थिक कार्यों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है ।
3. अधिवासों की सामाजिक-आर्थिक संरचना की विषमता प्रादेशिक विषमता को जन्म देती है ।

अनुसन्धान विधि एवं तकनीक

प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक तथा स्थानिक उपागमों का प्रयोग किया गया है । ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का स्थानिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है । इस कार्य में प्राथमिक एवं गौण प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग में लाया गया है । इन आँकड़ों को गुणात्मक व

परिमाणात्क विधियों से विश्लेषित किया गया है । कई स्थलों पर कुछ विशिष्ट तकनीकों का भी उपयोग किया गया है । इनमे समीपस्थ पडोसी तकनीक, कोटि-आकार नियम तथा सह-सम्बन्ध गुणाक विधियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है । सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारित करने के लिये अधिवास सूचकांक का उपयोग किया गया है । कई चरों के आचरण को देखने के लिये सह सम्बन्ध गुणाक का परिकलन किया गया है । खण्ड विकास स्तर पर चरों का चुनाव कर उन्हें स्कैटर डायग्राम तथा रिग्रेशन माडल द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके लिये कम्प्यूटर के एस0 पी0 एस0 एस0 प्रोग्राम का उपयोग भी किया गया है । ऑकड़ों के मुख्य श्रोत इस प्रकार है (1) जिला गजेटियर (2) जिला जनगणना पुस्तिका (3) जिला साख्यकीय पत्रिका (4) जिला वार्षिक योजना (5) जनपद की औद्योगिक प्रगति आख्या ।

विभिन्न आकड़ों को समुचित रूप में परिवर्तित कर उन्हें मानचित्रों एवं आरेखों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है ।

शोध प्रबंध सगठन

प्रस्तुत शोध प्रबंध 7 अध्यायों में सगठित किया गया है । प्रथम अध्याय में अध्ययन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है । मुख्यतया उन सिद्धान्तों का पुनरावलोकन किया गया है जो अधिवास तंत्र विश्लेषण से सम्बन्धित है । द्वितीय अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय प्रस्तुत किया गया है । इसके अन्तर्गत भौगोलिक बनावट, प्रवाह प्रणाली जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज मिट्टी तथा जनसंख्या के वितरण का उल्लेख किया गया है । अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण व नगरीय अधिवास तंत्र का विश्लेषण तृतीय अध्याय में किया गया है । अधिवासों में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन देखने के लिये सेवाकेन्द्रों का चुनाव किया गया है और उनके विविध पक्षों का विवर्णन चतुर्थ अध्याय में किया गया है । अधिवास तंत्र में होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के कारणों का उल्लेख करने के लिये उन्हें क्षेत्रीय परिवेश में विश्लेषित किया गया है और यह विश्लेषण पंचम अध्याय में संविस्तार प्रस्तुत किया गया है । इस विश्लेषण में कई सकल्पनाये सह-सम्बन्धों के माध्यम

से टेस्ट की गयी है । अध्याय षष्ठम् मे सामाजिक-आर्थिक विषमताओ का स्थानिक वितरण प्रतिरूप 22 चरों के माध्यम से किया गया है । इन 22 चरों का एक मापकीय रैखिक रूपान्तरण करने के लिये "जी स्कोर विधि" का प्रयोग किया गया है । इन समस्त विश्लेषणों के आधार पर सप्तम् अध्याय मे निष्कर्ष एवं नीतिपरक सस्तुतियाँ प्रस्तुत की गयी है जो अध्ययन क्षेत्र तथा अधिवास के समन्वीकृत विकास मे सहायक हो सकती है ।

REFERENCES

Ahmad, E.(1956), Origin and Evolution of Towns of Uttar Pradesh, Geographical Outlook, 1, 38-58

Alam, S.M. (1965),Hyderabad-Secunderabad : A Study in Urban Geography, Bombay : Allied publishers.

Alexanderson, G (1956), The Industrial Structure of American Cities, Nebraska, Lincoln.

Beguín, H (1979), Urban Hierarchy and the Rank-Size Distribution, Geographical Analysis 2.

Beckman, M J. (1958), City Hierarchies and the Distribution of City size, Eco-Development and Cultural Change, 6.

Boudeville, J.R. (1966), Problems of Regional Economic Planning, Edinburgh : University Press

Berry, B.J.L., and Garrison, W.L (1958), A Note on Central Place Theory and Range of goods, Eco.Geog.,34

Christaller, W (1966), Central Place in Southern Germany (Translated by C.W Baskin), Englewood Cliffs, New Jersey.

Dacey, M F (1966), Population of places in a Central place Hierarchy, Jl. of Reg. Science,6

Dwivedi, R.L. (1963), Origin and Growth of Allahabad Ind. Geog.Jl. 38, 16 -32

11. Dwivedi, R.L (1965), Demographic Features of Allahabad City, Geog. Rev. Ind, 27, 163-188
12. Dutt, S S. (1981), India's Urban feature : Role of Small and medium towns, Jl. of the Institute of Town Planners, India, 106, 1-7
13. Gregory, D., (1978), Ideology, Science and Human Geography London : Hutchinson.
14. Galpin, G.J. (1915), The Social Anatomy of an Agricultural Community, Research Bulletin of Agricultural Experiment Station, University of Wisconsin, Madison, vol 34
15. Hammond, C.W. (1982), Elements of Human Geography, Allen & unwin : London.
16. Harris, C.D. (1943), A Functional Classification of Cities in United States, Geog. Rev , 33, 86-99.
17. Harvey, D (1976), The Marxist Theory of the State, Antipode, 8 (2)
18. Hermansen, Tormod (1971) Spatial Organization and Economic Development, Mysore : Int. of Dev. Studies
19. Jefferson, M.,(1931) Distribution of the World's City Folks · A Study in Comparative Civilization, Geog. Rev., 21, 446-454

- 20 Jefferson M (1939), The Law of Primate City, Geog. Rev., 29, 226-232
- 21 Johnston, E A J (1970), The Organization of Space in Developing Countries Cambridge, Mass². Harvard University Press
- 22 Johnston, R J. (1987), Geography and Geographers, London : Edward Arnold
- 23 Kumara, V K. (1980), Environmental Pollution and Human Health A Geographical Study of Kanpur City, N.G.J.I. 26, 1 & 2
24. Kayastha, S L and Prasad, J (1978), Approach to Area planning and Development Strategy : A Case study of Phulpur Block, Allahabad District, N.G.J.I., 4
- 25 Kayastha, S L. and Singh, B N. (1981), Spatial Strategy for Integrated Rural Area Development A case study of Ghazipur Tahsil (U.P), India, N.G.J.I., 27, 1 & 2
- 26 Kayastha, S.L. and Singh R B (1980), Emerging Dynamics of Integrated Rural Development, N.G.J.I., 26, 3 & 4.
- 27 Kuklinski, A. and Petrella, R. (eds) (1971), Growth Poles and Regional Policies, The Hague . Mouton
28. Losch A (1954), The Economics of Location, (Translated by W.H. Woglom & W F. Stolper), New Haven

- 29 Mahadev, P.D (1978), Bangalore · A Garden city of Metropolitan Dimension in Misra, R.P. (edit) Million Cities of India, New Delhi · Vikas
- 30 Misra, H N (1989) Traditional and Contemporary Paradigms of Urban Geography, Annal NAGI, 9, 1
- 31 Misra, H N. (1988), The Popular Settlements of Allahabad City CITIES - The International Quarterly on Urban Policy, 5. No 2
- 32 Misra, H N. (1987), Habitat and Health in an Indian Village, in (ed) Misra, H N Rural Geography, New Delhi Heritage Publishers
- 33 Misra, H N (1986), A Model of Economic Base and its Application to the Towns of Uttar Pradesh, in Mahadev, P.D. (ed) Urban Geography, New Delhi : Heritage
- 34 Misra, H N (1986), Rae Bareli, Sultanpur and Pratapgarh Districts, Uttar Pradesh, North India, in Jorge Hardoy et al (ed), Small and Intermediate Urban Centres, Their role in national and regional Development in the third world, London : Hodder and Stoughton
- 35 Misra, H.N (1984), Human ^{Settlement} System and Regional Development in Developing Economy, in Kammeir, H D et al (edit) Equity with Growth, Planning Perspective for Small Towns in Developing Countries, Bangkok AIT, 233-241

- 36 Misra, H N (1984) Urban System of a Developing Economy, Allahabad : IIR . and also in 1988 New Delhi : Heritage Publishers
- 37 Misra, H N (1981), Rural Roots of Urban Poor - A Case Study of Informal Sector in an Indian City, in Misra, R P (edit) Rural Development and National Policies and Experiences, Singapore : Maruzen Asia, 211-229
- 38 Misra, H N. (1980), Towards Alternative Settlement Policy : The case of India, Nagoya : UNCRD
- 39 Misra, H N (1975), The Size and Spacing of Towns in the Umland of Allahabad, The Geogr. 22, 44-55
40. Misra, R.P. et al (1980),Multi-level Planning and Integrated Rural Area Development in India,New Delhi : Heritage
- 41 Misra, R P (ed)(1979),Habitat Asia : Issues and Responses,1-3, New Delhi . Concept
- 42 Misra, R P et al (1978) Regional planning and National Development, New Delhi . Vikas
- 43 Misra, R.P. et al (1974)Regional Development Planning in India : A New Strategy, New Delhi : Vikas
- 44 Moser, C A & Scott, W (1961),British Towns : A Statistical Study of their Social and Economic differences, London : Oliver & Boyd
- 45 Moseley, M J A ,(1974),Growth Centres in Spatial Planning, Oxford : Pergman Press

46. Nelson, H J , (1955), A Service Classification of American Cities, Econ. Geogr. 31, 189-210
47. Perroux. F., (1955) La Nation de Croissance, Economique Applique Nos 1 & 2.
48. Perroux. F.,(1950) Economic Space : Theory and Application,
Quarterly Jl. of Economics.
49. Pownall, L.L , (1953) The Functions of New-Zealand Towns, A.A.A.G., 43, 332-850
50. Rao, V L.S P ,(1964), Towns of Mysore State, Bombay: Asia Publishing House.
51. Ramesh, A.. (1964), Origin and Evolution of Ootacamond, N.G.J.I. 10, 16-28
52. Rondinelli, D A., (1983), Secondary Cities in Developing Countries : Policies for Diffusing' Urbanization, Beverly Hill: Sage Publication.
53. Singh, J., (1971), Rural Settlement Types and Patterns in Baghelkhand, MadhyaPradesh, India, N.G.J.I., 17, No , 4
54. Singh, K.N. (1981), Spatial Analysis of Rural Settlements and their types in Lower Ganga-Ghagra Doab, N.G.J.I. 27, No. 3 & 4

- 55 Singh, U, (1961), Allahabad - A Study on its Planning and Development, N.G.J.I., 7
56. Singh, L R.. (1958), Rural Settlements in the Tarai Region, Nat. Geogr., 3,
57. Singh, R L etal (ed) (1975), Readings in Rural Settlement Geography, Varanasi. N.G.J.I.
- 58 Smith, D M. (1977), Human Geography : A Welfare Approach, London . Edward Arnold.
- 59 Sundaram, K.V (1977), Urban and Regional Planning India, New Delhi : Vikas.
- 60 Tiwari, A.K., (1982), Spatial Aspects of Rural Development in Indian Desert, The Geographer, 29, 26-35
- 61 Ullman, Edward, L and Machael F. Dacey (1960), The Minimum Requirement Approach to the Urban Economic Base, Reg.Sci. Assn. papers and Proceedings 175-194
- 62 Von Thunen, H.(1826), Deriso-lierte State in Bezichug Hug landurirts Chaft and National Konomic, Rostak Translated by Warteburgh C.M As von Thuman's Isolated State, London : Oxford university Press
- 63 Zipf. G.K. (1949), Human Behaviour and Principle of least effort, New York - Addison - Wesley.

अध्याय 2

अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय पृष्ठभूमि

विद्यमान अध्याय में प्रस्तुत शोध विषय से सम्बन्धित सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि का पुनरावलोकन किया गया है । यह विवेचन ही आधारभूमि की रचना करता है । प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक व्यक्तित्व का विवेचन किया गया है । इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की स्थिति, भौगोलिक परिच्छेदिका, जलवायु, खनिज, वन सम्पत्ति एवं मिट्टी तथा जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का रेखांकन किया गया है ।

भौगोलिक परिच्छेदिका

स्थिति तथा विस्तार - उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी अंचल में स्थित प्रतापगढ़ जनपद ($25^{\circ} 24'$ से $26^{\circ} 11'$ उत्तर अक्षांश तथा $81^{\circ} 19'$ से $82^{\circ} 27'$ पूर्वी देशान्तर) उत्तर में मुल्तानपुर, पूर्व में जौनपुर, दक्षिण में इलाहाबाद, पश्चिम में रायबरेली तथा फतेहपुर जनपदों की सीमाओं से आवृत्त है । पूर्व-पश्चिम 115 किलोमीटर लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण 40 किलोमीटर चौड़ा यह अध्ययन क्षेत्र 3730 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है । प्रशासकीय दृष्टि से यह चार तहसीलों एवं पन्द्रह सामुदायिक विकास खण्डों में विभक्त किया गया है (चित्र संख्या 2.1 तथा 2.2) ।

अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1981 में 18,06,833 थी जो 1991 में बढ़कर 22,11,253 हो गयी है । जनसंख्या का घनत्व 1981 में 484 मनुष्य प्रतिवर्ग कि.मी. तथा लिंग अनुपात 1016 था जो 1991 में क्रमशः 595 तथा 929 हो गया है । जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण (97.3%) है । नगरीय जनसंख्या केवल 2.7 प्रतिशत है । जिले में नगरीय अधिवास की संख्या 7 है । कुल आबाद ग्रामीण अधिवास 2185 है जो 171 न्याय पंचायतों तथा 1530 ग्राम सभाओं में विभक्त है ।

धरातलीय रचना भूगर्भीय रचना की दृष्टि से यह भारत के वृहद् मैदानी भाग का उपांश है जिसका निर्माण हिम युग और उसके बाद में गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाये गये निक्षेप से हुआ है (शर्मा, 1959 तथा नेविल, 1904) । अध्ययन क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है । इस मैदान का समतल स्वरूप गंगा, सरई, गोमती व

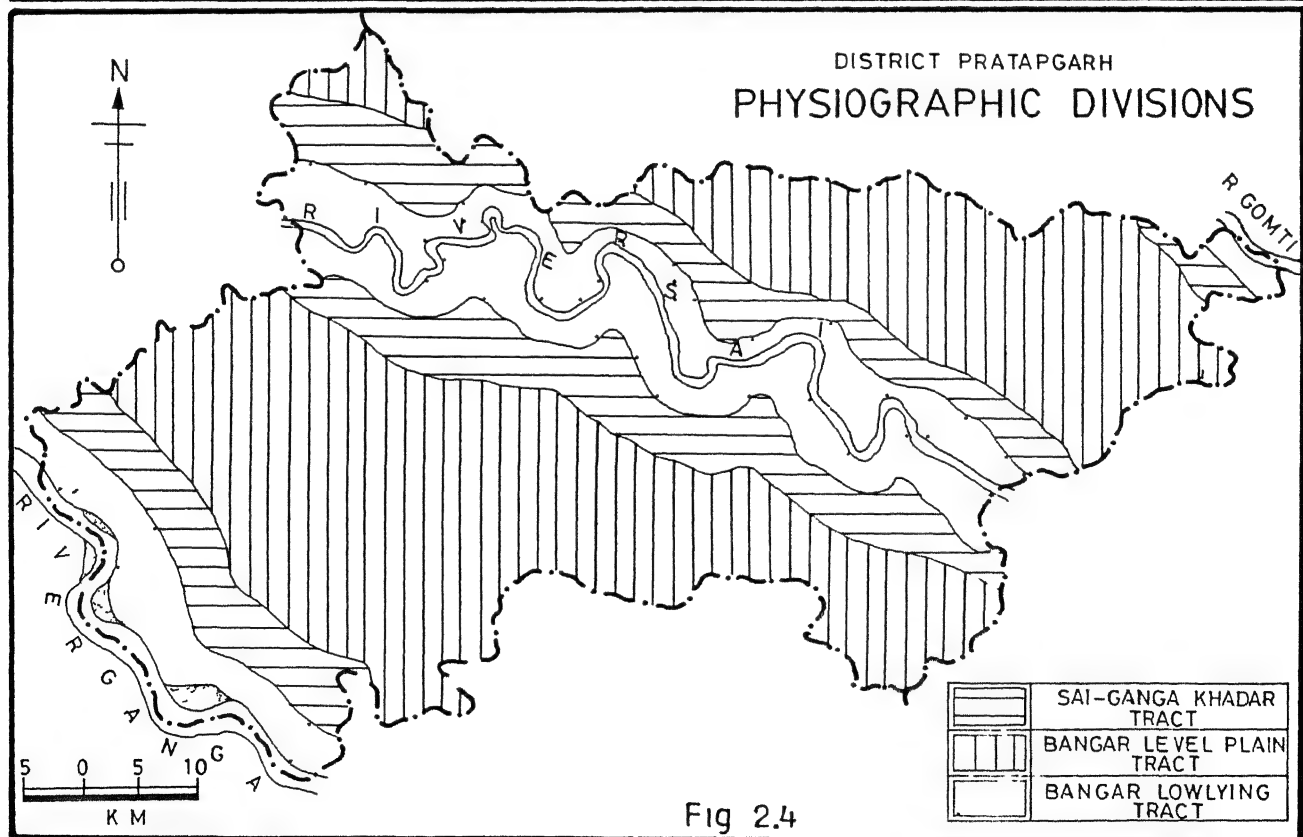
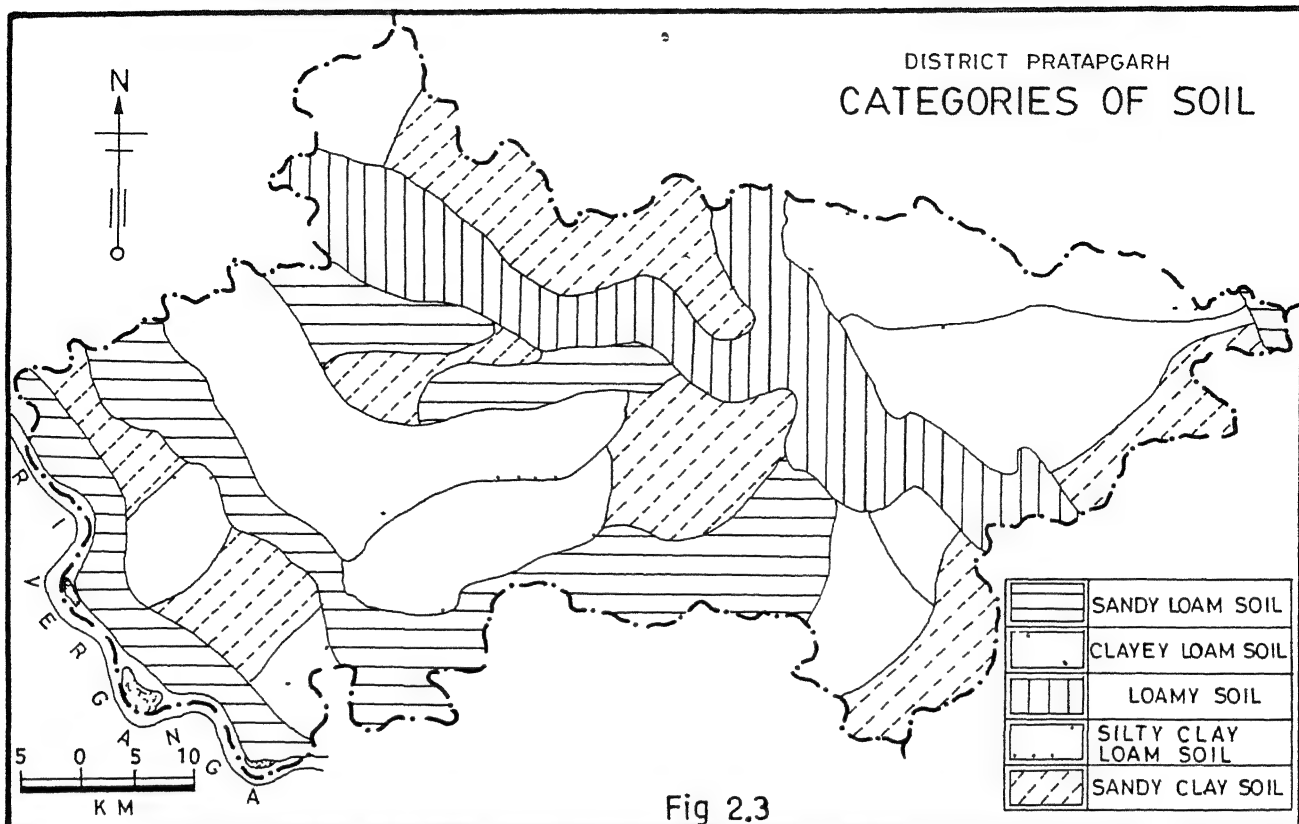
उनकी सहायक नदियों तथा नालों के कटाव से विकृत हो गया है । यह विकृति सई तथा गगा नदी के निकटवर्ती भागों में सर्वाधिक है । बहुत से भाग इतने अधिक असमतल हो गये हैं कि इन पर कृषि कार्य संभव नहीं है । इन असमतल भागों में जंगल पाये जाते हैं । सई नदी अध्ययन-क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है । इस नदी के तटवर्ती भाग में बलुई दुमट मिट्टी की एक पतली पट्टी है जो अधिक उपजाऊ है । इसके बाद बागर भूमि की निचली पट्टी है । रचना की दृष्टि से सम्पूर्ण क्षेत्र को तीन प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है (चित्र सख्या 2 4)

(अ) खादर क्षेत्र - खादर क्षेत्र के अन्तर्गत गगा, सई तथा गोमती नदियों का तटवर्ती भाग सम्मिलित है ।

(ब) समतल बागर क्षेत्र - सई तथा गगा के तटवर्ती खादर क्षेत्र के उपरान्त यह समतल बागर क्षेत्र तीन पेटियों में फैला है । इस क्षेत्र की मिट्टी दुमट है जिसमें बालू के सूक्ष्म कणों के साथ उपजाऊ चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण है । इस उपजाऊ मिट्टी में स्थान स्थान पर ककड का भी मिश्रण मिलता है । साधारणतया इस ककड का उपयोग कच्ची सड़कों के निर्माण में किया जाता है । इस क्षेत्र में आम, नीम, महुआ, पीपल, बरगद, कटहल, नीम आदि वृक्ष पाये जाते हैं ।

(स) निचला बागर क्षेत्र - यह क्षेत्र दो भागों में विभक्त है प्रथम भाग में सई तथा गगा नदी का मध्यवर्ती भाग है जो सई के दक्षिण तथा गगा के उत्तर में स्थित है । द्वितीय भाग सई के उत्तर में एक पतली पट्टी के आकार में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है । निचली भूमि होने के कारण इस क्षेत्र में तालाब व झीलों की अधिकता है । इस क्षेत्र में जहाँ कहीं ऊँची भूमि का क्षेत्र है वह मुख्यतः ऊसर तथा अनुपजाऊ है निचले भाग की मिट्टी चिकनी तथा मटियार है जिसकी उर्वरता सामान्य से अधिक है ।

जल प्रवाह - अध्ययन क्षेत्र के प्रवाह प्रणाली का मुख्य श्रोत गगा, सई तथा गोमती व उनकी सहायक नदियाँ हैं (चित्र 2 5) । गगा नदी जनपद के दक्षिणी सीमा पर लगभग 56 कि मी



की दूरी तक बहती है । इसकी सहायक नदी दौर है जो गंगा के समानान्तर बहती हुई जहानाबाद के निकट गंगा से मिल जाती है । सई नदी जनपद के मध्यवर्ती भाग से पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 175 कि मी की दूरी में बहती है । यह नदी हरदोई, उन्नाव, लखनऊ तथा रायबरेली जनपद से बहती हुई अध्ययन क्षेत्र के अठेहा परगना के मुसतफाबाद क्षेत्र में प्रवेश करती है । यह जनपद को उत्तरी तथा दक्षिणी दो भागों में विभक्त करती है । इसके दोनों किनारे पर कई छोटी छोटी नदिया आकर मिलती है जिसमें चमरौरा, परैया, नैया छोड़या, लोनी, सकरनी तथा बकुलाही मुख्य है । गोमती नदी अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी सीमा पर लगभग 8 कि मी की दूरी पर बहती है । गंगा, सई तथा गोमती नदियों में वर्ष भर पर्याप्त पानी रहता है परन्तु इनकी सहायक नदियों में वर्षा ऋतु के बाद पानी सूख जाता है। अध्ययन क्षेत्र में कई झील तथा ताल पाये जाते हैं जिनका निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन से हुआ है । इन झीलों तथा तालों का पानी रबी की फसल की सिंचाई के लिये प्रयोग में लाया जाता है।

जलवायु - मौसम सम्बन्धी आँकड़े स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है । जलवायु का विवेचन बमरौली इलाहाबाद की वेधशाला से उपलब्ध आँकड़े पर आधारित है । अध्ययन क्षेत्र का वार्षिक औसत तापमान 26° से 0° ग्रे है परन्तु मासिक औसत तापमान जनवरी में 17° से 0° ग्रे तथा मई में 34° से 5° ग्रे हो जाता है । मई व जून के महीने में पश्चिम से आने वाली गर्म तथा तेज हवाएँ तापमान को बढ़ाने के साथ साथ स्थिति को असह्य बना देती है (चित्र 2 6) । जून से सितम्बर तक पूर्व से आने वाली पुरवा हवाओं का तथा वर्ष के शेष महीनों में पश्चिम अथवा दक्षिण-पश्चिम से चलने वाली पछुवा हवाओं का प्रभाव रहता है । अक्टूबर व नवम्बर के महीने में वायु का वेग परिवर्तनशील रहता है । वर्षा का मुख्य स्रोत ग्रीष्म मानसून है । वार्षिक वर्षा का औसत 108 से 0 मी है जिसका 85 प्रतिशत जून से अक्टूबर के महीने में प्राप्त होती है । फरवरी व मार्च तथा अप्रैल में होने वाली वर्षा के साथ कभी कभी उपलब्ध वृष्टि हो जाती है, जिससे रबी की फसल को व्यापक हानि पहुँचती है । जाड़े की ऋतु में पाला व तुषारपात भी होता है जो आलू, तिलहन तथा दलहन की फसलों को हानि पहुँचाता है । वार्षिक वर्षा के वितरण प्रतिरूप से स्पष्ट है कि वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है ।

DISTRICT PRATAPGARH DRAINAGE

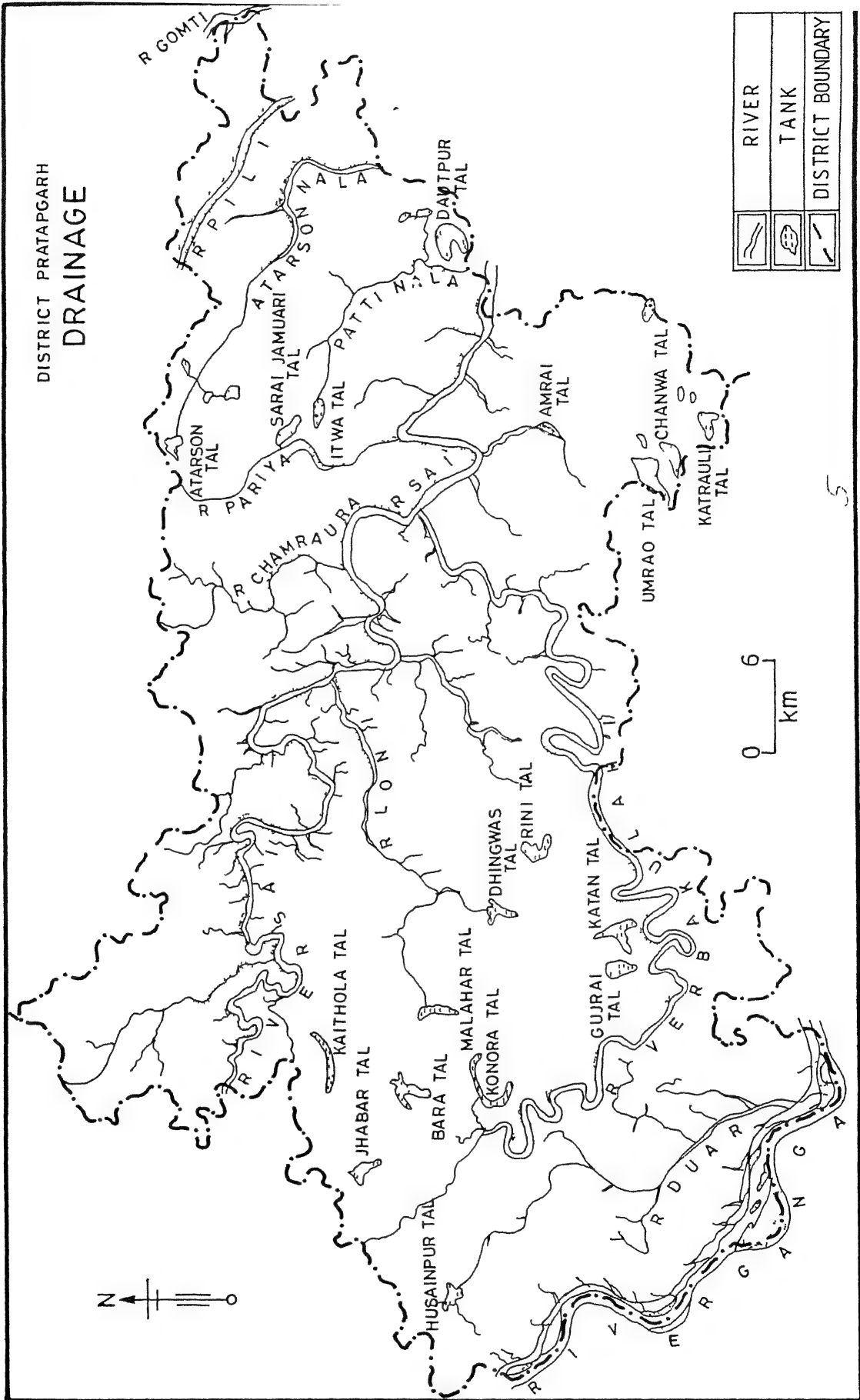


Fig 25

CLIMATIC CHARACTERISTICS

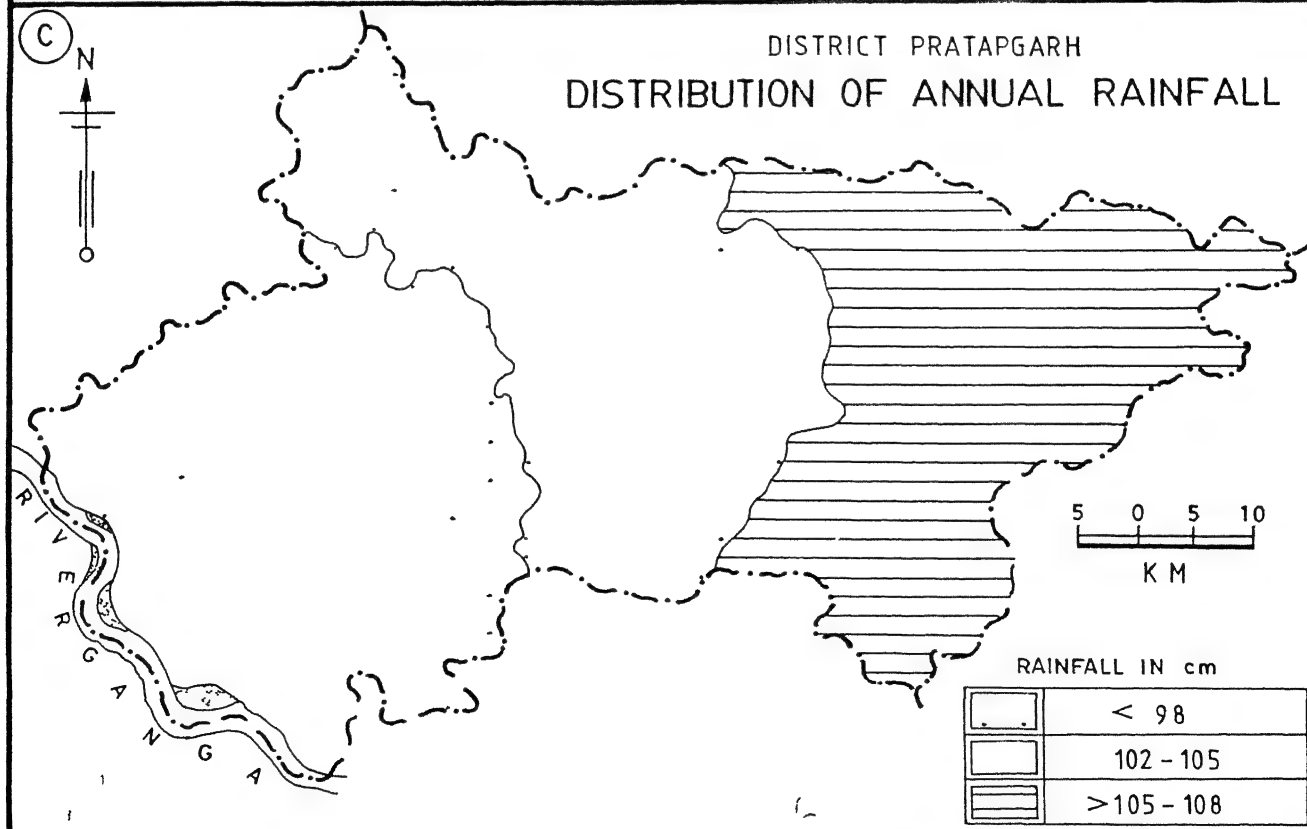
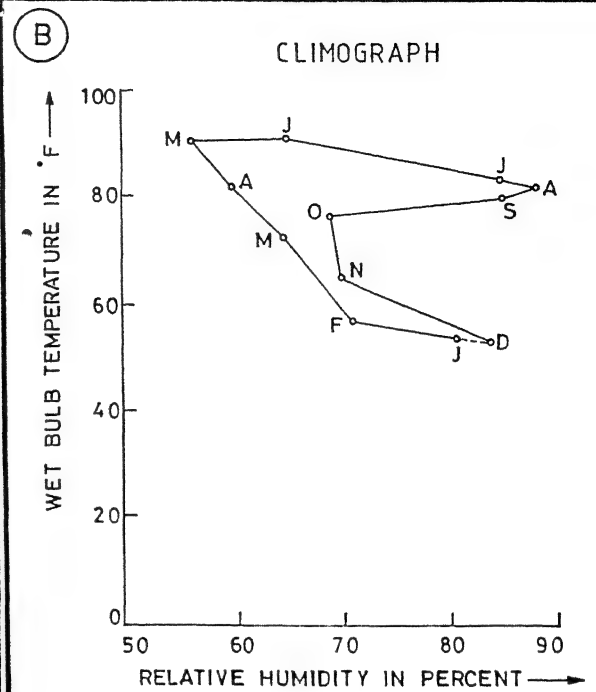
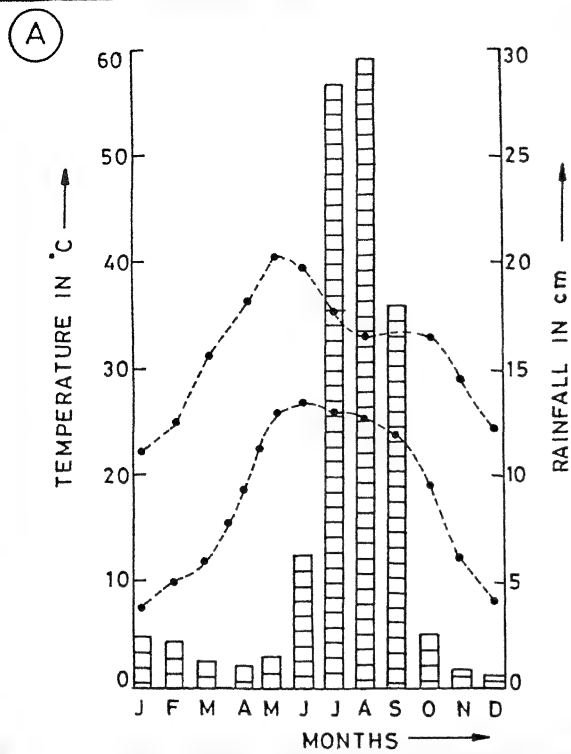


Fig 2.6

प्राकृतिक संसाधन

खनिज सम्पत्ति - खनिजों की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र महत्वहीन है । यहाँ की मिट्टी में चिकनी मिट्टी, रेत तथा ककड की जो मात्रा उपलब्ध है वह खनिज की गुणवत्ता की दृष्टि से निम्न कोटि की है । अतः आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है । चिकनी मिट्टी का यद्यपि यहाँ पर्याप्त भण्डार है परन्तु इसका उपयोग मिट्टी के बर्तन, इमारती ईंटों तथा छाजन के लिये खपड़ों के निर्माण तक सीमित है । रेह, जो सोडियम कारबोनेट व सल्फेट के साथ आंशिक मात्रा में कैल्शियम व मैग्नेशियम लवणों का मिश्रण होता है, इस क्षेत्र में व्यापक रूप से उपलब्ध है । इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिये किया जाता है । बागर क्षेत्र में मिट्टी में स्थान स्थान पर चूने की पर्याप्त मात्रा तथा अधोस्तरीय जल के उच्च स्तर के कारण मिट्टी की निचली तहों पर ककड बहुलता से पाया जाता है ।

वनस्पति अध्ययन क्षेत्र जंगल व वन के वितरण की दृष्टि से महत्वहीन है क्योंकि समस्त क्षेत्रफल के 0 । प्रतिशत भाग पर नैसर्गिक वनों का विस्तार है । ये वन मुख्यतः नदियों के कटे फटे भूभागों में फैले हुये हैं । इनमें विभिन्न प्रकार के मानसूनी वृक्ष पाये जाते हैं । विगत कुछ वर्षों में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वृक्षों को लगाने के साथ साथ वनों की सुरक्षा के लिये सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है ।

मिट्टी कृषि प्रधान क्षेत्र में उपयोगिता की दृष्टि से मिट्टी का विशेष महत्व है । जनपद की अधिकांश मिट्टी क्षारीय है जिसका पी० एच० मान 7 से अधिक है । रचना के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है । प्रथम प्रकार की मिट्टी चिकनी मटियार है जो कुण्डा, कालाकाकर, बाबागंज, विहार, रामपुर, लक्ष्मणपुर, मान्धाता, सदर, गौरा तथा शिवगढ़ में पाई जाती है । यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है । द्वितीय प्रकार की मिट्टी बालू व उसके मिश्रण से बनी दुमट मिट्टी है जो सागीपुर, स० चन्द्रिका तथा आसपुर देवसरा में मिलती है । प्रथम प्रकार की मिट्टी में आर्द्रता बनाये रखने की क्षमता अधिक होती है । जबकि बालू मिश्रित दुमट में आर्द्रता बनाये रखने की क्षमता नहीं होती है । कण रचना तथा

उनके तत्वों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी को पुन पाच भागों में विभक्त किया गया है (चित्र 2 3) -

- 1 बलुई दुमट
- 2 चिकनी दुमट
- 3 बादामी दुमट
- 4 भूरी तलहटी चिकनी दुमट
- 5 भूरी बादामी चिकनी बलुई दुमट

बालू प्रधान क्षेत्र में चिकनी मिट्टी के हल्के मिश्रण से युक्त बादामी रंग की मिट्टी की प्रधानता होती है । इसमें मिश्रित बारीक कणों में बालू का अंश 30 से 60 प्रतिशत तक तथा चिकनी मिट्टी में 10 से 20 प्रतिशत के बीच होता है । हल्की भूरी चिकनी दुमट का क्षेत्र मुख्यत जनपद के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है जो धान की खेती का सर्वोत्तम क्षेत्र है । हल्की बादामी बलुई दुमट मिट्टी गोमती नदी के तटवर्ती भागों में पाई जाती है । गोमती नदी के दक्षिण में सीमित क्षेत्र में बलुई चिकनी दुमट मिट्टी का मिश्रण है । उत्तरी पश्चिमी सीमा के पास सीमित क्षेत्र में बारीक बलुई दुमट मिट्टी की प्रधानता है ।

मानव ससाधन वितरण प्रतिरूप

जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप और आर्थिक ससाधनों के वितरण प्रतिरूप में गहरा सम्बन्ध है । अतः जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण आवश्यक है । यदि हम बिन्दु विधि से प्रदर्शित मानचित्र (संख्या 2 7) पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन क्षेत्र अत्यन्त सघन बसा हुआ है । किन्तु जनसंख्या के घनत्व के प्रतिरूप से जनसंख्या के वितरण की विषमता स्पष्ट प्रतीत होती है । जनसंख्या का घनत्व क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का अनुपात है ।

प्रतापगढ़ जनपद की जनसंख्या का घनत्व 1901 तथा 1981 के बीच 248 मनुष्य प्रति वर्ग

सारिणी सङ्ख्या 2 । अध्ययन क्षेत्र का तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व
(व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी०)

वर्ष	प्रतापगढ जनपद	उत्तर प्रदेश	भारत
1901	248	165	72
1951	297	215	111
1961	341	251	134
1971	381	300	173
1981	484	377	216
1991	595	472	267

स्रोत भारतीय जनगणना, 1951-91

सारिणी सं० 22 जनपद के विकास खण्ड स्तर पर कुल जनसंख्या का घनत्व
(मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी०)

विकास खण्ड का नाम	1961	1971	1981
सदर	453	844	848
नक्षमणपुर	357	395	497
मानधाता	377	434	573
सडवा चन्द्रिका	355	391	475
सागीपुर	313	343	423
कुन्डा	365	452	520
कालाकाकर	288	328	486
बाबागज	297	330	427
बिहार	320	367	478
रामपुरखास	298	326	422
पट्टी	278	320	456
गौरा	327	377	458
शिवगढ	246	388	512
मगरौरा	358	403	422
आसपुरदेवसरा	291	332	484

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961-81

कि० मी० से बढ़कर 484 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० हो गया है । इसकी तुलना में प्रदेश एवं राष्ट्र की जनसंख्या का घनत्व काफी कम है । उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व विगत 80 वर्षों में 165 से बढ़कर 377 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० तथा राष्ट्र की जनसंख्या का घनत्व 72 से बढ़कर 216 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० हो गया है (सारणी 2 1) । अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहाँ कि प्रति वर्ग कि० मी० उपलब्ध भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है । जनसंख्या के घनत्व का विकास खण्ड स्तर पर जो परिवर्तन हुआ है उसे सारणी संख्या 2 2 तथा 2 3 से देखा जा सकता है । सारणी संख्या 2 2 कुल जनसंख्या के घनत्व (ग्रामीण एवं नगरीय) का प्रदर्शन करती है जबकि सारणी संख्या 2 3 केवल ग्रामीण जनसंख्या के घनत्व को प्रदर्शित करती है। इन दो सारणियों से स्पष्ट है कि वे विकास खण्ड जहाँ कि नगरीय अधिवास पाये जाते हैं (उदाहरण के लिये सदर, कुण्डा, कालाकाकर, सडवा चन्द्रिका तथा पट्टी) उनकी जनसंख्या का घनत्व अधिक है । किन्तु यदि केवल ग्रामीण जनसंख्या के घनत्व पर विचार किया जाय तो मानधाता, शिवगढ़ तथा सदर विकास खण्ड अपेक्षाकृत सघन रूप से बसे हुये हैं । विकास खण्ड स्तर पर 1961 और 1981 के बीच जनसंख्या के घनत्व के वितरण का प्रदर्शन किया गया है (चित्रसंख्या 2 8) । वर्ष 1981 के आकड़ों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है

- 1 अत्यधिक घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत सदर विकास खण्ड आता है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 848 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० है ।
- 2 अधिक घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत मानधाता विकास खण्ड आता है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 573 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० है ।
- 3 मध्यम घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत कुण्डा (520) तथा शिवगढ़ (512) विकास खण्ड आते हैं ।
- 4 निम्न घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत लक्ष्मणपुर (497) कालाकाकर

**सारिणी 2.3 जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व
(मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी०)**

विकासखण्ड का नाम	1961	1971	1981
सदर	434	482	539
लक्ष्मणपुर	357	395	497
मानधाता	377	434	573
सडवा चन्द्रिका	355	391	455
सागीपुर	313	343	423
कुन्डा	365	452	480
कालाकार	288	328	452
बाबागज	297	330	427
बिहार	320	367	478
रामपुरखास	298	326	422
पट्टी	278	320	428
गौरा	327	377	458
शिवगढ	246	388	512
मगरौरा	358	403	422
आसपुर देवसरा	291	332	484

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1961-81

(486), आसपुर देवसरा (484), बिहार (478), गौरा (456), बाबागज (427), तथा सागीपुर (423) विकास खण्ड है ।

5 निम्नतम घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत रामपुर खास (422) तथा मगरोरा (422) विकास खण्ड है । इस निम्न घनत्व का मुख्य कारण अनुपजाऊ भूमि की अधिकता है ।

ग्रामीण जनसंख्या के घनत्व के वितरण के आधार पर (मानचित्र 2 8) अध्ययन क्षेत्र में चार भाग देखे जा सकते हैं -

1 अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र - यह वह विकास खण्ड है जहाँ जनसंख्या घनत्व 555 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० से अधिक है । इसके अन्तर्गत मानधाता विकासखण्ड (573 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी०) आता है ।

2 अधिक घनत्व वाले क्षेत्र - यह वे विकासखण्ड है जहाँ जनसंख्या घनत्व 498 से 554 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० है । इसके अन्तर्गत सदर विकासखण्ड (539) तथा शिवगढ विकासखण्ड (512) है ।

3 मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र - यह वह विकासखण्ड है जहाँ जनसंख्या घनत्व 423से 497 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० है । इसके अन्तर्गत कालाकाकर (452), बाबागज (427), बिहार (478), लक्ष्मणपुर (497), गौरा (458), पट्टी (428), आसपुर देवसरा (484), सो चन्द्रिका (455) तथा सागीपुर (423) है ।

4 निम्न घनत्व वाले क्षेत्र - इस श्रेणी में मगरोरा तथा रामपुर खास विकास खण्ड है जिनकी जनसंख्या का घनत्व 422 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० है । जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है यह वे क्षेत्र है जहाँ ऊसर युक्त अनुपजाऊ भूमि अधिक है ।

बढ़ती हुई जनसंख्या तथा जनसंख्या के घनत्व का मानव अधिवास संरचना पर पर्याप्त प्रभाव

पडा है जिसका उल्लेख अगले अध्याय में किया गया है ।

लिंग अनुपात - जनसंख्या के विश्लेषण में स्त्री - पुरुष अनुपात का विशेष महत्व है क्योंकि इससे जनसंख्या के महत्वपूर्ण गुण का उद्घाटन होता है । स्त्री - पुरुष का अनुपात लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है जो कि प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है । यह उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र में कुल जनसंख्या तथा ग्रामीण जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है । यह अनुपात उत्तर प्रदेश एवं भारत की तुलना में अधिक है । अध्ययन क्षेत्र में इसका वितरण अत्यन्त असंतुलित एवं विषम है । यद्यपि कि वर्ष 1901 - 81 में असंतुलन में कमी आयी है । वर्ष 1901 में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1045 थी जबकि वर्ष 1981 में यह संख्या घट कर 1016 हो गयी है (सारणी संख्या 2 4) । यदि हम कुल जनसंख्या के लिंग अनुपात के वितरण को विकासखण्ड स्तर पर देखें (परिशिष्ट) तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि में सदर, कालाकाकर, बिहार, आसपुर देवसरा तथा कुण्डा को छोड़ कर शेष अन्य विकासखण्डों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक रही है । यह तथ्य ग्रामीण जनसंख्या के लिंग अनुपात के विश्लेषण से भी स्पष्ट होता है । ये इस बात का द्योतक है कि अध्ययन क्षेत्र मूलतः आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ रोजगार के अवसर बहुत ही कम हैं तथा जोतों के असमान वितरण के कारण कृषि उत्पादन क्षमता बहुत कम है । फलस्वरूप पुरुषों का एक बहुत बड़ा समूह नगरों की ओर पलायन कर गया है । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण - नगरीय प्रवास का बहुत ही विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है । प्रवास की यह प्रवृत्ति नगरीय जनसंख्या के लिंग अनुपात के विश्लेषण से और अधिक स्पष्ट होती है । उदाहरण स्वरूप नगरीय जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 1901 में 900 थी किन्तु वर्ष 1981 में स्त्रियों की संख्या घट कर 856 हो गयी । ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आगमन के कारण नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि अधिकांश लोग सामाजिक व आर्थिक कारणों से नगरों में प्रवास करते समय अपने परिवार के साथ प्रवास नहीं कर पाते हैं । यही कारण है कि अध्ययन क्षेत्र की नगरीय जनसंख्या में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में

संरिणी सख्या 2 4 प्रतापगढ जनपद मे लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की सख्या)

वर्ष	ग्रामीण	नगरीय	जनपद
1901	1049	900	1045
1951	1044	873	1039
1961	1066	839	1062
1971	1022	847	1016
1981	1019	856	1016

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1951-81

बढ़ती जा रही है । डेविस किंग्सले (1951) का यह विचार कि भारतीय नगर पुरुष प्रधान है, अध्ययन क्षेत्र के लिये भी पूर्णतः सत्य है ।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिवेश मानव अधिवास की संरचना को पूर्णतया प्रभावित करता है । मानव अधिवास - संरचना का विश्लेषण अगले अध्याय में किया गया है ।

REFERENCES

1. Davis, K. (1951), The Population of India and Pakistan, Princeton . New Jersey
2. Nevill, H.R. (1904), Pratapgarh District Gazetteer, Allahabad : Government Press
3. Shafi, M. (1959), Land Utilization in Eastern Uttar Pradesh, Published Ph.D Thesis, Aligarh Muslim University, Aligarh

अध्याय 3

मानव अधिवास तंत्र

विगत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है । यह मानव अधिवास के उद्भव, विकास तथा वितरण को प्रभावित करता है । प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास तंत्र के इन्हीं पक्षों का विश्लेषण किया गया है ।

अधिवासों की उत्पत्ति

जैसा कि विगत अध्याय से स्पष्ट है, अध्ययन क्षेत्र गंगा-यमुना के मैदानी भाग का एक समतल धरातलीय एवं मुख्यतया बलुई दुमट मिट्टी वाला भाग है । तथा इस भाग में अनेक छोटी छोटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं । इन्हीं नदियों एवं झीलों के किनारे उपजाऊ मिट्टी वाले भूभाग पर अनेक अधिवासों का प्रादुर्भाव हुआ है ।¹ अनेक अन्तःसाक्ष्य एवं वहिसाक्ष्यों से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में अधिवासों का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । कनिंघम (1872), फहरेर (1867) तथा नेविल (1904) द्वारा प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि यहाँ पर हजारों वर्ष पूर्व भी मानव अधिवास विद्यमान थे । कई ऐसे अधिवास हैं जिनका इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । सराय नाहर, हडोर, राकी, अठेहा, मुस्तफाबाद, बेलखडी, बिहार, गोंडा, शकरदहा, मानिकपुर, कालाकाकर, करेटी, रामपुर, भदरी, अल्हापुर, देवीगंज, धारूपुर तथा अरोल आदि कुछ ऐसे अधिवास हैं (चित्र सख्या 3।) जो प्राचीनतम जनपुज के ऐतिहासिक उदाहरण हैं । ऐसा अनुमान है कि ये वे अधिवास हैं जो मुख्य रूप से बौद्ध - बिहार, स्तूप, मन्दिर अथवा किसी प्रमुख राजा या उनके आमात्य द्वारा निर्मित किला अथवा प्रशासनिक इकाई के केन्द्र रहे हैं । प्रारम्भ में नदियाँ ही मुख्य रूप से यातायात का साधन थीं । अतः उनका विकास भी नदियों के तट पर हुआ । अधिवास सम्बन्धी उत्पत्ति के एक अन्य सिद्धान्त के अनुसार अधिवासों की उत्पत्ति मुख्य रूप से उन भागों में हुई थी जो कि खाद्यान्न - बाहुल्य क्षेत्र थे (स्मेल्ल्स 1967) । बारहवीं से 17वीं शताब्दी के बीच जिन मानव अधिवासों का जन्म हुआ उनका उल्लेख जिला गजेटियर में किया गया है । गंगा नदी के किनारे कुण्डा तहसील में स्थित मानिकपुर कस्बा बारहवीं शताब्दी में एक ऐतिहासिक नगर था जो प्रादेशिक नियंत्रण केन्द्र रूप में हिन्दू तथा मुसलमान राजाओं द्वारा विकसित किया गया था । अनेक छोटे छोटे राजाओं एवं जमींदारों का क्षेत्र होने के कारण प्रतापगढ़ में कई महत्वपूर्ण अधिवास विकसित

सारिणी संख्या 3 । प्रतापगढ जनपद में जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण अधिवासों का प्रतिशत

जनसंख्या आकार	1901	1951	1961	1971	1981
0-499	73 4	64 4	59 4	54 7	44 8
500-999	19 5	25 0	26 5	27 3	28 8
1000-1999	6 0	8 7	11 4	14 2	20 6
2000-4999	1 1	1 9	2 7	3 8	5 6
5000-9999	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस बुक 1961, 1971, 1981

हुये । इनमें कालाकाकर, कैथौला, राजापुर, राकी तथा सुजाखर इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

अधिवासों का वास्तविक विकास आधुनिक काल में मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन काल में हुआ । क्योंकि वे समस्त केन्द्र जहाँ अंग्रेजों की छावनियाँ थी, प्रमुख अधिवास के रूप में स्थापित हुये। बेला प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ सिटी से लगभग 6 कि० मी० दूर पर स्थित है तथा जिला मुख्यालय का केन्द्र भी है, का विकास उस समय हुआ जब सन् 1858 में जिलों का पुनर्गठन किया गया । सड़क यातायात के विकसित होने से भी अधिवास विकसित हुये । सड़क यातायात का विकास मुख्य रूप से तीन चरणों में हुआ । सर्वप्रथम 1857 में प्रमुख केन्द्रों को सड़कों से जोड़ने के लिये ब्रिटिश शासन ने आदेश दिया और सन् 1858 में जब बेला प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के रूप में स्थापित हुआ तो इस स्थान को इलाहाबाद, फैजाबाद, रायबरेली, गौरीगंज, कटरा गुलाब सिंह तथा कालाकाकर से जोड़ दिया गया । इसके अतिरिक्त कई अन्य छोटे छोटे मार्ग भी रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिये निर्मित किये गये । इसमें गौरा तथा दाँदपुर रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली सड़कें मुख्य थी । सन् 1870 में 5472 कि० मी० लम्बी सड़क का निर्माण सम्पन्न हो चुका था । इनमें पक्की सड़कों की लम्बाई 100 8 कि० मी० थी । सन् 1904 तथा 1914 के बीच पश्चिम में राय बरेली तथा पूर्व में बादशाहपुर को जोड़ने वाली सड़कें पक्की हो चुकी थीं । किन्तु सड़कों का वास्तविक विकास स्वतंत्रता के पश्चात् हुआ । इन सड़कों के विकास के साथ अधिवास तन्त्रों का न केवल विकास हुआ, अपितु कई नये अधिवास बाजार अथवा सेवा केन्द्र के रूप में विकसित हुये । सड़क की भाँति ही रेलमार्ग के विकास से भी अधिवास तंत्र प्रभावित हुआ । यद्यपि कि अध्ययन क्षेत्र का रेलमार्ग मुख्य रूप से स्वतंत्रता से पूर्व का ही है, किन्तु अध्ययन क्षेत्र के वाह्य सम्पर्क बढ़ जाने के कारण न केवल यातायात की सुविधा में वृद्धि हुई, अपितु विभिन्न वस्तुओं के आयात, निर्यात को बल प्राप्त हुआ जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त स्कूल, कालेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाओं के फलस्वरूप भी अनेक बाजार तथा सेवा केन्द्र उभरे । प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को तीन तहसीलों तथा 15 विकास

खण्डों की इकाइयों में बाटने के कारण कई महत्वपूर्ण अधिवास विकसित हुये । इनमें कुन्डा, पट्टी, प्रतापगढ़ और लालगंज मुख्य हैं ।

अधिवासों के उद्भव एवं विकास के सम्बन्ध में मिश्रा एवं मिश्रा (1987) ने एक मॉडल विकसित किया (चित्र संख्या 3 2) है । इस मॉडल के अनुसार प्रारम्भ में मानव अधिवास का विकास एक ग्राम के रूप में होता है । गांव की आवश्यकता बढ़ने पर कुछ सेवाएं बढ़ जाती हैं जिससे गांव, बाजार अथवा कस्बे के रूप में विकसित हो जाता है । यातायात सुविधाओं एवं उच्च स्तर की सेवाओं के बढ़ने के साथ साथ यह कस्बे नगर का रूप धारण कर लेते हैं । विकास के इस प्रक्रम को तीन कालों - पूर्व उपनिवेश काल (सत्रहवीं शताब्दी के पूर्व का समय), उपनिवेश काल (सत्रहवीं शताब्दी से 1947 तक का समय) तथा स्वातंत्र्योत्तर काल (1947 के पश्चात् का काल) में विभक्त किया गया है ।

पूर्व उपनिवेश काल में मुख्य रूप से कुछ विशेष अभिजात्य आवास, किला, धार्मिक स्थल, प्रशासनिक केन्द्र, हाट अथवा बाजार के रूप में अधिवासों का विकास हुआ तथा पगडंडी, बैलगाड़ी एवं केवल कुछ कच्चे मार्ग, सम्पर्क का कार्य करते थे । औपनिवेशिक काल में सेवा संरचना तथा यातायात के साधनों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ तथा प्रशासनिक, वाणिज्यिक एवं यातायात सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि के कारण अधिवासों का विकास हुआ । कच्चे मार्गों के अतिरिक्त पक्की सड़कें तथा रेलवे लाइनें भी बिछायी गयीं । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नियोजित एवं अनियोजित सेवाओं में वृद्धि हुई तथा यातायात साधनों में और अधिक विकास हुआ, जिससे अधिवासों के आन्तरिक एवं बाह्य संरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़ा । अधिवास विकास का यह मॉडल प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में भी लागू होता है ।

अधिवास संरचना

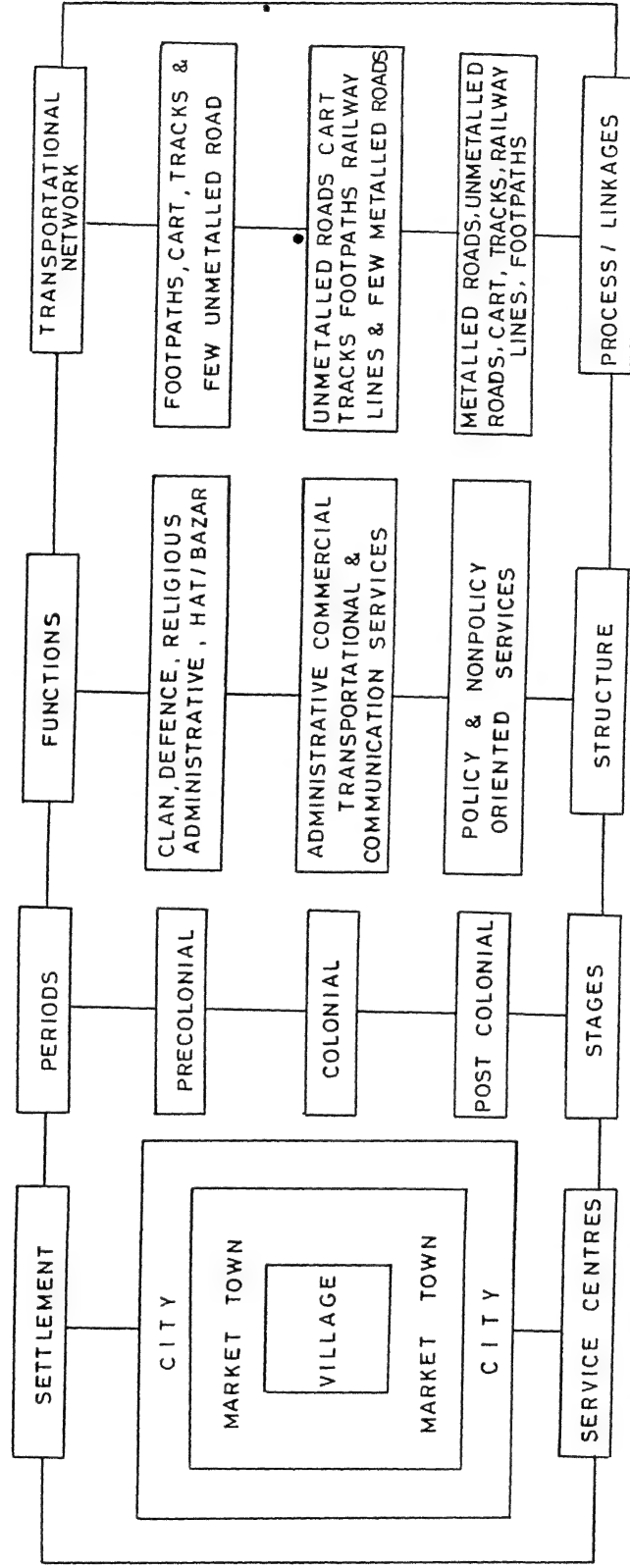
ग्रामीण अधिवास - जैसा कि सारिणी संख्या 3 1 तथा 3 2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 2185 ग्रामीण अधिवास हैं जिसमें से 978 (44.8 प्रतिशत) अधिवास ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 500 से कम है । 638 (28.8 प्रतिशत) अधिवास 500 - 1000 आबादी के

सारिणी संख्या 3.2 . प्रतापगढ जनपद में जनसंख्या वर्ग के अनुसार ग्रामीण अधिवासों में वृद्धि

जनसंख्या आकार	1901	1951	1961	1971	1981
0-499	1591	1402	1303	1201	978
	-	(-11 9)	(-7 1)	(-7 8)	(-18 6)
500-999	420	546	581	600	638
	-	(30 2)	(6 4)	(3 3)	(6 3)
1000-1999	132	195	251	312	440
	-	(47 7)	(28 7)	(24 3)	(41 0)
2000-4999	24	45	60	82	124
	-	(87 5)	(33 3)	36 7	(51 2)
5000 से अधिक	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
जनपद का योग	2167	2188	2195	2195	2185

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1901 1951,1961,1971,1981

EVOLUTIONARY MODEL OF SERVICE CENTRES



SOURCE : MISHRA H N et al EVOLUTIONARY MODEL OF SERVICE CENTRES IN SLOW GROWING ECONOMY .
 IN MISRA H N (ed) (1987) RURAL GEOGRAPHY , NEW DELHI HERITAGE PUBLISHERS

Fig 3.2

बीच, 440 (20.6 प्रतिशत) अधिवास 1000 - 2000 की आबादी वाले तथा 124 (5.6 प्रतिशत) अधिवास 2000 से 5000 आबादी वाले हैं तथा पाँच अधिवास (0.2 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। इन दोनों सारिणियों से यह स्पष्ट होता है कि 500 से कम जनसंख्या वाले अधिवासों की संख्या में पर्याप्त ह्रास हुआ है। इनकी संख्या सन् 1901 में 1591, 1951 में 1402, 1961 में 1303, तथा 1971 में 1201 थी। 1981 में ऐसे अधिवासों की संख्या केवल 978 ही रह गयी। विगत दो दशकों (1971 - 81) में इस प्रकार के अधिवासों की संख्या में 18.6 प्रतिशत का ह्रास हुआ। किन्तु 500 - 1000 की आबादी वाले ग्रामीण अधिवासों की संख्या में वृद्धि हुई है। विगत आठ दशकों (1901 - 81) में इस वर्ग के अधिवासों की संख्या 420 से बढ़कर 638 हो गई। इस प्रकार इस वर्ग में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक इसी प्रकार 1000 - 2000 एवं 2000 - 5000 की आबादी वाले ग्रामीण अधिवासों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इनकी संख्या सन् 1901 में क्रमशः 132 तथा 24 थी जबकि 1981 में यह बढ़कर 440 तथा 124 हो गयी। इस प्रकार विगत दो दशकों में 1000 - 2000 की आबादी वाले अधिवासों में 41.0 प्रतिशत तथा 2000 - 5000 की आबादी वाले अधिवासों में 51.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छोटे अधिवास बड़े अधिवासों के वर्ग में सम्मिलित हो रहे हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सन् 1901 - 71 के मध्य 5000 की आबादी वाले अधिवासों का अभाव था किन्तु 1981 में 5 अधिवास इस श्रेणी में भी आ गये। विगत दो दशकों में गाँवों की संख्या में जो ह्रास हुआ है उसका मुख्य कारण नगरीकरण है। कुछ ग्राम उदाहरण के लिये कुन्डा, पट्टी, अन्तू, मानिकपुर, बेला प्रतापगढ़ तथा कटरा मेदनीगज कस्बा अथवा नगर की श्रेणी में आ गये हैं।

उत्तर प्रदेश तथा प्रतापगढ़ जनपद में गाँवों की संख्या तथा उनमें निवास करने वाली जनसंख्या का तुलनात्मक प्रारूप सारिणी संख्या 3.3 में प्रस्तुत किया गया है। इस सारिणी से स्पष्ट है कि राज्य एवं अध्ययन क्षेत्र में लगभग पूर्ण समानता है। यह भी स्पष्ट है कि जनसंख्या का अधिकांश भाग 500 से 1000 तथा 1000 - 2000 के आबादी वाले अधिवासों में है।

सारणी संख्या 3.3 जनसंख्या वर्ष के अनुसार गाँवों की संख्या एवं उनमें निवास करने वालों की जनसंख्या

राज्य	वर्ष	0	500	500	999	1,000	1,999	2,000	4,999	5,000	9,999	10,000 से अधिक	
		3 ^x	4 ⁰	5 ^x	6 ⁰	7 ^x	8 ⁰	9 ^x	10 ⁰	11 ^x	12 ⁰	13 ^x	14 ⁰
उत्तर प्रदेश	1901	75 1	37 2	17 1	29 9	6 3	21 8	1 5	10 4	0 0	0 7	0 0	0 0
	1921	76 2	40 3	16 6	30 0	6 0	21 2	1 2	8 1	0 0	0 3	0 0	0 1
	1951	67 5	30 0	20 8	29 8	9 2	25 3	2 4	13 5	0 1	1 4	0 0	0 0
	1961	61 8	24 5	23 1	28 5	11 4	26 9	3 4	16 6	0 3	3 1	0 0	0 4
	1971	55 5	19 2	25 1	26 5	14 3	29 0	4 8	20 0	0 5	4 4	0 0	0 9
	1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतापगढ़ जनपद	1901	73 4	41 0	19 5	32 2	6 2	20 0	1	6 8	0 0	-	-	-
	1951	64 4	31 5	25 0	35 2	8 7	24 3	1 9	9 0	0 0	-	-	-
	1961	59 4	26 7	26 5	33 0	11 4	26 7	2 7	13 6	0 0	-	-	-
	1971	54 7	23 5	27 3	29 9	14 2	30 0	3 8	16 6	0 1	-	-	-
	1981	44 8	-	28 8	-	20 1	-	5 1	-	0 2	-	-	-

स्रोत उत्तर प्रदेश जनगणना 1961 - 81
जनपद जनगणना पुस्तिका 1961 - 81
x गाँवों का प्रतिशत, 0 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत

ग्रामीण अधिवासों की बढ़ती हुई आबादी इस बात का द्योतक है कि ये अधिवास विविध प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। उदाहरण के लिये कृषि योग्य भूमि पर अधिक दबाव पड़ रहा है। परती एवं बजर भूमि जो वातावरण के सतुलन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, घट रही है। साथ ही साथ जल, आवास एवं पर्यावरण समस्याएँ भी बढ़ रही हैं।

ग्रामीण अधिवास वितरण प्रतिरूप - धरातल पर अधिवासों के वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी क्षेत्र के नियोजन के लिये अधिवासों के वितरण प्रतिरूप को समझना परम आवश्यक है। प्रारम्भ में जब मात्रात्मक विधियों का प्रयोग भूगोल में नहीं होता था, उस समय केवल मानचित्र प्रेक्षण विधि द्वारा गुणात्मक शैली में वितरण को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था। मात्रात्मक विधि के प्रयोग के साथ ही साथ वितरण को स्पष्ट करने के लिये "समीपस्थ पड़ोसी तकनीक" का प्रयोग सर्वप्रथम एल० जे० किंग (1962) ने किया था। तत्पश्चात् इस विधि का प्रयोग अनेक भारतीय भूगोल विद्वानों ने भी किया है। इसके लिये जिस सूत्र का प्रयोग किंग महोदय ने किया, वह इस प्रकार है -

$$R_n = \frac{d_0}{d_c}$$

R_n = पड़ोसी तकनीक का अनुपात

d_0 = धरातल पर पड़ोसी दूरी का औसत

d_c = अपेक्षित दूरी का औसत

किन्तु यहाँ पर मिश्रा (1984) द्वारा प्रयुक्त अधोलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है --

$$R_n = 2\bar{D}\sqrt{\frac{N}{A}}$$

R_n = पड़ोसी विधि का अनुपात

\bar{D} = विभिन्न अधिवासों के बीच की औसत दूरी

N = अधिवासों की संख्या

A = क्षेत्रफल

इस विधि के अन्तर्गत यदि पड़ोसी विधि का अनुपात 1 से कम है तो उस प्रतिरूप को केन्द्रित प्रतिरूप कहा जाता है। यदि अनुपात 1 हो तो उसे रैन्डम कहा जायगा तथा यदि 1 से अधिक हो किन्तु 2.15 के बराबर या कम हो, तो उसे समान प्रकार का वितरण प्रतिरूप माना जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में समीपस्थ पड़ोसी तकनीक के आधार पर परिकलन के लिये तीन न्यादर्श क्षेत्रों का चुनाव किया गया। यह न्यादर्श क्षेत्र तीनों तहसीलों के मुख्यालय के चारों ओर 7 कि० मी० त्रिज्या द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रत्येक न्यादर्श क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग कि० मी० (चित्र संख्या 3.3) है। तीनों तहसीलों के तीन न्यादर्श क्षेत्र से प्राप्त परिणामों को सारिणी (संख्या 3.4) में प्रस्तुत किया गया है। इस सारिणी से स्पष्ट है कि तीनों तहसीलों में 1000 से 5000 आबादी वाले अधिवासों का वितरण प्रतिरूप समान है। ठीक इसी प्रकार 500 - 1000 आबादी वाले अधिवासों का वितरण प्रतिरूप कुन्डा एवं पट्टी में समान प्रकार का है किन्तु प्रतापगढ़ में केन्द्रित प्रकार का है। 200 - 500 आबादी वाले अधिवासों का वितरण कुन्डा एवं पट्टी में "रैन्डम" प्रकार का है किन्तु प्रतापगढ़ में समान प्रकार का दृष्टिगोचर होता है। 200 से कम आबादी वाले अधिवासों का वितरण कुन्डा एवं प्रतापगढ़ में रैन्डम प्रकार का है जबकि पट्टी में समान प्रकार का दृष्टिगोचर होता है। समीपस्थ पड़ोसी तकनीकी विधि से जो परिणाम प्राप्त हुये हैं, किंचित् संदिग्ध हैं। अतः इनका पुनः परीक्षण किया गया है। रैन्डम प्रतिरूप के परीक्षण के लिए अधोलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है (स्मिथ, 1977)।

$$Sde = \frac{0.26132}{\sqrt{N(N/A)}}$$

Sde = प्रमाणिक त्रुटि

$N =$ अधिवास सख्या

$A =$ क्षेत्रफल

इस सूत्र के प्रयोग से प्राप्त परिणाम सारिणी 3 4 में प्रस्तुत किया गया है । इससे स्पष्ट है कि अधिकांश परिणाम विश्वसनीय हैं और उनकी प्रमाणिकता 95 प्रतिशत तक है ।

नगरीय अधिवासों की संरचना एवं वितरण प्रणाली

अध्ययन क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी तथा अन्य शासकों के प्रभाव के चिन्ह आज भी देखने को मिलते हैं (डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1904) । यहाँ अनेक ऐसे अधिवास पाये जाते हैं जो अपनी ऐतिहासिकता का सकेत देते हैं । इनमें मानिकपुर सबसे प्राचीन नगरीय अधिवास था । किन्तु अन्य कस्बों का उद्भव एवं विकास आधुनिक है । वास्तविकता यह है कि अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण की प्रवृत्ति ब्रिटिश काल की देन है । वर्तमान में सन् 1991 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल 7 नगरीय अधिवास हैं । इन अधिवासों को जनसंख्या वर्ग के अनुसार वितरण सारिणी सख्या 3 5 में प्रदर्शित किया गया है । यदि हम सन् 1901-1991 के बीच नगरीय अधिवास की संख्या (सारिणी सख्या 3 6) पर विचार करें तो स्पष्ट होगा कि सन् 1961 में एकाएक इनकी संख्या 4 से घट कर एक हो गयी है । जो तीन अधिवास प्रभावित हुये, वे मानिकपुर, कटरा मेदनीगज तथा कस्बा प्रतापगढ़ थे । इसका मुख्य कारण यह था कि 1961 की जनगणना में नगरीय अधिवासों की परिभाषा में आमूल परिवर्तन हो गया । सन् 1901-51 तक वे समस्त अधिवास जो प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अथवा वाणिज्य की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझे जाते थे, उन्हें नगरीय अधिवासों का दर्जा दे दिया गया था ।

सन् 1961 में नगरीय अधिवासों की परिभाषा को बहुत वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया । इस परिभाषा के अनुसार टाऊन एरिया, नोटीफाइड एरिया, कैंटूनमेन्ट एरिया, म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को नगरीय अधिवास के अन्तर्गत रखा गया । इसके अतिरिक्त वे अधिवास भी जिनकी आबादी 5000 थी, तथा जहाँ की जनसंख्या का घनत्व 386 मनुष्य प्रति वर्ग कि०

सं. सरिणी सख्या 3 4 प्रतापगढ़ जनपद में अधिवासों का विवरण प्रसार

अधिवास आकार	कुन्डा	पट्टी	प्रतापगढ़
0 - 200	0 99*	1 4*	1 0*
200 - 499	1 0*	1 1*	1 9*
500 - 999	1 4*	1 3*	0 8*
1000 - 4999	1 4*	1 2*	1 5

* 95% पर प्रमाणित

स्रोत समीपस्थ पडोसी तकनीक के आधार

**सारिणी सख्या 3 5 जनसख्या वर्ग के अनुसार प्रतापगढ जनपद में
नगरीय अधिवासों का वितरण प्रतिरूप**

वर्ग	आकार	नगरीय अधिवास
I	100,000 से अधिक	-
II	50,000 - 99,999	1
III	20,000 - 49,000	-
I	10,000 - 19,999	1
	05,000 - 09,999	5
	05,000 से कम	-

स्रोत जनगणना, 1991

सारणी सख्या 3 6 प्रतापगढ़ जनपद में नगरीय अधिवासों की सख्या

वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991
नगरीय अधिवासों की सख्या	04	04	04	04	04	04	01	01	07	07

स्रोत जिला जनगणना पुस्तिका 1951-91

मी० था और जहाँ की कुल आबादी का 75 प्रतिशत भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगा था, उसे भी नगरीय अधिवास का दर्जा दिया गया । इस नयी परिभाषा के कारण नगरीय अधिवास की संख्या सन् 1951-61 में 4 से घट कर केवल 1 रह गयी थी । यह परिभाषा सन् 1971 में भी मान्य थी और कुछ सशोधन के साथ यही परिभाषा सन् 1981 की जनगणना में भी मान्य रही । सन् 1981 की परिभाषा के अनुसार वे समस्त अधिवास जो टाऊन ऐरिया, नोटीफाइड ऐरिया, म्यूनिसिपल बोर्ड, कैंटूनमेन्ट अथवा म्यूनिसिपल कोर्पोरेशन हों अथवा वे समस्त अधिवास जिनकी कुल जनसंख्या 5 हजार या उससे अधिक हो और कुल पुरुष जनसंख्या का $\frac{3}{4}$ कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगा हो, एवं जनसंख्या का घनत्व 400 मनुष्य प्रति वर्ग कि० मी० हो, उसे नगरीय अधिवास माना गया है । कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिनकी आबादी 5 हजार से कम है, उन्हें "सेन्सस टाउन" माना गया है । इस प्रकार के नगर मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में पाये जाते हैं । एक अन्य परिवर्तन यह हुआ कि बागाती, बागबानी, व मत्स्य पालन क्रियाओं को कृषि कार्यों के अन्तर्गत नहीं रखा गया । सन् 1981 में मानिकपुर, कटरामेदनीगंज, कस्बा प्रतापगढ़ पुनः नगरीय अधिवास की श्रेणी में आय गये । इसके अतिरिक्त कुन्डा, पट्टी तथा अन्तू भी पहली बार नगरीय अधिवास के रूप में उभर कर आये हैं । कुन्डा तथा पट्टी तहसील हेडक्वार्टर होने के कारण तथा अन्य विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं के कारण विकसित हो रहे हैं । अन्तू एक प्रमुख बाजार एवं रेलवे स्टेशन तथा ब्लाक हेडक्वार्टर की सुविधा के कारण तेजी से विकसित हो रहा है (चित्र संख्या 3 4 अ, ब, स, द) ।

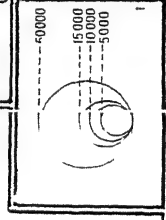
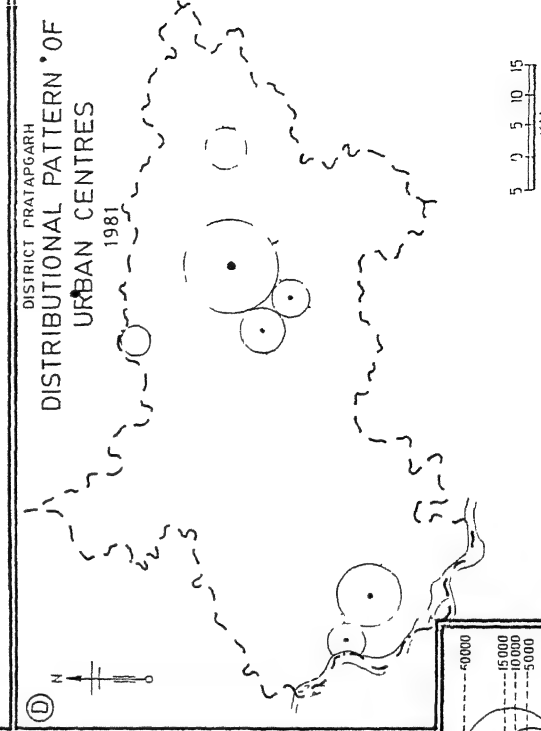
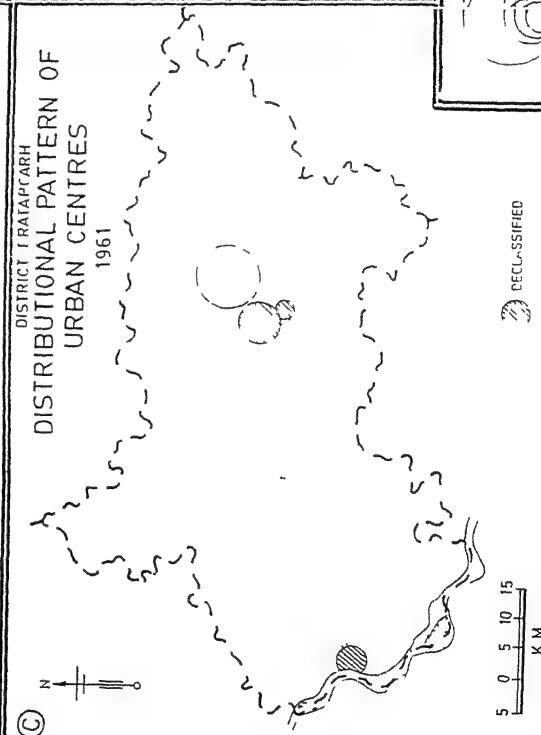
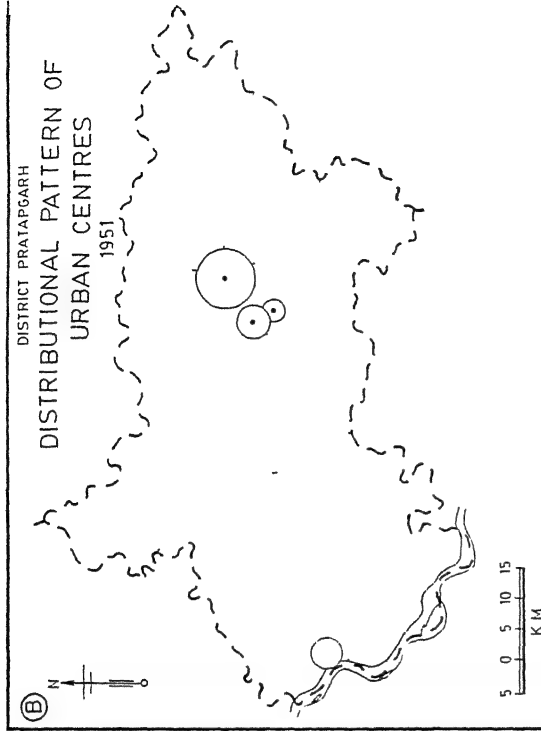
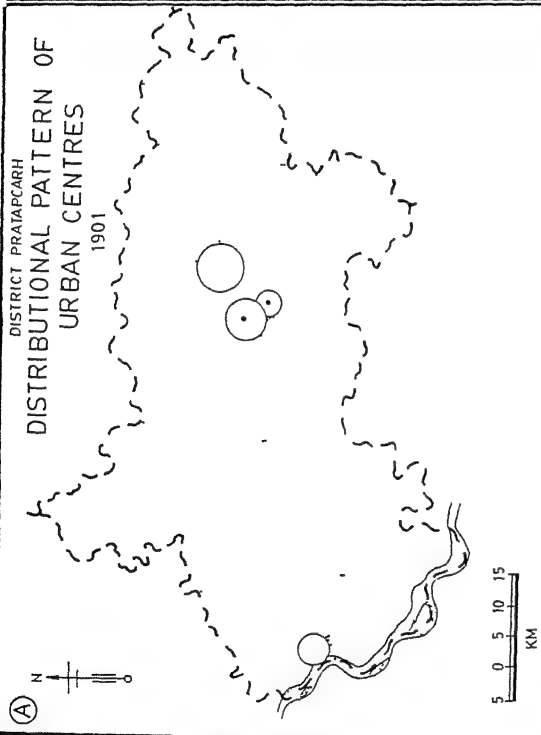
नगरीय अधिवास जनसंख्या गत्यात्मकता

जनसंख्या वृद्धि तथा लिंग अनुपात - अध्ययन क्षेत्र के सात नगरीय अधिवासों की जनसंख्या वृद्धि सारिणी संख्या 3 7 द्वारा प्रदर्शित की गयी है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि बेला प्रतापगढ़ न केवल जिला मुख्यालय है, अपितु जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अधिवास है । यह सन् 1921 से लगातार अध्ययन क्षेत्र के मुख्य नगरीय केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है । सन् 1951-81 के बीच इसकी जनसंख्या में तीन गुने से अधिक (234 प्रतिशत) वृद्धि

सारिणी सख्या 3 7 प्रतापगढ जनपद मे नगरीय जनसख्या एव लिंग अनुपात

क्रम सख्या	1951	1961	1971	1981	1991	लिंग अनुपात 1981 1991
1 बेला पगतापगढ	15,026	21,400	27,909	49,932	66,845	818 853
	-	(42 4)	(30 4)	(78 9)	(33 87)	
2 कुन्डा	-	03,112*	04,134 *	11,626	16,480	896 901
			(32 8)	(181 2)	(41 75)	
3 मानिकपुर	04 712	05,413 *	06,666 *	08,773	11,640	917 848
		(14 8)	(23 0)	(31 6)	(27 6)	
4 प्रतापगढ	04,596	04,711 *	04,714 *	06,565	09,265	895 849
		(2 5)	(0 1)	(39 9)	(41 06)	
5 पट्टी	-	02,546 *	02,663 *	05457	06,750	865 867
		-	(4 5) *	(104 5)	(23 69)	
6 अन्नू	-	03,724 *	04,524	04,489	06,343	912 943
		-	(21 4)	(-0 8)	(41 36)	
7 कटरा भेदिनीगज	02,109	01,570 *	02,026 *	04,067	05,575	958 909
	-	(25 3)	(29 0)	(100 7)	(34 55)	

* यह कस्बे सेन्सस के अनुसार टाऊन नहीं थे । कोष्ठक मे जनसख्या वृद्धि प्रतिशत दिखाया गया है ।
 स्रोत जिला जगगणना पुस्तिका 1951, 1961, 1971, 1981, 1991



हुई है । सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि 1971 - 81 में हुई । न केवल बेला प्रतापगढ़ में, अपितु अन्य नगरीय अधिवासों में भी इस दशक में जनसंख्या में वृद्धि हुई है । जिन कस्बों में 1981 - 91 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई उनमें कुंडा (41 75), अन्तू (41 36) तथा प्रतापगढ़ (41 06) हैं । कटरा (34 55), बेला प्रतापगढ़ (33 87), मानिकपुर (27 6) तथा पट्टी (23 69%) की वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है ।

यदि हम सन् 1981 के लिंग अनुपात (प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट होगा कि लिंग अनुपात तथा नगरों की जनसंख्या वृद्धि में सीधा सह सम्बन्ध है । जिनका लिंग अनुपात कम है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि अधिक तीव्रता से हुई है । इससे स्पष्ट है कि बेला प्रतापगढ़, कुंडा, पट्टी जैसे कस्बों में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास है । ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास के कारण ही इन कस्बों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है । प्रवासी जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात कम है क्योंकि अधिकांश लोग इन कस्बों में रोजगार का अवसर तलाश करने आते हैं । सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण ये लोग महिलाओं को अपने साथ नहीं ला पाते (मिश्रा, 1982) । यह भी उल्लेखनीय है कि इन नगरीय अधिवासों के विकास के मुख्य आर्थिक आधार टरशियरी प्रकार के कार्य हैं जिनमें वाणिज्य, व्यापार तथा सेवा सम्बन्धी इकाइयों का बाहुल्य है । ये इकाइयाँ मुख्य रूप से उत्पादक इकाई न होकर उपभोक्ता इकाइयाँ हैं (मिश्रा 1990) । इस प्रकार की इकाइयों की वृद्धि का मुख्य कारण अध्ययन क्षेत्र की पिछड़ी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन है (मिश्रा, 1990) ।

कोटि- आकार नियम तथा नगरीय अधिवास - जैसा कि पूर्व वर्णित है, कोटि आकार नियम एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है, जो अधिवास तंत्र विश्लेषण का महत्वपूर्ण, सैद्धान्तिक आकार प्रस्तुत करती है, सारिणी संख्या 3 8 में अध्ययन क्षेत्र के नगरीय अधिवासों का कोटि आकार नियम पर आधारित परिकल्पना ब्राउनिंग (1961) तथा मिश्रा (1984) द्वारा प्रतिपादित तथा प्रयोग किये गये नियम पर आधारित है । इस परिकल्पना से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के नगरीय अधिवासों में कोटि-आकार संकल्पना व्यावहारिक नहीं प्रतीत होती है । बेला प्रतापगढ़

**सारिणी सख्या 3 8 कोटि आकार नियम के अनुसार प्रतापगढ जनपद के नगरीय
अधिवासों की जनसंख्या व वास्तविकता से विचलन**

क्रम सं०	नगरीय सेवाकेन्द्र	कोटि का रेसिप्रोकल	वास्तविक जनसख्या अनुमानित जनसख्या	वास्तविक एव अनुमानित जन- सख्या के मध्य अन्तर	वास्तविक जनसख्या के आकार के अन्तर का प्रतिशत	अनुमानित जनसख्या के आकार के अन्तर का प्रतिशत	
1	बेला प्रतापगढ	1 00	49,932	35086	+14846	29 7	70 3
2	कुन्डा	0 500	11,626	17543	-5917	50 9	150 9
3	मानिकपुर	0 333	8,883	11695	-2922	33 3	133 3
4	प्रतापगढ सिटी	0 250		8772	-2207	33 6	133 6
5	पट्टी	0 200	5,457	7017	-1530	28 0	128 6
6	अन्तू	0 166	4,489	5848	-1361	30 3	130 3
7	कटरा मेदिनीगंज	0 142	4,067	5012	-945	23 2	123 2
	योग	2 591	90907	90973	29728	229	870 2
	औसत	37	12986 7	12996 1	4246 8	32 7	124 3

को छोड़ कर शेष अन्य 6 अधिवासों की जनसंख्या नियम पर आधारित जनसंख्या (अनुमानित जनसंख्या) से कम है । वास्तविक एवं अनुमानित जनसंख्या का अन्तर एवं उस पर आधारित प्रतिशत को सारिणी के वर्ग संख्या 7, 8 व 9 में देखा जा सकता है । बेला प्रतापगढ़ ही एक ऐसा नगर है जिसकी वास्तविक जनसंख्या अनुमानित जनसंख्या से अधिक है । स्पष्ट है कि यह क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक नगर है । यदि कोटि - आकार नियम के अनुसार नगरीय अधिवासों का वितरण होता तो बेला प्रतापगढ़ की वास्तविक तथा अनुमानित जनसंख्या का अन्तराल (14,846) अन्य 6 अधिवासों में वितरित होना चाहिये था । वास्तव में अध्ययन क्षेत्र में जेफरसन (1939) महोदय का प्राथमिक नगर सिद्धान्त अधिक तर्क संगत लगता है । क्योंकि यदि हम जनसंख्या क्रम पर आधारित प्रथम दो (बेला प्रतापगढ़ तथा कुन्डा) नगरों की तुलना करें तो उन दोनों के बीच 1:4 अनुपात है तथा प्रथम एवं अन्तिम (बेला प्रतापगढ़ व मानिकपुर) का अनुपात 1:123 है । स्पष्टतया अध्ययन क्षेत्र एक अविकसित क्षेत्र है, जहाँ पर एक सबसे बड़ा नगर होता है, शेष उससे छोटे होते हैं । इससे यह भी स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिवासों का सतुलित विकास अभी तक नहीं हो पाया है । सतुलित विकास के लिए उपयुक्त मानव अधिवास नीति की प्रासंगिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

REFERENCES

1. Browning, L H & Gibbs, J P (1961), Some Measures of Demographic and Spatial Relationships among cities, in Gibbs, J.P. (ed.) Urban Research Methods, New Delhi : East West Press
2. Cunningham, A (1872), Archaeological Survey of India, XI. (Simla)
3. Fuhrer, A (1969), The Monumental Antiquities and Inscriptions in the North-Western Provinces and Oudh, Varanasi.
4. Jefferson, M. (1939), The Law of Primate city, Geog Rev 29, PP 226-232
5. King, L.J. (1962), A Quantitative Expression of the Pattern of urban settlement in Selected Area of the United States, Tijdschrift Voor Economische Geografie, 53
6. Misra, H.N. (1986), Rae Bareilly, Sultanpur and Pratapgarh Districts, Uttar Pradesh, Northern India, in Hardoy, J.E. et al (ed.) Role of Small and Intermediate Urban Centres, London : Hodder and Stoughton
7. Misra, H.N (1984), Urban System of a Developing

- 8 Misra, H N. (1984) Human Settlement System and Regional Development in Developing Economy in Karnmeir, H D et al (edit) Equity with Growth : Planning Perspective for Small Towns in Developing Countries, Bangkok : AIT, 223-241
9. Misra, H.N and Misra, K K (1987), An Evolutionary Model of Service Centres' in a slow growing Economy, in Misra H N (Edit), Rural Geography, New Delhi Heritage Publishers
10. Misra, H N (1990), Tertiarisation in Indian Towns : A study of the Urban Growth Process in a Developing Region, I.G.U Regional Symposium on Asian-Pacific Countries, Beijing, China
- 11 Nevill, H.R (1904), Pratapgarh District Gazetteer, Allahabad : Government Press
- 12 Smith, D.M. (1980) Patterns in Human Geography, London . Penguin
13. Smailes, A.W (1967), The Geography of Towns, London : Hutchinson

अध्याय 4

सेवाकेन्द्रों का स्थानिक विश्लेषण

विगत अध्याय में अधिवास तंत्र के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है । प्रस्तुत अध्याय में अधिवासों में होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है । इसके लिए सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का चुनाव किया गया है और इन सेवा केन्द्रों में ही परिवर्तनों को देखने का प्रयत्न किया गया है ।

सेवा केन्द्र सकल्पना एवं चुनाव -

कोई भी अधिवास जब अपने आस पास के क्षेत्रों को एक या एक से अधिक सुविधाएँ अथवा सेवाएँ प्रदान करता है तो उसे सेवा केन्द्र कहा जाता है । इस प्रकार सेवा केन्द्र तथा सेवा केन्द्र से बाहर उसके आस पास रहने वाली जनसंख्या में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है । सेवा केन्द्र सम्बन्धी सकल्पना के प्रादुर्भाव का श्रेय कूले (1894), वान् थ्यूनेन (1826), गालपिन (1915) तथा क्रिस्टलर (1933) को है । क्रिस्टलर का योगदान इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सन् 1933 में केन्द्र - स्थल सिद्धान्त को प्रतिपादित कर सेवा केन्द्रों की सकल्पना को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया । अनेक अन्य पश्चिमी विद्वानों ने भी अपने शोध के द्वारा समय समय पर सेवा केन्द्रों से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है । इनमें जेफरसन (1939), डिकिसन (1932), ब्रेसी (1963), ब्रश (1953), स्मेल्स (1944), बी० जे० एल० बेरी (1958), फोल्के (1968) तथा मैफील्ड (1967) का विशेष योगदान है । कई भारतीय विद्वानों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं जिनका समीक्षात्मक विश्लेषण गुरुभाग सिंह (1973) तथा के० के० मिश्रा (1981) ने विस्तार पूर्वक किया है ।

सेवा केन्द्रों के चुनाव में विभिन्न प्रकार के आधारों तथा सूचकांकों का प्रयोग किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन में अधोलिखित सेवाओं पर विचार किया गया है

शैक्षिक सेवाएँ - प्राइमरी स्कूल, जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कालेज, डिग्री कालेज ।

2 चिकित्सा सम्बन्धी सेवाएँ - औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार नियोजन केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र ।

- 3 डाक एव संचार सम्बन्धी सेवाएँ - डाक घर एव तार घर ।
- 4 यातायात सेवाएँ - बस स्टेशन, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन ।
- 5 वाणिज्य सम्बन्धी सेवाएँ - साप्ताहिक अथवा दैनिक बाजार केन्द्र ।

उपरोक्त पाँच प्रकार की सुविधाओं में से यदि कोई भी चार सुविधाएँ उपलब्ध हैं तो उसे सेवा केन्द्र का दर्जा दिया गया है । इस प्रकार कुल 76 सेवा केन्द्र चुने गये हैं जिनमें 23 कुन्डा तहसील में, 26 प्रतापगढ़ तहसील में तथा 27 पट्टी तहसील में हैं । इन सेवा केन्द्रों में पायी जाने वाली विविध सुविधाओं को सारिणी सख्या 4 में प्रस्तुत किया गया है ।

सेवा केन्द्रों का सोपानक्रम

सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम अथवा सोपान क्रम निर्धारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्थानिक संगठन में सेवा केन्द्रों के महत्व का पता चलता है । बड़े सेवा केन्द्र का सेवा क्षेत्र बड़ा तथा छोटे सेवा केन्द्र का सेवा क्षेत्र छोटा होता है । सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम अथवा सोपानक्रम कई विधियों से ज्ञात किया जा सकता है । इनमें कोटि आकार विधि, यातायात अधिगम्यता पर आधारित केन्द्रियता तथा सेवा कार्यों के आधार पर निर्धारण की विधियाँ मुख्य हैं ।

सेवा केन्द्रों का कोटि - क्रम तब - ग्रामीण एव नगरीय सेवा केन्द्रों का सामूहिक तब विश्लेषण करने के लिए सेवा केन्द्रों को उनके जनसख्या क्रम के अनुसार लागू ग्राफ पर अंकित किया गया है । "य" अक्ष पर जनसख्या कोटिक्रम "र" अक्ष पर अधिवासों की जनसख्या दिखायी गयी है । इस प्रकार कुल चार रेखाचित्र (चित्र सख्या 4.1 तथा 4.2) प्रस्तुत किये गये हैं । यह रेखाचित्र अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों का जनसख्या के आधार पर तीन दशकों का (1961, 1971, 1981) पदानुक्रम प्रस्तुत करते हैं । इससे स्पष्ट है कि उच्च स्तर पर केवल एक सबसे बड़ा सेवा केन्द्र है और फिर एकाएक सेवाकेन्द्रों का आकार छोटा हो गया है । निम्न स्तर के कई सेवाकेन्द्र एक साथ पुजीभूत हो गये हैं । रेखा चित्र का आकार तीन

सारिणी सख्या 4 । प्रतापगढ जनपद के सेवाकेन्द्रों में उपलब्ध सेवाये (1961-81), अधिवास सूचकांक

क्रमांक	सेवाकेन्द्र	कार्यात्मक इकाई		कार्यात्मक प्रकार	
		1961	1981	1961	1981
01	बेला प्रतापगढ	16	143	6	16
02	कुण्डा	4	59	4	14
03	मानिकपुर	2	44	2	11
4	प्रतापगढ सिटी	1	15	1	8
05	कन्धई मधुपुर	-	4	-	4
06	पट्टी	5	35	5	13
07	ऐधा	-	4	5	4
08	अन्तू	2	13	2	9
09	कटरा मेदिनीगज	1	9	1	7
10	लरून	-	5	-	5
11	रेहुआ लालगज	3	10	3	7
12	अन्तसुन्ड	1	7	1	7
13	परियावा	2	8	2	7
14	सराय इनायत	1	8	1	7
15	स0 चन्द्रिका	4	8	2	8
16	राहाटीकर	1	6	1	4
17	सबलगढ	1	9	1	8
18	जामताली	4	8	3	7
19	डीहमेहदी	1	7	1	5
20	रामजीतपुर चिलबिला	4	5	3	5
21	धारूपुर	2	8	1	7

22	अजगरा	-	8	-	7
23	सग्रामगढ	5	10	3	9
24	दलीपपुर	4	8	4	7
25	ताला	-	7	-	6
26	भादरूँ	-	9	-	8
27	रामापुर	2	5	1	4
28	रामगज	2	11	1	11
29	उदईशाहपुर	1	11	1	10
30	मानधाता	3	11	3	11
31	मझिलगो	1	6	1	6
32	आसपुरदेवसरा	2	6	2	6
33	भदई	4	12	4	9
34	सरायभूपत	-	10	-	9
35	शीतलामऊ	1	8	1	7
36	आधारपुर	-	5	-	5
37	कालाकाकर	1	12	1	12
38	राजगढ	1	7	1	6
39	रामनगर भोजपुर	-	7	-	6
40	भूपियामऊ	2	7	2	6
41	सहरूआ	-	8	-	7
42	नारी	-	6	-	6
43	कोहडौर	1	8	1	8
44	डडहि याडीह	1	8	1	6
45	गडवारा	4	7	4	5
46	कजासरायगुलामी	1	7	1	6

47	नरई		7	-	5
48	सेफाबाद	1	7	1	6
49	मेहरूआ मलकिन	-	6	-	5
50	भदोही	-	5	-	5
51	अठेहा	1	5	1	5
52	बासी	-	7	-	7
53	पिचूरा	-	6	-	6
54	सदहा	-	5	-	4
55	भोजपुर	-	6	-	6
56	भगसेरा	-	9	-	8
57	पूरेगोलिया	1	8	1	6
58	उतरास	-	6	-	5
59	हरचेनपुर	-	8	-	7
60	कन्धारपुर	-	6	-	5
61	बिन्द	-	6	-	5
62	धरौली	-	5	-	4
63	कलयानपुर	-	7	-	6
64	महुली	-	7	-	7
65	उगापुर	-	7	-	7
66	सागीपुर	3	11	3	11
67	आमापुर	-	8	-	7
68	नेवादाखुर्द	1	8	1	7
69	दशरथपुर	-	8	-	9

70	नरहरपुर	-	10	-	8
71	लक्ष्मणपुर	4	9	3	9
72	रुक्मैयापुर	1	6	1	5
73	सवैया	-	5	-	5
74	सरायभीमसेन	-	5	-	5
75	गुलामीपुर	-	6	-	6
76	रघुनाथपुर	-	6	-	5

स्रोत टाऊन विलेज डाइरेक्टरी, भारतीय जनगणना, 1961 - 81

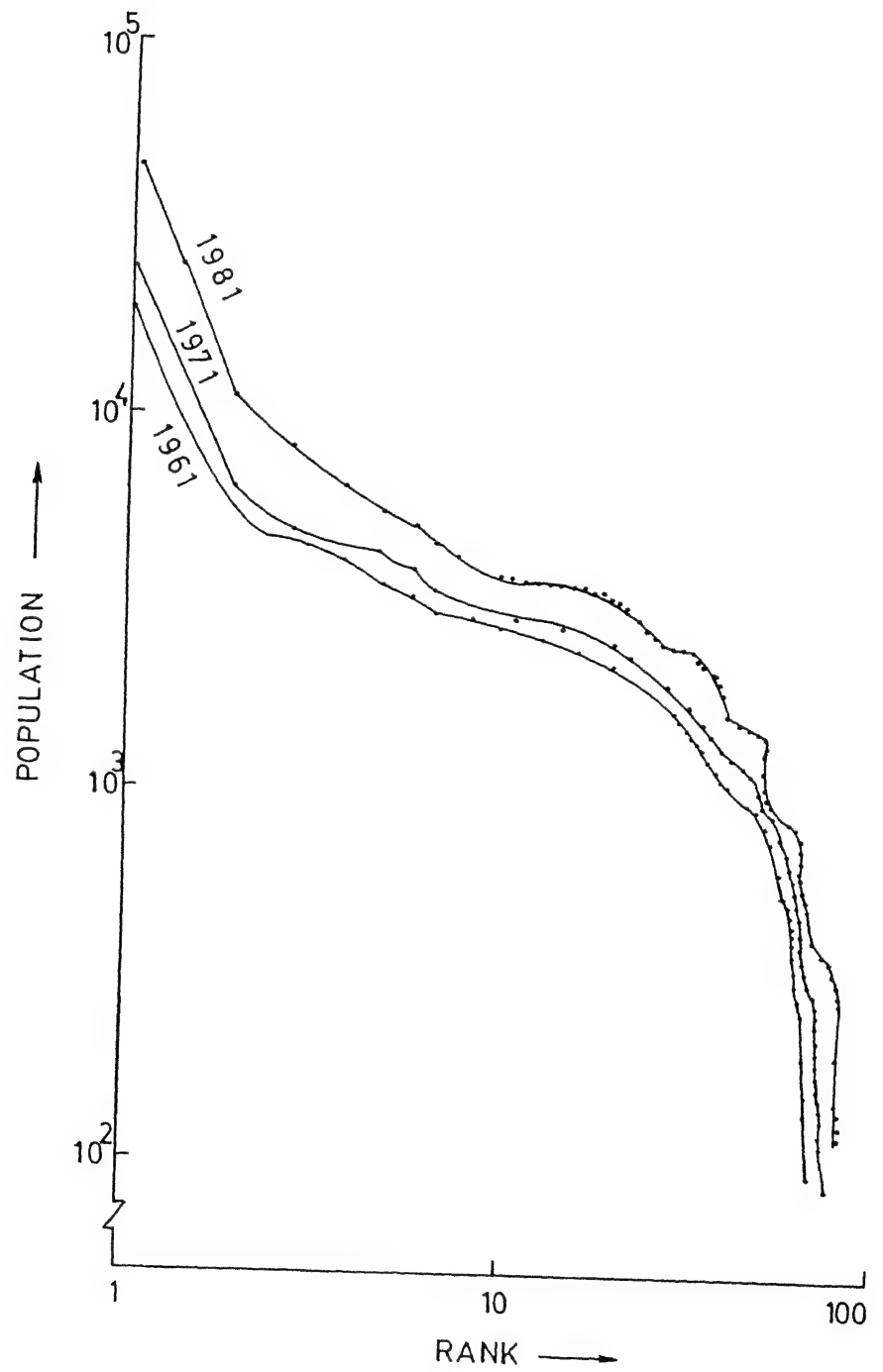


Fig 4 1

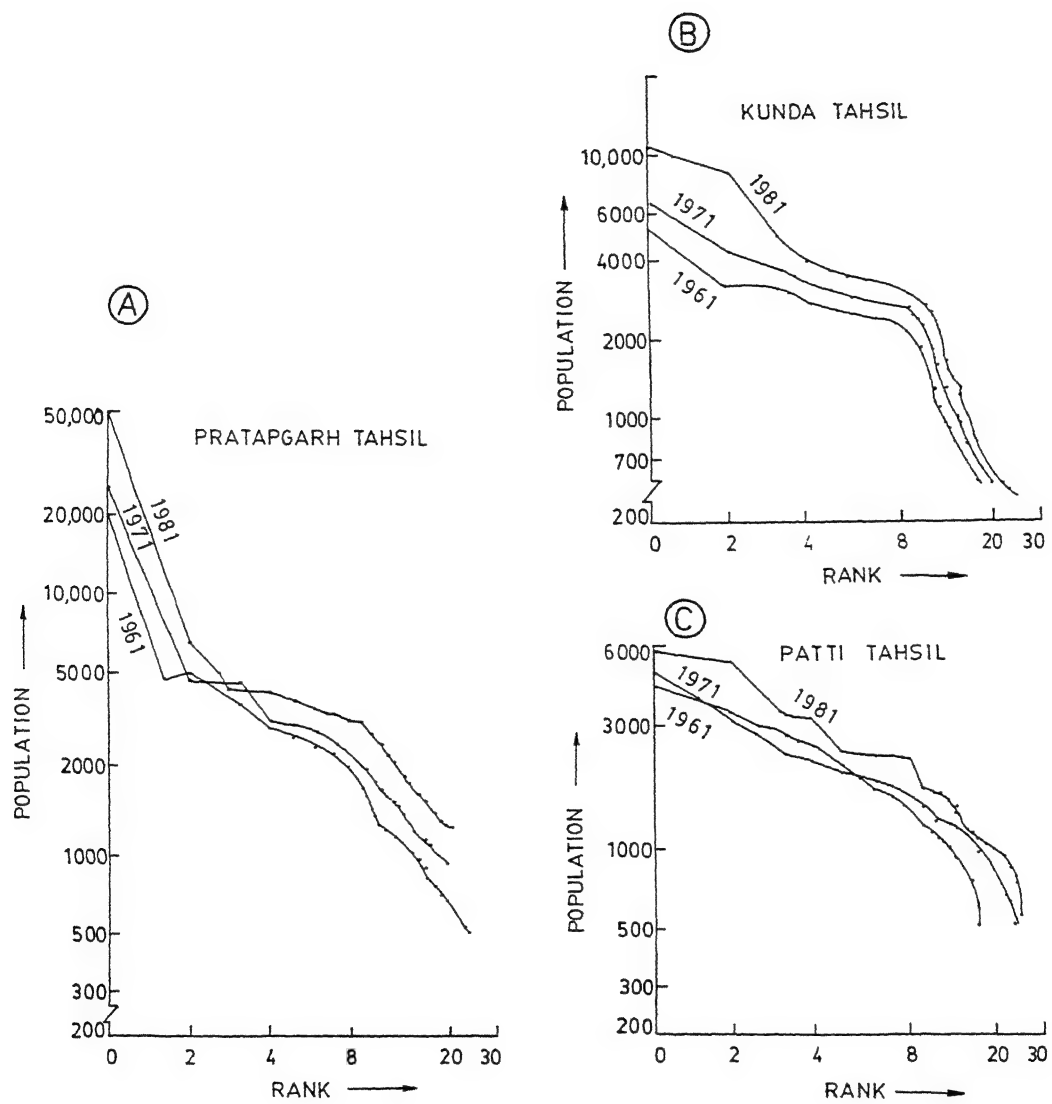


Fig 4 2

दशकों (1961, 1971, 1981) में एक ही जैसा रहा है, किन्तु मध्यवर्ती भाग में इस रेखाचित्र का आकार उन्नतोदर प्रकार का हो गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ सेवाकेन्द्रों की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। इससे यह भी स्पष्ट है कि सेवाकेन्द्रों का सोपानक्रम समुचित रूप से संगठित नहीं है। यह प्रतिरूप विषमता का द्योतक है। यही तथ्य तहसील स्तर पर भी परिलक्षित होते हैं।

सेवा केन्द्रों का कार्यात्मक सोपान क्रम - सेवा केन्द्रों को कार्यात्मक सोपान क्रम के अनुसार वर्गीकृत करने के लिये अधिवास सूचकांक ज्ञात किया गया है। अधिवास सूचकांक को ज्ञात करने के लिये उडकाक तथा वेली (1979) द्वारा प्रदर्शित विधि का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम कार्यात्मक भार निर्धारित करने में अधोलिखित सूत्र प्रयोग में लाया गया है

$$FCV = \frac{1 \times 100}{f}$$

FCV = Functional Centrality Value

f = Frequency of a Function in all service centres

इस सूत्र के आधार पर परिकलित सेवाओं का कार्यात्मक भार सारिणी सख्या 4.2 में प्रस्तुत किया गया है। इस सारिणी के आधार पर प्रत्येक सेवा केन्द्र का अधिवास सूचकांक परिकलित किया गया है जिसके लिए अधोलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है।

$$SI = FCV \times Cf$$

SI = Settlement Index

FCV = Functional Centrality Value

Cf = Occurrence of Functions in a service centre

इस सूत्र के आधार पर परिकलित प्रत्येक सेवा केन्द्र का सूचकांक सारिणी सख्या 4.3 में प्रस्तुत किया गया है। इसके आधार पर सेवा केन्द्रों को पदानुक्रम में वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया

सारणी सख्या 4 2 अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं का कार्यात्मक भार

क्रम सं०	सेवाये	कार्यात्मक भार
शिक्षा सेवायें		
1	प्राइमरी स्कूल	2 0
2	जूनियर बेसिक स्कूल	0 9
3	सीनियर बेसिक स्कूल	2 4
4	हाईस्कूल	3 4
5	इन्टरमीडियेट कालेज	10 0
6	डिग्री कालेज	16 6
स्वास्थ्य सेवायें		
7	चिकित्सालय	2 8
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5 6
9	परिवाण कल्याण केन्द्र	5 0
10	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	3 6
11	औषधालय	3 3
डाक व तार सेवाये		
12	डाकघर	1 2
13	तारघर एवं फोन	2 7
बस एवं रेलवे स्टेशन सेवायें		
14	बस स्टॉप व स्टेशन	1 8
15	रेलवे स्टेशन	16 7
बाजार सेवायें		
16	बाजार के दिन	0 5
17	बैंक सेवाये	4 6
18	पुलिस स्टेशन सेवा	10 0

स्रोत सूत्र के आधार पर परिकलित

-
संरिणी सख्या 4 3 प्रतापगढ जनपद के सेवाकेन्द्रों मे उपलब्ध सेवायें (1961-81)
अधिवास सूचकाक

क्रम सं०	सेवाकेन्द्र	अधिवास सूचकाक	
01	बेला प्रतापगढ	243 8	306 9
02	कुण्डा	61 0	112 6
03	मानिकपुर	22 8	69 0
04	प्रतापगढ सिटी	3 2	73 5
05	कन्धई मधुपुर	-	7 3
06	पट्टी	73 1	102 4
07	ऐधा	-	5 3
08	अन्तू	7 2	47 8
09	कटरा मेदिनीगज	3 2	18 7
10	लरून	-	9 1
11	रेहुआ लालगज	22 3	30 9
12	अन्तसुन्ड	3 2	19 4
13	परियावा	7 2	14 7
14	सराय इनायत	3 2	17 6
15	सडवा चन्द्रिका	11 1	22 7
16	राहाटीकर	3 2	8 5
17	सबलगढ	4 0	24 3
18	जामताली	13 5	14 4
19	डीहमेहदी	3 2	12 4
20	रामजीतपुर चिलबिला	23 8	10 6

21	धारूपुर	11 4	17 1
22	अजगरा	-	13 6
23	सग्रामगढ	37 0	19 5
24	दलीपपुर	24 0	24 5
25	ताला	-	13 2
26	भादरूँ	-	21 5
27	रामापुर	6 3	4 9
28	रामगज	7 3	23 1
29	उदईशाहपुर	4 0	25 9
30	मानधाता	13 5	26 8
31	मझिलागो	3 2	10 9
32	आसपुर देवसरा	9 5	10 6
33	भदरी	30 3	35 7
34	सराय भूपत	-	23 1
35	शीतलामऊ	4 0	14 6
36	आधारपुर	-	10 4
37	कालाकाकर	4 0	54 3
38	राजगढ	3 2	14 8
39	रामनगर भोजपुर	-	10 1
40	भूपियामऊ	20 6	26 4
41	सहेरूआ	-	16 2
42	नरी	-	10 9
43	कोहडौर	14 3	16 8
44	डडैयाडीह	4 0	13 7

45	गडवारा	16 0	11 3
46	कजासरायगुलामी	3 2	14 6
47	नरई	-	9 3
48	सैफाबाद	5 3	12 7
49	मेहलवा मलकिन	-	11 0
50	भदोही	-	11 2
51	अठेहा	6 3	10 9
52	बासी	-	15 5
53	पिचूरा	-	14 1
54	सदहा	12 5	6 0
55	भोजपुर	-	13 4
56	भगेसरा	-	18 0
57	पूरेगोलिया	4 0	13 6
58	उतरास	-	10 9
59	हरचेनपुर	-	13 9
60	कन्धारपुर	-	8 5
61	बीन्द	-	11 0
62	धरौली	-	6 0
63	कल्याणपुर	-	9 7
64	महुली	-	14 8
65	उगापुर	-	17 0
66	सागीपुर	22 8	31 4
67	आयापुर		15 5

68	नेवादाखुर्द	4 0	26 8
69	दशरथपुर	-	7 3
70	नरहरपुर	-	19 7
71	लक्ष्मणपुर	23 6	24 0
72	रूकैयापुर	4 3	6 3
73	सवैया	-	8 3
74	सरायभीमसेन	-	11 5
75	गुलामीपुर	-	16 7
76	रघुनाथपुर	-	10 5

स्रोत परिकलित

गया है । सोपानक्रम समूह ज्ञात करने के लिये एक वितरण आरेख (चित्र सख्या 4 3) की रचना की गयी है जिसके "य" अक्ष पर सेवा केन्द्रों के जनसख्या का क्रम दिखाया गया है तथा "र" अक्ष पर सेवा केन्द्रों के अधिवास सूचकांक को प्रदर्शित किया गया है । इस वितरण आरेख के आधार पर सेवा केन्द्रों को तीन भागों में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार है

1 प्रथम सेवा केन्द्र बेला प्रतापगढ़ जो जनपद का मुख्यालय है, अध्ययन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र है तथा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सामाजिक व आर्थिक संस्थाएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध है । बेला प्रतापगढ़ का अधिवास सूचकांक 306 9 है और इसे प्राथमिक केन्द्र की संज्ञा दी जा सकती है ।

2 द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्र - इसके अन्तर्गत कुन्डा (112 6), पट्टी (102 4), प्रतापगढ़ सिटी (73 5), मानिकपुर (69 0) तथा कालाकाकर (54 3) है । यह सभी सेवा केन्द्र 1981 की जनगणना के अनुसार नगरीय अधिवास भी है ।

3 तृतीय श्रेणी के सेवा केन्द्र - यह सेवा केन्द्रों का सबसे बड़ा समूह है जिसके अन्तर्गत 70 सेवा केन्द्र आते हैं जो इस प्रकार हैं अन्तू (47 8), भदरी (35 7), सागीपुर (31 4), रेहुआलालगंज (30 9), नेवादाखुर्द (26 8), मानधाता (26 8), भोपियामऊ (26 4), उर्दूशाहपुर (25 91), दलीपपुर (24 5), सबलगढ़ (24 3), लक्ष्मणपुर (24 0), रामगढ़ (23 1), सरायभूपत (23 1), सडवा चन्द्रिका (22 7), भादरूँ (21 5), नरहरपुर (19 7), सगामगढ़ (19 5), परियावाँ (19 4), कटरामेदनीगंज (18 7), भगसेरा (18 0), सराय इन्द्रावत (17 6), धारूपुर (17 1), उगापुर (17 0), कोहडौर (16 8), गुलामीपुर (16 7), सहेरुआ (16 2), बासी (15 5), आमापुर (15 5), महुली राजगढ़ (14 8), शीतलामऊ (14 6), कजासरायगुलामी (14 6), परियाँवा (14 5), जामताली (14 4), पिचूरा (14 1), हरचेनपुर (13 9), उडैयाडीह (13 7), पूरेगोलिया (13 6), अजगरा (13 6), भोजपुर (13 4), ताला (13 2), सैफाबाद (12 7), डीहमेहदी (12 4), सरायभीमसेन (11 5), गडवारा (11 3), भदोही (11 2), महेलवा मलकिन (11 0), बिन्द (11 0), उत्तरास (10 9), अठेहा

(10 9), नरी (10 9), मझिलेगा (10 9), आसपुरदेवसरा (10 6), रामजीतपुर चिलबिला (10 6),, रघुनाथपुर (10 5), आधारपुर (10 5), कल्यानपुर (9 7), नरई (9 3), लरून (9 1), राहाटीकर (8 5), कन्धारपुर (8 5), सवैया (8 3), दशरथपुर (7 3), कन्धईमधुपुर (7 3), रोकैयापुर (6 3), धरौली (6 0), सदहा (6 0), ऐधा (5 3), रामापुर (4 9) ।

सेवाकेन्द्रों का वितरण प्रतिरूप - इन सेवा केन्द्रों के वितरण प्रतिरूप (चित्र सख्या 4 4) से स्पष्ट है कि तृतीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों का वितरण रैन्डम प्रकार का है । इस मानचित्र से यह भी स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में कई ऐसे भाग हैं जो सेवा केन्द्र विहीन हैं । सेवा केन्द्रों के समान वितरण के अभाव में स्थानिक, संगठन का अभाव है जो पिछड़ेपन का द्योतक है । ठीक इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के सेवाकेन्द्र भी सख्या में कम तथा अनियमित रूप से वितरित हैं । अध्ययन क्षेत्र के उत्तर पश्चिम का भाग ऐसा है जहाँ पर द्वितीय श्रेणी के कोई भी सेवा केन्द्र नहीं पाये जाते हैं । इससे स्पष्ट है कि तृतीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों एवं द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों में सम्बन्ध का अभाव है । सभी स्तर के सेवा केन्द्र बेला प्रतापगढ़ पर ही आश्रित हैं । यह ही इसकी प्राथमिकता का मुख्य कारण है ।

सेवाकेन्द्रों के परिवर्तन की दिशा - यदि हम विगत 20 वर्षों में हुये परिवर्तनों पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि 1961 और 1981 के मध्य सेवा केन्द्रों की संरचना में पर्याप्त अन्तर आया है । सन् 1961 तथा 1981 के मध्य सेवा केन्द्रों में उनकी कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक प्रकार तथा अधिवास सूचकांक का तुलनात्मक अध्ययन सारिणी (सख्या 4 3) से किया जा सकता है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि अधिकांश सेवा केन्द्रों की कार्यात्मक इकाई में विगत दो दशकों में दुगुने से अधिक वृद्धि हुई है । इस सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि 34 ऐसे अधिवास हैं, जो सन् 1981 में पहली बार सेवा केन्द्र के रूप में उभर कर आये हैं । ठीक इसी तरह कार्यात्मक प्रकार में भी वृद्धि हुई है । इनके आधार पर परिकल्पित अधिवास सूचकांक में भी पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । परिवर्तन की दिशा सकारात्मक है क्योंकि सभी सेवा केन्द्रों में कार्यात्मक इकाईयों एवं प्रकारों में वृद्धि हुई है । सन् 1961 की स्थिति के आधार पर वितरण आरेख (चित्र सख्या 4 3) की रचना की गयी है जिसमें सेवा

केन्द्रों के सूचकांक तथा उनकी जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है । इस आरेख से स्पष्ट है कि बेला प्रतापगढ़ उस समय भी प्रथम श्रेणी का सेवा केन्द्र था किन्तु द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों की संख्या केवल दो थी । इन द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों (पट्टी एवं मानिकपुर) का स्थान सन् 1981 में जहाँ सुरक्षित है, वहीं दूसरी ओर तीन अन्य सेवा केन्द्र आ जुड़े हैं । सबसे अधिक परिवर्तन तृतीय स्तर के सेवा केन्द्रों में हुआ है । इनकी संख्या सन् 1961 में केवल 31 थी जबकि सन् 1981 में इस वर्ग के अन्तर्गत 70 सेवा केन्द्र हो गये हैं । इस प्रकार इस वर्ग में सेवा केन्द्रों की संख्या बढ़ी है ।

सेवा केन्द्रों का कार्य - आकार सम्बन्ध - बेरी तथा गैरीसन (1958) का विचार है कि सेवा केन्द्रों की जनसंख्या तथा उनके द्वारा प्रतिपादित किये जाने वाले कार्य में सीधा सह सम्बन्ध है । सामान्य परीक्षण में भी यह देखा गया है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे सेवाकेन्द्र की सेवाओं तथा सेवा की इकाइयों में वृद्धि होती है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है । इस दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों की जनसंख्या तथा उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाली सेवाओं को आधार मान कर अधोलिखित सकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है ।

1. सेवा केन्द्रों की जनसंख्या एवं उनमें केन्द्रित कार्यात्मक इकाइयों में धनात्मक सह सम्बन्ध है ।
2. सेवा केन्द्रों की जनसंख्या अथवा आकार एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में धनात्मक सह - सम्बन्ध है ।
3. सेवा केन्द्रों की कार्यात्मक इकाइयों एवं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं (कार्यात्मक प्रकार) में धनात्मक सह सम्बन्ध है ।

उपरोक्त तीनों सकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए छ आरेखों (चित्र संख्या 4 5, अ, ब, स, द, य, फ) की रचना की गयी है । इन आरेखों से स्पष्ट है कि एक निश्चित जनसंख्या तक सेवा केन्द्रों की कार्यात्मक इकाइयों में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं दृष्टि गोचर होता है ।

उदाहरण के लिए, 100 से 300 जनसंख्या वाले सेवा केन्द्रों में कार्यात्मक इकाई की संख्या में कोई अन्तर नहीं है। पुनः 300 से 1000 की आबादी तक और 1000 से 4000 आबादी तक, कार्यात्मक इकाईयों की संख्या में कोई विशेष अन्तर नहीं है किन्तु 4000 के ऊपर वाले सेवा केन्द्र, मुख्य रूप से जिनकी आबादी 5000 से 50,000 के बीच है, उनकी कार्यात्मक इकाईयों में बहुत ही उल्लेखनीय अन्तर पाया जाता है। 5000 से 11,000 के बीच वाले सेवा केन्द्रों की इकाईयों में पर्याप्त अन्तर आया है। 5000 से 11000 के बीच वाले सेवा केन्द्रों में कार्यात्मक इकाईयों की संख्या में आबादी बढ़ने के साथ वृद्धि होती गयी है। किन्तु 11000 के ऊपर आबादी वाले सेवा केन्द्र (प्रस्तुत अध्ययन में बेला प्रतापगढ़ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है) में कार्यात्मक इकाईयों की संख्या सहसा बहुत अधिक हो गयी है। 5000 से 11000 आबादी वाले सेवा केन्द्रों में कार्यात्मक इकाईयों की संख्या 20 से 60 के बीच है। जबकि 50,000 इकाई वाले सेवा केन्द्र की कार्यात्मक इकाई की संख्या 150 है। इस प्रकार इतना तो स्पष्ट है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ कार्यात्मक इकाईयों में वृद्धि होती है। किन्तु कम आबादी वाले छोटे सेवा केन्द्रों में यह बात स्पष्ट नहीं होती है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश सेवा केन्द्र 4000 से कम आबादी वाले हैं। अतः रैंक - आर्डर जिका सूत्र इस प्रकार है

पर आधारित सह - सम्बन्ध धनात्मक नहीं प्रतीत होता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिये सेवा केन्द्रों को उनकी जनसंख्या तथा कार्यात्मक इकाईयों के क्रम के आधार पर तहसील स्तर पर सह सम्बन्ध गुणांक उक्त सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है। सेवा केन्द्रों की जनसंख्या एवं कार्यात्मक इकाईयों में तहसील स्तर पर जो सह - सम्बन्ध प्राप्त किये गये हैं वे ऋणात्मक हैं। कुन्डा, पट्टी तथा प्रतापगढ़ तहसीलों के परिकलित सह - सम्बन्ध क्रमशः - 0.3, - 0.3, तथा - 0.4 है (सारिणी संख्या 4.4)। वर्ष 1961 पर आधारित आकड़ों के आधार पर परिकलित

सारिणी सख्या 4 4 प्रतापगढ जनपद मे तहसील स्तर पर सेवाकेन्द्रों की कार्यत्मक इकाई, कार्यत्मक प्रकार, अधिवास सूचकांक तथा उनकी जनसख्या का सह-सम्बन्ध गुणांक
(1961-81)

चर	1961				1981			
	कुन्डा	प्रतापगढ	पट्टी	कुन्डा	प्रतापगढ	पट्टी	प्रतापगढ	पट्टी
सेवाकेन्द्रों की जनसख्या तथा कार्यत्मक इकाई	-0 3	-0 1	+0 9	-0 3	-0 4	-0 3	-0 4	-0 3
सेवाकेन्द्रों की जनसख्या तथा कार्यत्मक प्रकार	-0 9	-0 2	-0 5	-0 3	-0 2	-0 2	-0 2	-0 2
सेवाकेन्द्रों की जनसख्या तथा अधिवास सूचकांक	-0 1	-0 1	-0 1	-0 2	-0 3	-0 4*	-0 3	-0 4*

स्रोत परिकलित

सह सम्बन्ध भी ऋणात्मक है । सेवा केन्द्रों की जनसंख्या तथा उनके द्वारा दी गयी सेवाओं के प्रकार में सम्बन्ध देखने के लिये भी रेखा चित्र तैयार किया गया है । इससे भी पहले जैसी स्थिति उभर कर सामने आती है । इस रेखाचित्र से स्पष्ट है कि 1000 तक की आबादी वाले सेवा केन्द्रों की सेवाएँ 4 से 8 प्रकार की हैं । 1000 आबादी वाले सेवा केन्द्रों में भी सेवाओं की संख्या सामान्यतः 4 से 10 के बीच है । इस प्रकार 10,000 आबादी तक कोई विशेष अन्तर स्पष्ट नहीं होता है । किन्तु इससे अधिक आबादी वाले केन्द्र उदाहरण के लिये बेला प्रतापगढ़ एवं कुन्डा में सेवाओं की संख्या 14 एवं 16 प्रकार की है । इस सह - सम्बन्ध को तहसील स्तर पर देखने का प्रयत्न किया गया है , तहसील स्तर पर सेवा केन्द्रों की जनसंख्या एवं उनके सेवा के प्रकार में ऋणात्मक सह सम्बन्ध है । कुन्डा, पट्टी एवं प्रतापगढ़ तहसीलों में सह सम्बन्ध क्रमशः - 0.3, - 0.2 तथा -0.3 है । सेवा केन्द्रों में कार्यात्मक इकाई एवं उनके कार्यात्मक प्रकारों का सह-सम्बन्ध भी चित्र द्वारा (चित्र संख्या 4.5) प्रस्तुत किया गया है । इस आरेख से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सेवा केन्द्रों की कार्यात्मक इकाई 20 से कम ही है । तथा उनके कार्यात्मक प्रकार में भी अन्तर नहीं है । अधिकांश सेवा केन्द्रों में कार्यात्मक इकाई की संख्या 4 और 12 के बीच है । इस आरेख से भी धनात्मक सह - सम्बन्ध बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता है । यही स्थिति 20 वर्ष पहले भी थी । जैसा कि चित्र संख्या 4.5 से स्पष्ट होता है । यद्यपि इनमें कोई भी सह - सम्बन्ध प्रमाणिक नहीं प्रतीत होते हैं । किन्तु इस दिशा में और अधिक शोध की भी आवश्यकता है ।

सेवा केन्द्रों में जनसंख्या की परिवर्तनशीलता

सेवा केन्द्रों में कार्यात्मक इकाई एवं उनके प्रकारों के विश्लेषण के साथ - साथ उनकी जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है । यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो आर्थिक प्रक्रिया से जुड़ी है । विगत 20 वर्षों (1961 - 81) में सेवा केन्द्रों में होने वाले जनसंख्या की वृद्धि को सारिणी 4.5 - द्वारा प्रदर्शित किया गया है । इस सारिणी के आधार पर सेवा केन्द्रों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है

1. वे सेवा केन्द्र जिनमें जनसंख्या वृद्धि 200% से अधिक हुयी है जैसे - कुन्डा, परियावाँ एवं सराय भूपत ।

सारणी सख्या 4 5 सेवा केन्द्रों में जनसख्या वृद्धि (1961 - 81)

क्रम सं०	सेवा केन्द्र	प्रातशत
01	बेला प्रतापगढ	133 4
02	कुन्डा	273 6
03	मानिकपु	62 1
04	प्रतापगढ	39 4
05	कन्धई मधुपुर	37 5
06	पट्टी	114 3
07	ऐधा	58 7
08	अन्तू	20 5
09	कटरा मेदिनी गज	158 8
10	लरून	46 6
11	रेहुआ लाल गज	26 6
12	अन्तसुण्ड	3 0
13	परियावा	370 9
14	सराय इन्द्रावत	42 2
15	सडवा चन्द्रिक	39 5
16	शहाटीकर	26 2
17	सबलगढ	48 7
18	जामताली	25 1
19	डीह मेहदी	44 2
20	रामजीतपुर चिलबिला	48 9

21	धारूपुर	33 2
22	अजगरा	28 9
23	सग्रामगढ	43 6
24	दलीपपुर	59 4
25	ताला	57 8
26	भादयू	79 6
27	रामापुर	110 1
28	रामगज	64 4
29	उदई शाहपुर	54 1
30	मानधाता	83 5
31	मझिलगो	10 0
32	आसपुर देवसरा	62 1
33	भदरी	38 1
34	सराय भूपत	490 8
35	शीतलामऊ	68 1
36	आधारपुर	31 8
37	मोहम्मदाबाद उर्फ कालाकाकर	13 2
38	राजगढ	9 3
39	रामनगर भोजपुर	25 3
40	भोपियामऊ	92 5
41	सहेरूआ	53 1
42	नरी	40 7
43	कोहडौर	66 7
44	उडैयाडीह	50 7
45	गडवारा	32 4

46	कजासराय गुलामी	43 9
47	नरई	35 9
48	सैफाबाद	41 9
49	मेहलवा मलकिन	64 6
50	भदोही	70 2
51	अठेहा	32 0
52	बासी	47 3
53	पिचूरा	25 1
54	सदहा	51 2
55	भोजपुर	89 5
56	भगेश्वर	33 2
57	पूरे गोलिया	111 2
58	उतरास	47 2
59	हरचेनपुर	84 4
60	कन्धारपुर	19 6
61	बीन्द	61 5
62	धरौली	-7 3
63	कल्यानपुर	42 3
64	महुली	--
65	दशरथपुर	0 9
66	उगापुर	48 2
67	सागीपुर	-4 4
68	आमापुर	56 2
69	नेवादाखुर्द	20 8
70	नरहरपुर	22 6

71	लक्ष्मणपुर	50 0
72	रोकैयापुर	15 3
73	सवेया	43 8
74	रघुनाथपुर	15 7
75	सरायभीमसेनपुर	43 2
76	गुलामीपुर	46 4

श्रोत जनपद जनगणना पुस्तिका। 1961, 1981

- 2 वे सेवा केन्द्र जिनमे जनसख्या वृद्धि 150% से 200% के बीच है जैसे - बेला प्रतापगढ़, कर्धई मधुपुर, कटरा मेदनीगज, रामापुर एव पूरे गोलिया
- 3 वे सेवा केन्द्र जहाँ पर कि जनसख्या वृद्धि 50% से 100% के मध्य है जैसे - मानिकपुर, ऐधा, दलीपपुर, ताला, भाद्यू, रामगज, उदयीशाहपुर, मानधाता, आसपुर देवसरा, शीतलमऊ, भोपिया मऊ, सहेरूआ, कौहडौर, उडैयाडीह, मेहलवा मालकिन, सदहा, भोजपुर, हरचेनपुर, बीद, आलापुर, लक्ष्मणपुर एव सराय भीमसेनपुर आदि ।
- 4 वे सेवा केन्द्र जिनकी जनसख्या मे 50% से क्रम वृद्धि हुयी है वे इस प्रकार है - नरी, गडवारा, कजासराय गुलामी, नरई, सैफाबाद, अठेहा, बासी, पिचूरा, भगसेरा, उतरास, कन्धारपुर, कल्यानपुर, आगापुर, नेबादा खुर्द, नरहरपुर, रोकैयापुर, सवैया, रघुनाथपुर, मुलामीपुर ।
- 5 कुछ ऐसे भी सेवा केन्द्र है जहाँ पर अपवादस्वरूप जनसख्या मे ह्रास हुआ है जैसे - धरौली, दशरथपुर, सागीपुर एव महुली ।

सेवा केन्द्रों मे साक्षरता की स्थिति

यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचकांक है जो सामाजिक स्तर मे परिवर्तनशीलता का द्योतक है। अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों का शैक्षिक स्तर एव विगत दो दशकों (1961 - 81) मे कुल जनसख्या मे साक्षरता प्रतिशत सारिणी 4 6 मे प्रस्तुत किया गया है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि सेवा केन्द्रों मे निवास करने वाली जनसख्या का साक्षरता अनुपात बढ़ रहा है । 99 प्रतिशत केन्द्रों मे साक्षरता की स्थिति मे सुधार हुआ है । सन् 1981 की साक्षरता प्रतिशत के आधार पर सेवा केन्द्रों को अधोलिखित वर्गो मे विभक्त किया जा सकता है

- 1 वे सेवा केन्द्र जहाँ पर साक्षरता का अनुपात 25 से अधिक है । जैसे - प्रतापगढ़, पट्टी, राजगढ़, तथा सराय भीमसेनपुर ।
- 2 वे सेवा केन्द्र जहाँ पर कि साक्षरता का अनुपात 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है जैसे -

सरिणी संख्या 4 6 सेवाकेन्द्रों में साक्षरता 1961-81 (प्रतिशत में)

क्रम सं०	सेवाकेन्द्र	1961	1981
01	बेला पतापगढ		56 4
02	कुन्डा	19 0	31 8
03	मानिकपुर	6 9	26 3
04	प्रतापगढ सिटी	22 6	24 8
05	कन्धई मधुपुर	2 2	29 1
06	पट्टी	20 8	51 8
07	ऐधा	9 7	30 0
08	अन्तू	13 8	31 6
09	कटरा मेदिनीगज	18 5	33 4
10	लरूल	6 0	14 7
11	रेहुआ लालगज	12 6	22 0
12	अन्तसण्ड	8 9	20 7
13	परियावा	13 9	18 7
14	सराय इन्द्रावत	9 5	23 2
15	सडवा चन्द्रिका	15 4	26 9
16	राहाटीकर	20 3	20 4
17	सबलगढ	16 1	37 0
18	जामताली	15 2	20 6
19	डीहमेहदी	20 4	28 1
20	रामजीतपुर चिलोबेला	17 2	15 1

21	धारूपुर	15 0	25 9
22	अजगरा	14 5	28 3
23	सग्रामगढ	12 8	24 5
24	दलीपपुर	24 8	17 8
25	ताला	18 1	31 3
26	भादयू	8 7	37 2
27	रामापुर	15 3	18 7
28	रामगज	28 1	29 4
29	उदईशाहपुर	17 4	29 7
30	मानधाता	21 4	27 2
31	मञ्जिलगो	4 5	25 6
32	आसपुर देवसरा	12 6	22 8
33	भदरी	2 3	27 2
34	सराय भूपत	-	38 0
35	शीतलमऊ	22 0	37 8
36	आधारपुर	12 0	35 1
37	मोहम्मदाबाद उफे कालाकाकर	39 1	38 7
38	राजगढ	11 8	55 2
39	रामनगर भोजपुर	21 5	24 3
40	भोपियामऊ	21 9	31 3
41	सहेरूआ	18 1	23 6
42	नरी	4 0	16 7
43	कोहडौर	25 0	37 6

44	उडेयाडीह	20 0	28 3
45	गडवारा	22 2	31 3
46	कजासराय गुलामी	13 8	24 5
47	नरई	11 2	20 2
48	सेफाबाद	15 1	26 2
49	मेहलवा मालकिन	12 7	42 7
50	भदोही	18 2	32 4
51	अठेहा	16 1	21 7
52	बासी	9 3	17 8
53	पिचूरा	3 8	9 8
54	सदहा	6 8	13 8
55	भोजपुर	21 9	23 8
56	भगसेरा	24 7	35 5
57	पूरेगोलिया	61 5	43 7
58	उतरास	8 1	16 5
59	हरचेनपुर	19 0	22 7
60	कन्धारपुर	15 6	17 2
61	बीन्द	12 8	19 8
62	धरोली	15 8	22 8
63	कल्यानपुर	3 8	31 5
64	महुली		10 0
65	दशरथपुर	11 0	19 0
66	उगापुर	20 6	28 6

67	सागीपुर	16 7	32 0
68	आमापुर	17 8	28 3
69	नेवादाखुदे	9 6	35 1
70	नरहरपुर	8 7	41 9
71	लक्ष्मणपुर	36 6	47 4
72	रोकैयापुर	22 9	26 2
73	सवैया	10 4	18 8
74	रघुनाथपुर	20 9	32 3
75	सरायभीमसेनपुर	18 5	63 2
76	गुलामीपुर	8 2	24 6

स्रोत जनपद जनगणना पुस्तिका 1961, 1981

भोपियामऊ, कौहडौर, गडवारा, सैफाबाद, मेहलवा मलकिन, कुन्डा, मानिकपुर, कधई, मधुपुर, ऐधा, अन्तू, कटरा मेदिनीगज, सडवा चन्द्रिका, सबलगढ, डीह मेहथी, धारूपुर, अजगरा, ताला, भादयूँ, रामगज, उदयीशाहपुर, मानधाता, मझिलुगो, भदरी, सराय भूपत, शीतलमऊ, धारूपुर, कालाकाकर, भदोही, उडैयाडीह, भगसेरा, पूरेगोलिया, कल्यानपुर, आगापुर, सागीपुर, आमापुर, नरहरपुर, नेवादा खुर्द, लक्ष्मणपुर, रोकैयापुर तथा रघुनाथपुर ।

- 3 वे' सेवा केन्द्र जहाँ पर कि साक्षरता का अनुपात 25 प्रतिशत से कम है जैसे - प्रतापगढ सिटी, लरून, रेहुआ, लालगज, अन्तसुन्ड, सराय इन्द्रावत, परियावाँ, रहाटीकर, जामताली, चिलबिला, सगामगढ, दलीपपुर, रामपुर, आसपुर देवसरा, राम नगर, भोजपुर, नरी, सहेरवा, कजा सराय गुलामी, नरई, अठेहा, बासी, पिचूरा, सदहा, भोजपुर, उतरास, हरचेनपुर, कधारपुर, बीद, धरौली, महुली, दशरथपुर, सवैया एव मुलामीपुर ।

यह उल्लेखनीय है कि इनमे से पिचूरा को छोड कर शेष अन्य सेवा केन्द्रों का साक्षरता अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक है । सन् 1961 की तुलना मे 1981 मे जो वृद्धि हुयी है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामाजिक परिवर्तन की लहर अब तीव्रता से चल पडी है । यद्यपि कि साक्षरता स्तर मे अभिवृद्धि जनसख्या प्रवास को बढावा दे रही है । यही कारण है कि तहसील एव जिला मुख्यालयों की जनसख्या बढ रही है तथा रोजगार के अवसर की तलाश मे लोग आस - पास के नगरों उदाहरण के लिये लखनऊ, कानपुर, बनारस एव इलाहाबाद की ओर प्रवास कर रहे है ।

सेवा केन्द्रों की आर्थिक सरचना - सेवा केन्द्रों की आर्थिक सरचना का विश्लेषण करने के लिये उनमे काम करने वाली जनसख्या को प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय वर्गों मे विभक्त किया गया है और 1961 तथा 1981 के आँकड़ों के आधार पर तुलनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । यह तुलनात्मक स्थिति रेखाचित्र (4 6) द्वारा प्रदर्शित किया गया है । इससे अधोलिखित तीन निष्कर्ष निकलते है

1. तृतीयक प्रकार के व्यवसाय मे लगी हुयी जनसख्या के प्रतिशत मे सन् 1981 में 1961 की

तुलना में वृद्धि हुई है ।

2 द्वितीय प्रकार के व्यवसाय में लगी हुयी जनसख्या के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है तथा साथ ही साथ अधिकांश सेवा केन्द्रों में द्वितीयक प्रकार का व्यवसाय प्रचलित हो रहा है ।

3 प्राथमिक प्रकार के व्यवसाय के अनुपात में 1961 की तुलना में 1981 में कमी आयी है ।

अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिवासों में सरचनात्मक परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ रही है । इससे उनमें न केवल गतिशीलता आई है अपितु उनका आर्थिक आधार भी सुदृढ़ हो रहा है । निश्चय ही इससे स्थानिक एवं क्षेत्रीय समायोजन एवं आर्थिक विकास में वृद्धि होगी ।

REFERENCES

- 1 Berry, B.J L., (1967), Geography of Market Centres and Retail Distribution, Englewood Cliffs . Prentice - Hall
- 2 Berry, B J.L and Garrison, W L (1958), The Functional Bases of the Central Place Hierarchy, Economic Geography, 34, 145-54
- 3 Breesé, G (1963), Urban Development Problems in India, A.A.A.G. 53, 253 - 265
- 4 Brush, J.E (1953), The Hierarchy of Central Places in South Western Wisconsin, Geographical Review, 43, 380 - 402
- 5 Brush, J.E. & Bracy, H.E. (1955), Rural Service Centres in Southwestern Wisconsin and England, Geog. Rev., 45, 4, 559-69
- 6 Christaller, W. (1966), Central Place in Southern Germany (Translated by C.W. Baskin), New Jersey : Englewood Cliffs
- 7 Cooley, C.H. (1984) The Theory of Transportation, Publication the American Economic Association, 9, 1 - 48
- 8 Dickinson, R E. (1932), The Distribution and Function of the Smaller Urban Settlement of East Anglia, Geography , 17, 19-31

- 9 Folke, Steen, (1968) Central Place System and Spatial Interaction, in Jacobsen, N.K and Johnston, R.H. (eds),
21st Intl Geogr Cong Collected paper - 57
- 10 Galpin, G.J (1915), The Social Anatomy of An Agricultural Community, Research Bulletin in Agricultural experiment Station
University of Wisconsin, Madison, 34
- 11 Jefferson, M. (1939), The Law of Primate City, Geog. Rev. 39, 226 - 232
- 12 Mayfield, R C. (1967), A Central Place Hierarchy in Northern India, Quantitative Geography Pf.1 Economics and Cultural Topics, Illinois, 120 - 166
13. Misra K.K. (1981) System of Service Centres in Hamirpur District, U P , India, unpublished Ph.D. thesis, Bundelkhand University, Jhansi.
14. Smalls, A.W. (1944), The Urban Hierarchy of England and Wales Geography, vol. 29, pp 41-51
15. Singh, G. (1973), Service Centres : Their Function and Hierarchy, Ambala District Punjab, India, unpublished thesis, Cincinnati University U.S A.
16. Von Thunen, H (1826), Deriso-lierte state in Beziehung Hug landwirts chaft and National Konomic, Rostock Translated by Warteburgh C M As Von Thunen's Isolated State, London Oxford University Press.

16. Woodcock, R C and Bailey M J (1928), Quantitative Geography, Eastover Macdonald and Evans

अध्याय 5

सामाजिक - आर्थिक कारक एवं रूपान्तरण

विगत अध्याय में सेवा केन्द्रों की विशेषताओं का अध्ययन किया गया है और उसके सामाजिक व आर्थिक आधारों के परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । प्रस्तुत अध्याय में अधिवास तत्र एव सेवा केन्द्रों में होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारकों का सह - सम्बन्ध स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है ।

इस अध्याय में मुख्य रूप से सामाजिक कारक के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण एवं शिक्षा तथा आर्थिक कारकों के अन्तर्गत जनसंख्या व्यवसाय प्रतिरूप, भूमि उपयोग, कृषि प्रतिरूप इत्यादि का विश्लेषण किया गया है । कुछ सम्बन्धित सकल्पनाओं का परीक्षण भी किया गया है ।

सामाजिक रूपान्तरण

जनसंख्या जोन्स (1981) तथा क्लार्क (1972) ने जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करते हुये स्पष्ट किया है कि समस्त सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का आधार जनसंख्या ही है । जनसंख्या वह सदर्भ बिन्दु है जिससे अन्य समस्त तत्वों का निरीक्षण किया जाता है तथा उन्हें अर्थ प्रदाना किया जाता है । यह समस्त सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में "फोकस" का कार्य करती है । चान्दना (1980) का विचार है किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक व आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पृष्ठि भूमि, ऐतिहासिक घटनाओं तथा राजनैतिक अवधारणाओं की सूचक होती है ।

जनसंख्या वृद्धि अध्ययन क्षेत्र में सर्वप्रथम जनगणना का श्रीगणेश । फरवरी 1869 में हुआ ।

इस गणना में जनपद की जनसंख्या 782,681 आकी गयी । किन्तु जनसंख्या का विधिवत कार्य वर्ष 1901 में प्रारम्भ हो सका । इस जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या 908,105 थी जिसमें 443,994 पुरुष 464,111 महिलाएँ थी । आधुनिकतम (1981) जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या बढ़कर 1,806,833 हो गयी है जिसमें पुरुषों की संख्या

908,050 है । इन आठ दशकों में जनसंख्या लगभग दुगुनी हो गयी है, जैसा कि सारिणी (संख्या 5 1) से स्पष्ट है । 80 वर्षों में 98.9 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट होता है कि वार्षिक वृद्धि दर केवल 1.23 प्रतिशत है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है । किन्तु विभिन्न दशकों की जनसंख्या के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि समान रूप से नहीं हुई है । सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या लगभग सभी दशकों में अधिक रही है । यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अध्ययन क्षेत्र जन प्रवास समस्या से पूर्णतः प्रभावित है । प्रारम्भ से ही गरीबी एवं पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या बड़े बड़े महानगरों बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मध्यम श्रेणी के नगरों - अमृतसर, लुधियाना, कानपुर, लखनऊ इत्यादि की ओर प्रवासित होती रहती है । इस क्षेत्र से कुछ जनसंख्या का प्रवास पूर्वी द्वीप समूह - जावा, सुमात्रा, फिलीपाइन तथा बर्मा (मुख्य रूप से रगून) की ओर भी हुआ (नेविल, 1904) । इस प्रवास के फलस्वरूप पुरुषों की संख्या पूर्ण रूप से प्रभावित हुई क्योंकि प्रवास की प्रक्रिया में पुरुषों का ही योगदान था ।

जनसंख्या वृद्धि के विश्लेषण की दृष्टि से वर्ष 1921 विभाजक रेखा का कार्य करता है, क्योंकि इसके पूर्व हमारे प्रदेश की जनसंख्या में निरन्तर ह्रास हुआ और अध्ययन क्षेत्र उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा । वर्ष 1901 - 21 मुख्य रूप से बीमारी, महामारी, सूखा, बाढ़, अकाल तथा विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों से प्रभावित रहा । जैसा कि (सारिणी 5 2) से स्पष्ट है वर्ष 1901 - 11 तथा 1911 - 21 में अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या में क्रमशः 1.4 तथा 4.91 प्रतिशत ह्रास हुआ । इस ह्रास के मुख्य कारण इन्फ्लुएन्जा, चेचक तथा हैजा जैसी महामारियाँ थी, जिससे समूचा देश प्रभावित हुआ । इन महामारियों के साथ साथ मानसून की असफलता से उत्पन्न अकाल से भी जनसंख्या का ह्रास हुआ, क्योंकि भुखमरी के कारण जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण वर्ग प्रभावित हुआ ।

अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में भी 1921 के बाद से पर्याप्त अन्तर आया । 1921 - 31 में जनपद की जनसंख्या में लगभग 60 प्रतिशत (59.8 प्रतिशत) की वृद्धि

सारिणी सख्या 5.1 : प्रतापगढ जनपद में जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल व्यक्त	दशक की विभिन्न व्यक्त मे	प्रतिशत
1901	443,994	464,111	908,105		
1911	435,152	460,127	895,299	-12806	-1 14
1921	415,491	435,261	850,753	+44527	-4 91
1931	440,051	461,567	901,618	+50866	+5 98
1941	527,429	509,067	1,036,496	+134878	+14 96
1951	542,763	564,042	1,106,805	+70309	-6 78
1961	607,165	642,031	1,252,196	+145,391	+13 14
1971	705,726	716,981	1,422,707	+170,511	+13 62
1981	898,783	908,050	1,806,833	+384126	+27 0

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1951-81

सारिणी सख्या 5.2 अध्ययन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा भारतवर्ष की जनसंख्या वृद्धि की दिशा

वर्ष	प्रतापगढ़ जनपद की जनसंख्या का प्रतिशत	उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत	भारत की जनसंख्या का प्रतिशत
1901			
1911	1 4	-0 07	5 93
1921	-4 91	-3 08	-0 31
1931	+5 98	6 08	11 0
1941	+14 96	13 57	14 22
1951	-6 78	11 83	13 31
1961	+13 14	16 66	21 64
1971	+13 66	19 78	24 80
1981	+27 0	25 59	25 0

स्रोत प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1951-81

हुई । ठीक इसी प्रकार 1931 - 41, 1941 - 51, 1951 - 61, 1961 - 71 तथा 1971 - 81 में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई । इसका मुख्य कारण मृत्युदर में कमी है । साथ ही स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार के कारण महामारी से होने वाली मृत्यु पर नियन्त्रण पा लेने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ा । अध्ययन क्षेत्र ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश तथा सम्पूर्ण देश में मृत्युदर में कमी आई है । जन्मदर बढ़ी है । अस्तु जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है । सारिणी संख्या 5 2 से स्पष्ट है कि (चित्र संख्या 5 1) विगत दशक 1971 - 81 में अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि (27 0 प्रतिशत), प्रदेश (25 59 प्रतिशत) तथा राष्ट्र की वृद्धि (25 0 प्रतिशत) से किंचित अधिक थी ।

वृद्धि - वितरण प्रतिरूप भौगोलिक दृष्टि से यह देखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि लघु प्रादेशिक स्तर पर जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप क्या है । इस दृष्टि से विकास खण्ड स्तर पर कुल जनसंख्या वृद्धि का प्रेक्षण किया जा सकता है । यह सारिणी (संख्या 5 3) 1961 - 71 तथा 1971 - 81 की जनसंख्या वृद्धि दिखाने के साथ साथ विगत दो दशकों (1961 - 81) में विकास खण्ड स्तर पर हुई जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत भी दर्शाती है ।

जिन विकास खण्डों में जनसंख्या वृद्धि 50 प्रतिशत से अधिक है वे विकास खण्ड ऐसे हैं जहाँ पर नगरीय जनसंख्या पाई जाती है । सदर (53 0 प्रतिशत) तथा कुन्डा (54 9 प्रतिशत) विकास खण्ड इसी कोटि में हैं ।

जिन विकास खण्डों में जनसंख्या की वृद्धि 40 से 50 प्रतिशत के बीच हुई है वे मान्धाता (47 0 प्रतिशत), कालाकाकर (46 1 प्रतिशत), बाबागज (40 9 प्रतिशत), बिहार (48 6 प्रतिशत), रामपुर खास (40 3 प्रतिशत), गौरा (43 1 प्रतिशत), शिवगढ़ (44 4 प्रतिशत) तथा आसपुर देवसरा (44 2 प्रतिशत) हैं ।

कुछ ऐसे विकास खण्ड हैं जिसमें जनसंख्या वृद्धि विगत दो दशकों में 30 से 40 प्रतिशत के बीच है । उनमें मगरौरा (39 6 प्रतिशत), सागीपुर (32 5 प्रतिशत), सडवा चन्द्रिका (34 0

सारिणी सख्या 5 3 जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर जनसख्या वृद्धि (प्रतिशत मे)

विकासखण्ड का नाम	1961-71	1971-81	1961-81	20 वर्षों मे औसत वृद्धि
सदर	14 9	33 1	53 1	2 7
लक्ष्मणपुर	12 8	25 0	38 2	1 91
मानधाता	12 9	28 2	47 5	2 4
स0 चन्द्रिका	10 2	21 6	34 0	1 7
सागीपुर	27 6	20 9	32 5	1 6
कुन्डा	24 0	25 0	54 9	2 7
कालाकाकर	13 8	28 3	46 1	2 3
बाबागज	13 4	28 2	40 9	2 1
बिहार	14 7	29 6	48 6	2 4
रामपुरखास	9 3	28 4	40 3	2 0
पट्टी	15 3	28 1	47 7	2 4
गौरा	15 6	23 8	43 1	2 2
शिवगढ	12 1	26 1	41 4	2 1
मगरौरा	12 5	24 1	39 6	2 0
आसपुर देवसरा	14 32	26 1	44 2	2 2

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961, 1971
जिला साख्यकी पत्रिका, 1984

प्रतिशत) तथा लक्ष्मणपुर (38.2 प्रतिशत) है ।

विगत दो दशकों में (1961 - 81) में अध्ययन क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि 2.2 प्रतिशत थी । जिन विकास खण्डों में वार्षिक दर इससे अधिक थी वे सदर, मानघाता, कालाकाकर, बिहार तथा पट्टी है । आसपुर देवसरा तथा गौरा की वृद्धि दर क्षेत्र के वृद्धि दर के बराबर है । मगरौरा, रामपुरखास, बाबागज, सागीपुर, कुन्डा, सडका चन्द्रिका तथा लक्ष्मणपुर की विकास दर क्षेत्र के विकास दर से कम है । विकास खण्ड स्तर पर वृद्धि दर चित्र 5.2 के माध्यम से प्रदर्शित की गयी है ।

ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि का (सारणी संख्या 5.4) अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सदर, कुन्डा, पट्टी, सडका चन्द्रिका और कालाकाकर में जो वृद्धि में अधिकता है वह नगरीय जनसंख्या के कारण है । ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि अधिकांश विकासखण्ड में समान है ।

नगरीकरण की प्रवृत्ति नगरीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों का द्योतक है । अनेक विद्वान तो यह मानते हैं कि नगरीकरण की तीव्रता विकास का परिचायक है (मिश्रा, 1984) ।

जब किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या का केन्द्रीकरण होने लगता है और अकृषिकृत कार्यों में वृद्धि होने लगती है तथा जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर आश्रित हो जाता है तो उसे नगरीकरण कहते हैं । उल्लेखनीय है कि भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात् इस प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि हुई है । इसके कई सामाजिक - आर्थिक कारण हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की कमी, शिक्षा में वृद्धि, भूमि का असमान वितरण तथा नगर एवं देहात की असमान मजदूरी प्रमुख हैं । क्षेत्र विशेष की आर्थिक प्रगति मुख्य रूप से औद्योगीकरण, वाणिज्यिक व्यापार के अवसरों में वृद्धि तथा यातायात के साधनों की सुगमता भी नगरीकरण की प्रवृत्ति को बल प्रदान करती है ।

अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण की प्रक्रिया आधुनिक है । जैसा कि सारणी संख्या 5.5 से स्पष्ट

**सारिणी सख्या 5.4 . जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर
ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि(प्रतिशत मे)**

विकासखण्ड का नाम	1961-71	1971-81	1961-81	
सदर,13 3	8 9	21 0	1 1	
लक्ष्मणपुर	12 8	25 0	38 2	1 9
मानधाता	12 9	28 2	47 5	2 4
सडवा चन्द्रिका	12 6	16 4	28 3	1 4
सागीपुर	13 5	20 9	32 5	1 9
कुन्डा	14 0	15 3	43 0	2 2
कालाकाकर	13 5	17 7	34 1	1 7
बाबागज	13 4	28 2	40 9	2 1
बिहार	13 8	29 6	48 6	2 4
रामपुरखास	14 1	28 4	40 3	2 0
पट्टी	13 2	20 5	38 9	1 9
गौरा	13 1	23 8	43 1	2 2
शिवगढ	12 3	26 1	41 4	2 1
मगरौरा	14 1	24 0	39 6	2 0
आसपुर देवसरा	14 3	26 1	44 2	2 2
जनपद	13 32	22 6		

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961, 1971
जिला साख्यकी पत्रिका, 1984

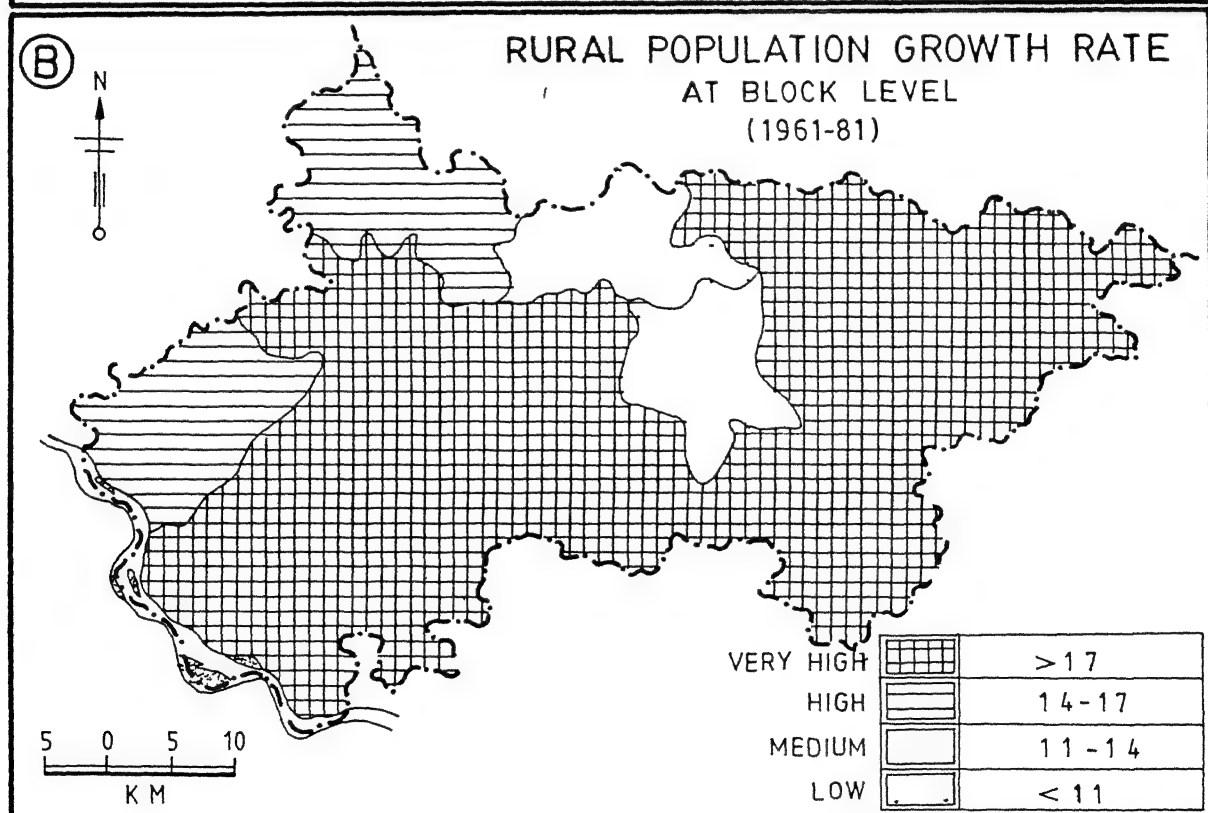
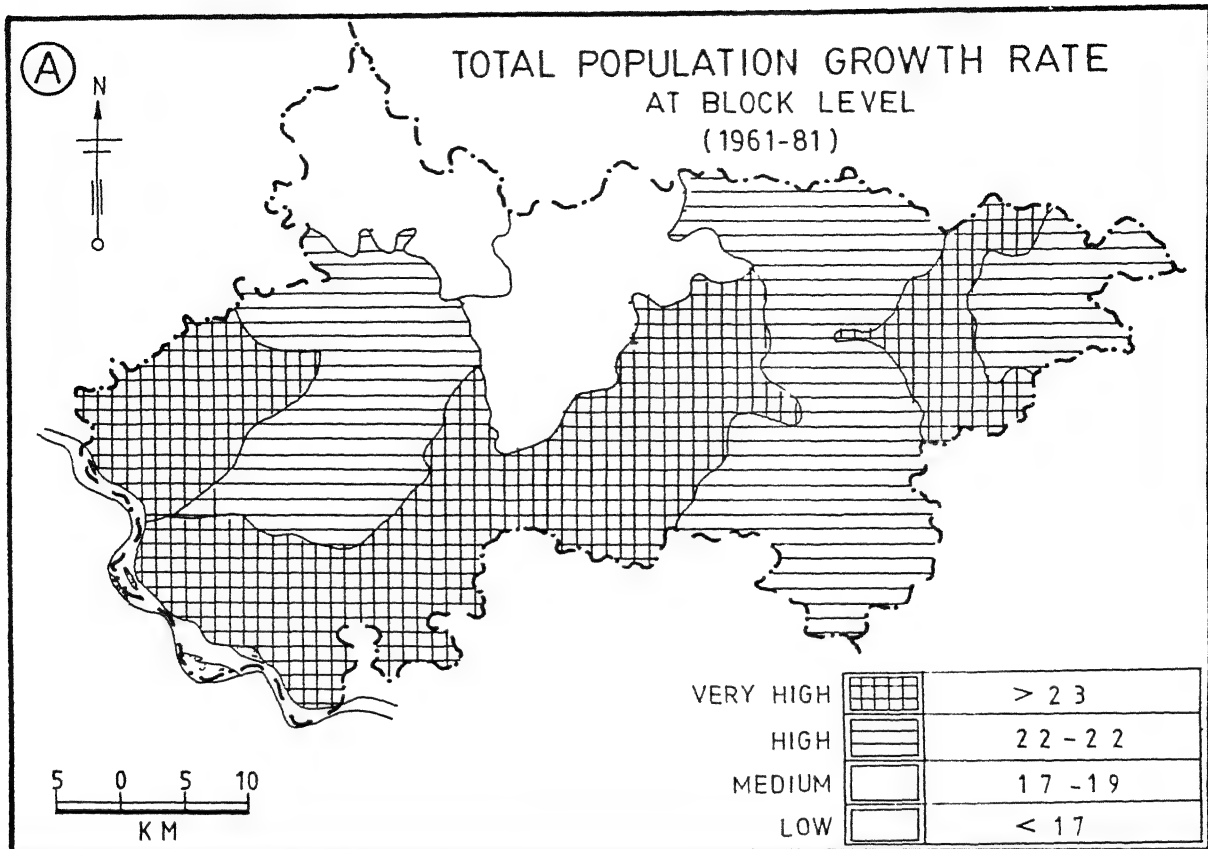


Fig 52

**सारिणी संख्या 5 5 . प्रतापगढ़ जनपद में ग्रामीण तथा नगरीय
जनसंख्या की वृद्धि (प्रतिशत में)**

वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या
1901	-	-
1911	- 1 2	- 21 6
1921	- 5 1	16 5
1931	5 8	28 6
1941	14 7	35 9
1951	6 7	17 1
1961	12 7	42 4
1971	13 3	30 4
1981	23 0	225 7

स्रोत भारतीय जनगणना 1961, 1971, 1981

है कि सन् 1951 - 61 में नगरीय आबादी में 42.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा 1961 - 71 में यह वृद्धि 30.4 प्रतिशत रही है। वास्तव में 1961 तथा 1971 में केवल बेला प्रतापगढ़ (जो कि जिला मुख्यालय है) ही मात्र एक नगर था। इसका मुख्य कारण यह है कि सन् 1961 में नगरीय परिभाषा को बहुत अधिक वैज्ञानिक बना दिया गया। फलस्वरूप मानिकपुर, कटरा मेदनीगंज तथा कसबा प्रतापगढ़ जैसे छोटे नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवासों की श्रेणी में जा मिले। इस प्रकार 1961 - 71 में केवल एक ही नगरीय अधिवास था। सन् 1981 में पुनः 6 नये अधिवासों के नगरीय अधिवासों की श्रेणी में आ जाने के कारण नगरीय जनसंख्या में 225 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। नगरीकरण की दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है क्योंकि 1901 से 1971 तक नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का केवल 2.0 प्रतिशत या उसके आस पास ही रही है। किन्तु 1981 की जनगणना में नये नगरीय अधिवासों के जुड़ जाने से तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात के अन्तर में कुछ कमी आयी है तथा वर्तमान में नगरीय जनसंख्या का योगदान कुल जनसंख्या का 5.0 प्रतिशत है। सारिणी संख्या 5.6 में अध्ययन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा भारतवर्ष के विभिन्न दशकों में ग्रामीण नगरीय अनुपात को प्रस्तुत किया गया है। इस सारिणी के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रदेश और देश की तुलना में अध्ययन क्षेत्र में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का योगदान बहुत कम है। देश की नगरीय आबादी लगभग 24 प्रतिशत तथा प्रदेश में 18 प्रतिशत है जबकि प्रतापगढ़ जनपद में यह केवल 5 प्रतिशत है।

साक्षरता साक्षरता जनसंख्या की गुणात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है तथा सामाजिक परिवर्तनों के मूल्यांकन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है (चान्दना 1980)। जनसंख्या के साक्षरता अनुपात की वृद्धि जहाँ एक ओर सामाजिक परिवर्तन को इंगित करती है वहीं पर दूसरी ओर इससे आर्थिक परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ता है। साक्षरता के साथ दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है। जीवन मूल्य में बदलाव होने लगता है तथा जनसंख्या की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है। यदि हम 1901 - 81 के आँकड़ों पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट होगा कि साक्षरता के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर सतत वृद्धि हो रही है। साक्षरता का सबसे

संरणी 5 6 प्रतापगढ जनपद मे ग्रामीण एव नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत

वर्ष	प्रतापगढ जनपद		उत्तर प्रदेश		भारत	
	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय
1901	97 9	2 1	88 9	11 1	89 2	10 6
1911	98 1	1 9	89 8	10 2	89 7	10 3
1921	98 1	1 9	89 4	10 6	88 8	11 2
1931	97 9	2 1	88 8	11 2	88 0	12 0
1941	97 7	2 3	87 4	12 4	86 1	13 9
1951	96 6	2 4	86 4	13 6	82 7	17 3
1961	98 3	1 7	87 2	12 8	82 0	18 0
1971	98 1	1 9	86 0	14 0	80 1	19 9
1981	94 9	5 1	82 0	18 0	76 3	23 73

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961
भारतीय जनगणना, 1961, 1971, 1981

सारिणी संख्या 5 7 प्रतापगढ़ जनपद में साक्षरता का तुलनात्मक स्वरूप

प्रतापगढ़ जनपद				उत्तर प्रदेश				भारत			
पुरुष	स्त्री	कुल		पुरुष	स्त्री	कुल		पुरुष	स्त्री	कुल	
1901	61	01	31	-	-	-	983	060	535		
1951	146	12	76	-	-	-	2490	793	1667		
1961	248	32	137	-	-	-	3444	1295	240		
1971	312	62	185	315	106	217	3945	1869	295		
1981	389	88	238	3876	140	272	4674	2488	362		

स्रोत प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961, 1971, 1981

सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश 1986

सारणी सख्या 5 8 प्रतापगढ जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत (ग्रामीण)

विकास खण्ड का नाम	1961			1971			1981		
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
सदर	17 4	2 7	20 0	37 1	8 9	23 1	45 8	13 0	29 4
लक्ष्मणपुर	13 6	1 5	15 2	34 0	5 4	19 2	40 5	7 5	23 7
मानधाता	12 8	1 6	14 3	34 7	6 4	20 1	42 1	8 5	25 0
स0 चन्द्रिका	12 6	1 6	14 2	35 1	5 4	19 6	42 6	12 9	25 0
सागीपुर	11 4	1 6	13 0	26 1	3 9	15 0	33 3	3 3	19 3
कुण्डा	9 8	1 5	11 3	28 0	6 8	17 5	33 1	12 2	22 7
कालाकाकर	9 2	0 8	10 4	23 4	4 7	14 3	45 1	4 9	25 2
बाबागज	9 9	1 3	11 21	24 9	4 3	14 5	21 8	6 0	18 8
बिहार	10 6	0 9	11 6	28 7	5 3	16 9	35 3	10 4	23 0
रामपुरखास	9 1	0 8	9 9	24 0	3 5	13 7	28 7	5 2	17 0
पट्टी	11 8	0 7	13 2	31 5	6 2	18 9	40 9	7 0	23 6
गौरा	11 5	1 0	12 5	31 6	4 2	17 7	371	6 6	21 6
शिवगढ	13 1	1 5	9 7	31 8	5 1	20 0	41 2	7 8	24 1
मगरोरा	12 3	1 3	12 6	36 4	5 4	18 8	37 0	6 8	21 8
आसपुर देक्सरा	11 7	1 5	13 2	32 0	6 2	19 2	39 9	7 2	23 3

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961, 1971, 1981

महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि हो रही है । अध्ययन क्षेत्र में 1901 - 81 में साक्षरता 31 प्रतिशत से 23.8 प्रतिशत हो गयी । किन्तु यह वृद्धि प्रदेश एवं देश की तुलना में कम है । स्त्रियों एवं पुरुषों की साक्षरता का अन्तर भी इसकी पुष्टि करता है । पुरुषों की साक्षरता 1901 - 81 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 39.0 प्रतिशत हो गयी जबकि स्त्रियों की साक्षरता 0 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत ही हुयी है । स्त्रियों की साक्षरता का यह अनुपात प्रदेश (14.0 प्रतिशत) और राष्ट्र (25.0 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है । साक्षरता में वास्तविक वृद्धि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुई । जबकि अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों पर शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की गयी ।

अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता अनुपात का वितरण प्रतिरूप मानचित्र (5.3) द्वारा प्रदर्शित किया गया है । इस मानचित्र से स्पष्ट है कि सदर विकास खण्ड में जिला मुख्यालय होने के कारण साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है । इस मानचित्र में पुरुषों एवं स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत का वितरण भी अलग अलग मानचित्रों में दिखाया गया है । पुरुषों की साक्षरता के अनुपात के वितरण में अधिक विषमता नहीं पायी जाती है । पश्चिम में रामपुरखास और बाबागंज विकास खण्डों को छोड़कर शेष अन्य विकासखण्डों में वितरण प्रतिरूप लगभग समान है । स्त्रियों की साक्षरता के वितरण को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस मानचित्र से स्पष्ट है कि महिलाओं में साक्षरता की बहुत कमी है । जबकि महिलाओं की साक्षरता को सामाजिक विकास तथा विकास स्तर के उन्नयन का प्रतीक माना जाता है । महिलाओं की साक्षरता का औसत 7.9 प्रतिशत है । 15 विकास खण्डों में से दस विकासखण्डों में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत इस औसत से भी कम है । मानधाता तथा बिहार विकास खण्डों में स्त्रियों की साक्षरता 7.9 तथा 10.7 के बीच है । केवल तीन ऐसे विकासखण्ड हैं जिनकी साक्षरता 10.7 से 13.6 प्रतिशत के बीच है । ये विकासखण्ड कालाकाकर, सदर तथा सडवा चन्द्रिका हैं ।

महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि हो रही है । अध्ययन क्षेत्र में 1901 - 81 में साक्षरता 31 प्रतिशत से 23.8 प्रतिशत हो गयी । किन्तु यह वृद्धि प्रदेश एवं देश की तुलना में कम है । स्त्रियों एवं पुरुषों की साक्षरता का अनंतर भी इसकी पुष्टि करता है । पुरुषों की साक्षरता 1901 - 81 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 39.0 प्रतिशत हो गयी जबकि स्त्रियों की साक्षरता 0.1 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत ही हुयी है । स्त्रियों की साक्षरता का यह अनुपात प्रदेश (14.0 प्रतिशत) और राष्ट्र (25.0 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है । साक्षरता में वास्तविक वृद्धि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुई । जबकि अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों पर शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की गयी ।

अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता अनुपात का वितरण प्रतिरूप मानचित्र (5.3) द्वारा प्रदर्शित किया गया है । इस मानचित्र से स्पष्ट है कि सदर विकास खण्ड में जिला मुख्यालय होने के कारण साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है । इस मानचित्र में पुरुषों एवं स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत का वितरण भी अलग अलग मानचित्रों में दिखाया गया है । पुरुषों की साक्षरता के अनुपात के वितरण में अधिक विषमता नहीं पायी जाती है । पश्चिम में रामपुरखास और बाबागंज विकास खण्डों को छोड़कर शेष अन्य विकासखण्डों में वितरण प्रतिरूप लगभग समान है । स्त्रियों की साक्षरता के वितरण को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस मानचित्र से स्पष्ट है कि महिलाओं में साक्षरता की बहुत कमी है । जबकि महिलाओं की साक्षरता को सामाजिक विकास तथा विकास स्तर के उन्नयन का प्रतीक माना जाता है । महिलाओं की साक्षरता का औसत 7.9 प्रतिशत है । 15 विकास खण्डों में से दस विकासखण्डों में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत इस औसत से भी कम है । मानघाता तथा बिहार विकास खण्डों में स्त्रियों की साक्षरता 7.9 तथा 10.7 के बीच है । केवल तीन ऐसे विकासखण्ड हैं जिनकी साक्षरता 10.7 से 13.6 प्रतिशत के बीच है । ये विकासखण्ड कालाकाकर, सदर तथा सडवा चन्द्रिका हैं ।

आर्थिक रूपान्तरण

व्यवसायिक संरचना कार्यरत जनसंख्या के व्यवसायिक वर्गों का विश्लेषण कर किसी क्षेत्र का आर्थिक आधार सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। सामान्यतः यदि किसी क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है तो जनसंख्या की निर्भरता कम होती है और प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक स्तर में निरन्तर वृद्धि होती है। यह महत्वपूर्ण है कि जनगणना के विभिन्न दशकों में कार्यरत जनसंख्या की परिभाषा तथा व्यवसायिक संरचना की परिभाषा में बदलाव होता रहा है। यही कारण है कि, किन्हीं दो दशकों की व्यवसायिक संरचना और कार्यरत जनसंख्या का तुलनात्मक विश्लेषण सम्भव नहीं हो पाता। वर्ष 1981 में व्यवसायिक संरचना के विश्लेषण के लिये मुख्य रूप से जनसंख्या को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है

1. मुख्य कर्मकर
2. सीमान्त कर्मकर
3. बेरोजगार

एक व्यक्ति यदि वर्ष के अधिकांश समय में (कम से कम 183 दिन) किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ था तो उसे मुख्य कर्मकर माना गया। किन्तु एक व्यक्ति जो वर्ष के कुछ महीने तक ही कार्य में लगा था उसे सीमान्त कर्मकर माना गया तथा वह व्यक्ति जो वर्ष भर किसी भी आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया में नहीं रह पाया है उसे कार्य न करने वाले की श्रेणी में रखा गया है।

कार्य की परिभाषा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आर्थिक उत्पादन को कार्य माना गया है। यह शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, अथवा शारीरिक व मानसिक दोनों ही हो सकता है। कार्य की सीमा के अन्तर्गत केवल वास्तविक कार्य को ही नहीं अपितु प्रभावी निरीक्षण एवं निदेशन को भी इसके अन्तर्गत रखा गया है। कार्यरत जनसंख्या को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है -

1. कृषक

- 2 कृषि श्रमिक
- 3 पारिवारिक उद्योग एव
- 4 अन्य कर्मकर

प्रस्तुत विश्लेषण में कृषक तथा कृषि श्रमिकों को प्राथमिक व्यवसाय के अन्तर्गत रखा गया है तथा पारिवारिक उद्योग एव अन्य कार्यों में लगी हुई जनसंख्या को क्रमशः सुविधा के अनुसार द्वितीयक एव तृतीयक वर्गों के अन्तर्गत रखा गया है। इन तीनों वर्गों के अन्तर्गत प्रतापगढ़ जनपद की कार्यरत जनसंख्या को सारणी संख्या 5.9 में प्रस्तुत किया गया है। इस सारणी से अध्ययन क्षेत्र की कार्यरत जनसंख्या का तीन दशकों (1961 - 81) का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। इस सारणी से स्पष्ट है कि कृषि ही आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार है क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। यद्यपि विगत दशकों की तुलना में कृषि में कार्यरत जनसंख्या में ह्रास हुआ है, क्योंकि वर्ष 1961 में इसके अन्तर्गत 87.0 प्रतिशत लोग लगे हुये थे। जबकि वर्ष 1981 में यह प्रतिशत घटकर 84.5 प्रतिशत हो गया है। किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि में लगी जनसंख्या के अनुपात का ह्रास द्वितीयक व्यवसाय में नहीं परिलक्षित होता है। जैसा कि स्पष्ट है कि द्वितीयक व्यवसाय मूलतः औद्योगिक है, किन्तु इसमें केवल 3.0 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि द्वितीयक व्यवसाय के अनुपात में भी ह्रास हुआ है क्योंकि वर्ष 1961 - 81 में यह 6.2 प्रतिशत से घट कर केवल 2.9 प्रतिशत रह गया है। स्पष्टतया औद्योगीकरण की प्रवृत्ति को उचित महत्व नहीं प्राप्त हुआ। प्राथमिक व्यवसाय का ह्रास तृतीयक व्यवसाय की वृद्धि में परिलक्षित होता है। यह वे कर्मकर हैं जो मुख्य रूप से औपचारिक और अनौपचारिक व्यापार, वाणिज्य, सेवा तथा यातायात सम्बन्धित कार्यों में कार्यरत हैं। विगत तीन दशकों में तृतीयक व्यवसाय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 1961 में केवल 6.60 प्रतिशत लोग अन्य सेवाओं (तृतीयक व्यवसाय) में लगे थे किन्तु वर्ष 1981 में यह अनुपात दुगुने से अधिक (13.7 प्रतिशत) हो गया।

विकास खण्ड स्तर पर जनसंख्या के व्यवसायिक संरचना का वितरण सारणी संख्या 5.10 में

संश्लेषणी सङ्ख्या 5 9 प्रतापगढ जनपद मे व्यवसायिक वर्गों मे कार्यरत
जनसङ्ख्या का प्रतिशत

व्यावसायिक वर्ग	1961	1971	1981
प्रथमिक व्यावसाय	87 1	87 6	84 5
द्वितीयक व्यावसाय	6 3	4 5	2 9
तृतीय व्यावसाय	6 7	7 9	13 7

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1961-81

सारिणी सख्या 5 10 जनपद मे विकास खण्डवार जनसख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण (प्रतिशत)

विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक क्रियाये			द्वितीयक क्रियाये			तृतीयक क्रियाये		
	1961	1971	1981	1961	1971	1981	1961	1971	1981
मदर	76 6	75 6	84 0	7 6	7 9	3 3	15 8	16 5	12 7
लक्ष्मणपुर	88 1	89 3	88 5	5 9	4 5	2 7	6 0	6 2	8 8
मानधाता	90 0	90 8	87 5	5 6	4 0	4 1	4 4	5 2	8 4
स0 चन्द्रिका	87 9	88 8	89 4	6 7	3 9	2 2	5 4	7 2	8 4
सागीपुर	90 0	93 9	92 9	5 0	2 6	2 6	4 2	3 5	4 5
कृण्डा	85 1	87 4	90 0	7 5	4 7	2 1	7 4	7 9	6 9
कालाकाकर	81 7	890 4	89 2	8 6	4 3	3 6	9 7	5 3	7 2
बाबागज	88 9	91 1	91 7	5 6	3 8	2 0	5 4	5 1	5 1
बिहार	89 3	90 9	86 8	6 5	4 5	3 5	4 2	4 6	9 7
रामपुरखास	89 4	91 6	92 9	5 5	3 3	2 0	4 8	5 1	5 1
पट्टी	90 0	88 2	91 6	5 0	4 3	1 7	5 0	7 5	6 7
गौरा	92 8	88 5	88 4	4 1	4 3	3 3	3 4	7 5	8 3
शिवगढ	89 8	85 4	86 0	4 7	4 1	2 1	5 5	10 5	11 9
मगौरा	90 4	89 2	89 1	5 0	3 2	2 5	4 6	7 6	8 4
आसपुर देवसरा	90 6	93 2	91 7	4 3	2 7	0 9	3 1	5 1	7 4

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1961-81

प्रस्तुत किया गया है । यह सारणी वर्ष 1961 तथा 1981 की स्थिति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है । इस सारणी से जहाँ प्रारम्भिक व्यवसाय अथवा कृषि का वर्चस्व, आर्थिक आधार के रूप में स्पष्ट है, वहीं दूसरी ओर द्वितीयक व्यवसाय (पारिवारिक एवं अन्य उद्योग) की कमी तथा तृतीयक व्यवसाय में अपेक्षाकृत अभिवृद्धि भी दिखाई पड़ती है । विकासखण्ड स्तर पर व्यवसायिक संरचना के प्रतिरूप का चित्र सख्या 5.4 तथा 5.5 द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यह दोनों रेखाचित्र वर्ष 1961 तथा 1981 की स्थिति को विकास खण्ड स्तर पर दर्शाने का प्रयत्न करते हैं । 1961 तथा 1981 की व्यवसायिक संरचना में दो महत्वपूर्ण अन्तर स्पष्ट दिखायी देते हैं

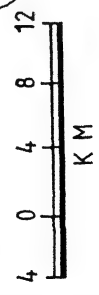
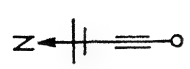
1. प्रत्येक विकासखण्ड में द्वितीयक प्रकार के व्यवसाय में लगी जनसंख्या के अनुपात में ह्रास हुआ है ।

2. तृतीयक प्रकार के व्यवसाय में अपेक्षाकृत आनुपातिक वृद्धि हुई है । तृतीयक व्यवसाय पर निर्भरता 4 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के मध्य है । इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में विविधता की प्रक्रिया प्रारम्भ है किन्तु गति बहुत धीमी है । विविधता की इस प्रक्रिया में तृतीयक प्रकार के व्यवसाय अधिक व महत्वपूर्ण होंगे । सम्भवतया इनसे ही नगरीकरण की प्रक्रिया को आधार मिलेगा (रजा, 1981 तथा मिश्रा, 1990) ।

भूमि उपयोग - व्यवसायिक संरचना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषि अध्ययन क्षेत्र का मुख्य आर्थिक आधार है । इस आधार को स्पष्ट करने के लिये कृषि उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है ।

मानव सभ्यता के आरम्भ से ही भूमि का उपयोग कृषि उत्पादन के लिये होता रहा है । वास्तव में यह सबसे बड़ी प्राकृतिक सम्पदा है । भूगोल विशेषज्ञों ने भूमि उपयोग के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण कर इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया है । इस परम्परा में कई पाश्चात्य एवं भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने योगदान किया है । इनमें प्रो० इनायदी (1964), प्रो० स्टैम्प (1962) तथा प्रो० शफी (1960, 1972) के कार्य विशेष रूप

PRATAPGARH DISTRICT SECTORAL COMPOSITION OF WORKERS AT BLOCK LEVEL (1961)



	PRIMARY WORKERS
	SECONDARY WORKERS
	TERTIARY WORKERS

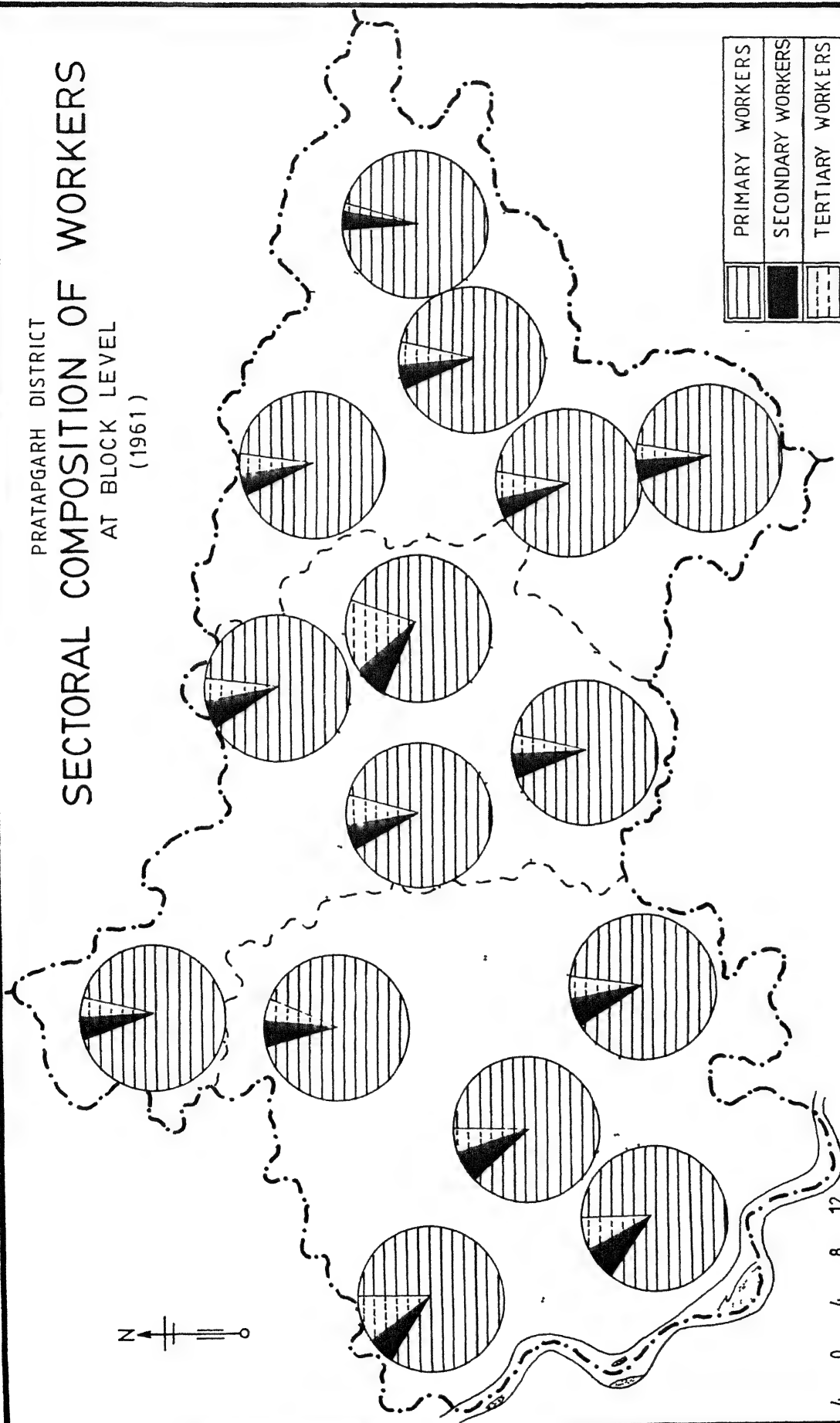
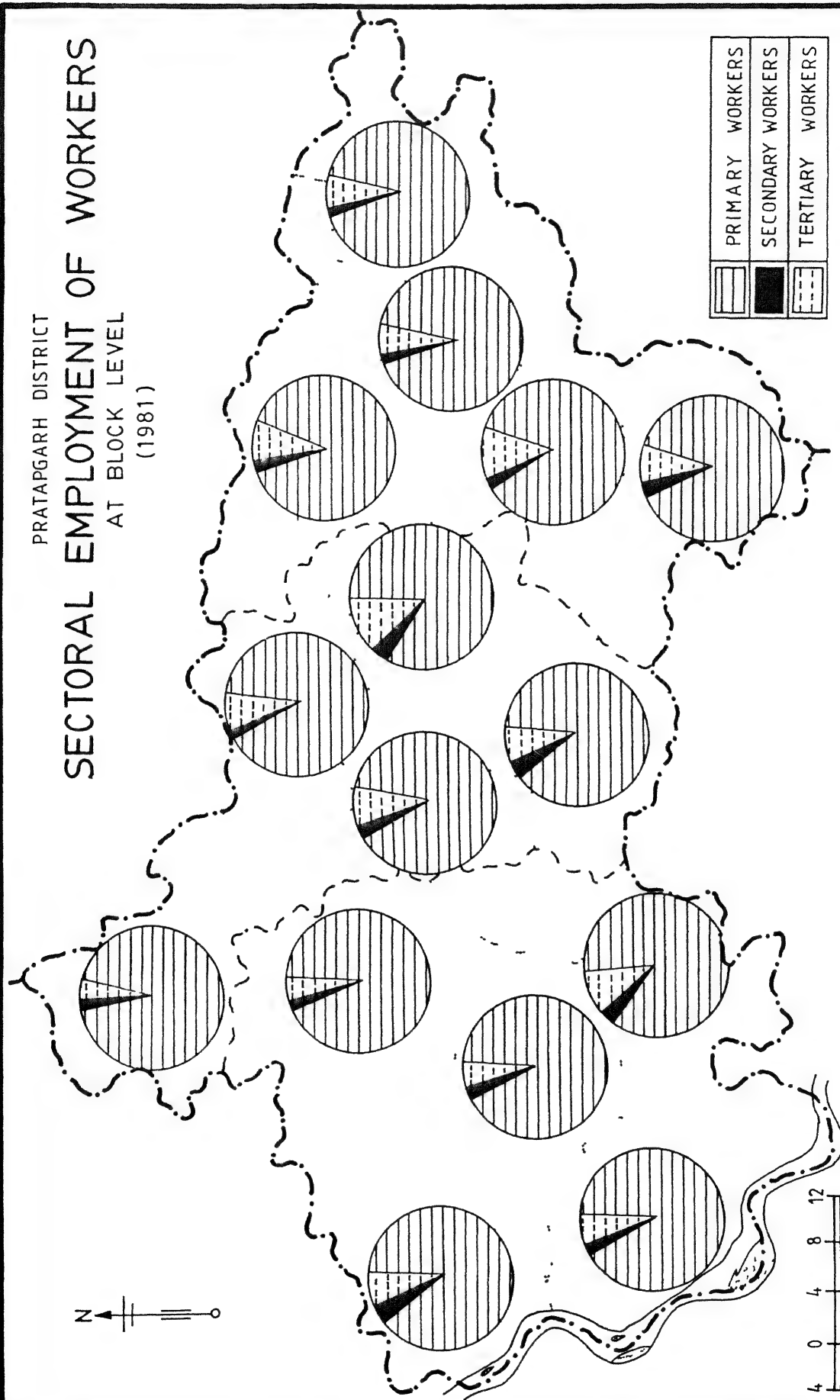


Fig 54

PRATAPGARH DISTRICT

SECTORAL EMPLOYMENT OF WORKERS AT BLOCK LEVEL (1981)



से उल्लेखनीय है ।

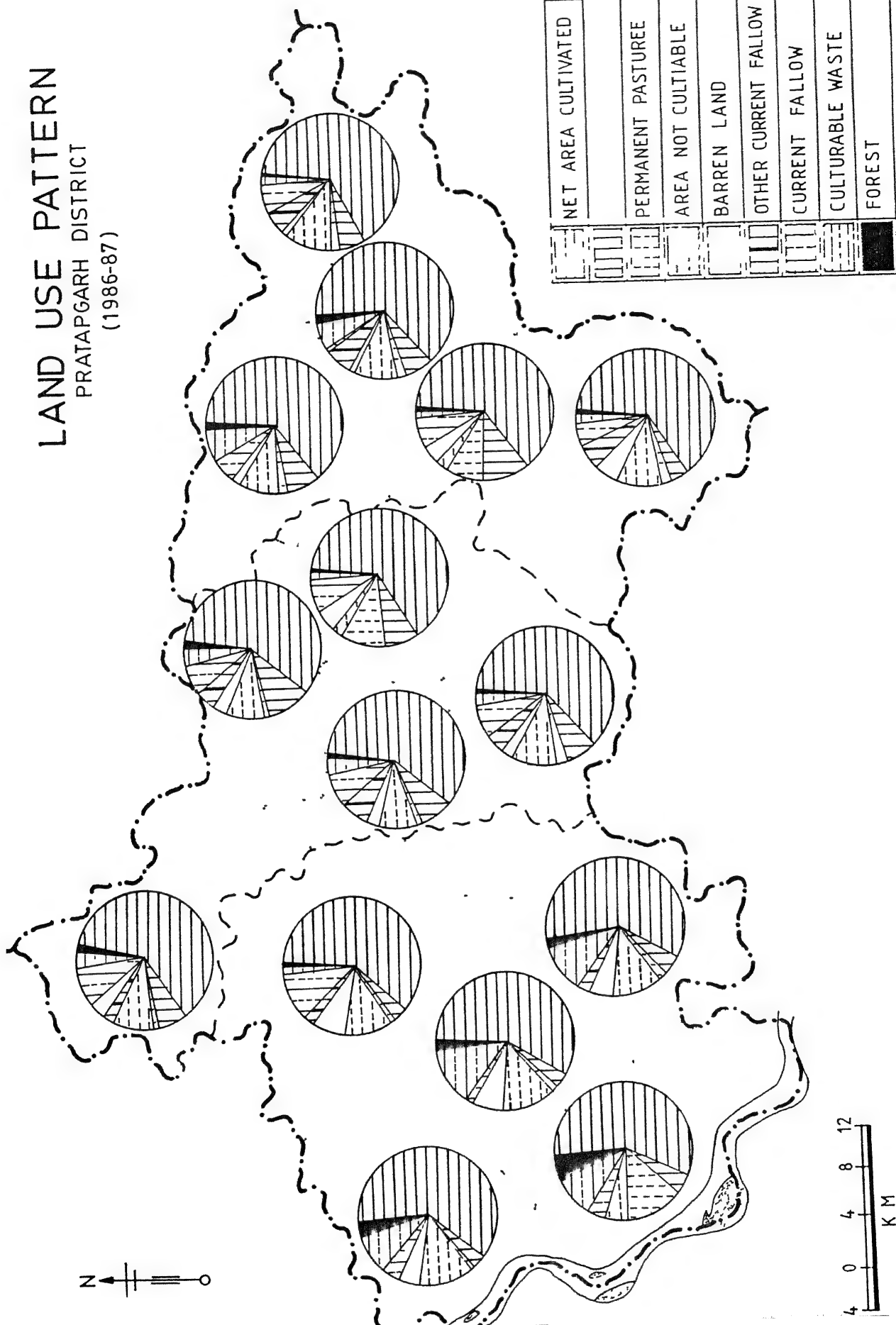
अध्ययन क्षेत्र में स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात् के भूमि उपयोग का प्रतिरूप सारिणी सख्या 5 11 में दिया गया है । यद्यपि भूमि उपयोग के वर्गीकरण में किंचित भिन्नता के कारण पूर्ण रूप से तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, किन्तु फिर भी इससे महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं । सारिणी सख्या 5 11 से स्पष्ट है कि वन के क्षेत्रों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वर्ष 1961 से 1986 - 87 तक वन का क्षेत्रफल केवल 0 1 प्रतिशत ही बना रहा है । किन्तु परती क्षेत्र में ह्रास हुआ है । शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्ष 1901 में 56 2 प्रतिशत, वर्ष 1951 में 61 7 प्रतिशत तथा 1981 में 64 7 प्रतिशत था । तात्पर्य यह है कि शुद्ध बोये गये क्षेत्र में वृद्धि हुई है । यह उल्लेखनीय है कि सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । उदाहरण के लिए 1951 में सिंचित क्षेत्र केवल 38 0 प्रतिशत था जबकि सन् 1961 में यह बढ़ कर 40 0 प्रतिशत हो गया था तथा 1986 - 87 में सिंचित क्षेत्र 62 0 प्रतिशत तक पहुँच गया । इसी प्रकार एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । वर्ष 1961 में एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 24 3 प्रतिशत था जो 1986 - 87 में बढ़ कर 38 0 प्रतिशत हो गया । उसका महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पादन पर पड़ा है और उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

वर्ष 1986 - 87 के भूमि उपभोग का प्रतिरूप विकासखण्ड स्तर पर देखा गया है (सारिणी सख्या 5 12 तथा चित्र सख्या 5 6) । इस सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद में वन का अभाव है, किन्तु ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि अधिक है । जिन विकास खण्डों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 60 0 प्रतिशत से अधिक है, उनमें आसपुर देवसरा (67 4 प्रतिशत), सागीपुर (66 8 प्रतिशत), मगरौरा (66 3 प्रतिशत), पट्टी (66 1 प्रतिशत), मानधाता (66 0 प्रतिशत), सदर (65 4 प्रतिशत), सड़वा चन्द्रिका (63 0 प्रतिशत), गौरा (62 3 प्रतिशत), लक्ष्मणपुर (60 8 प्रतिशत) तथा शिवगढ़ (60 4 प्रतिशत) है । किन्तु कालाकाकर (59 7 प्रतिशत), रामपुरखास (59 3 प्रतिशत), कुन्डा (59 1 प्रतिशत), बाबागज (58 1 प्रतिशत) तथा बिहार (56 3 प्रतिशत) विकास खण्डों में शुद्ध बोये गये क्षेत्र का क्षेत्रफल 60 प्रतिशत से कम है, जो

LAND USE PATTERN

PRATAPGARH DISTRICT

(1986-87)



NET AREA CULTIVATED	
PERMANENT PASTURE	
AREA NOT CULTIVABLE	
BARREN LAND	
OTHER CURRENT FALLOW	
CURRENT FALLOW	
CULTURABLE WASTE	
FOREST	

अध्ययन क्षेत्र के औसत उपयोग में कम है । इसका मुख्य कारण यह है कि इन विकास चरणों में ऊसर तथा बजर भूमि अधिक है तथा सिंचाई के साधन अपेक्षाकृत कम हैं ।

फसल प्रतिरूप - विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र का विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे खाद्यान्न तथा मुद्रादायिनी फसलों के महत्व का स्पष्टीकरण होता है । इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में जीविकोपार्जन की कृषि की जाती है अथवा विपणन कृषि पर विशेष बल दिया जाता है । इस तथ्य विश्लेषण के लिये सारिणी सख्या 5 13 तथा चित्र सख्या 5 7 को, देखा जा सकता है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग प्रारम्भ से ही खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत ही रहा है । किन्तु कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन विगत 25 वर्षों में हुये हैं । स्वतंत्रता से पूर्व मुख्य रूप से मोटे अनाज वाली फसलें -- ज्वार, बाजरा, जौ, चना जैसी फसलें अधिक महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि इसके अन्तर्गत अधिकांश भाग लगा था । किन्तु 1961 एव 1986 - 87 के आँकड़ों से स्पष्ट है कि मोटे अनाज वाली फसलों की तुलना में धान एव गेहूँ की फसलों का महत्व बढ़ा है । सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के कारण सम्भवतः धान की तुलना में गेहूँ के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई । वर्ष 1961 में धान के अन्तर्गत 26.6 प्रतिशत तथा गेहूँ के अन्तर्गत 9.5 प्रतिशत क्षेत्र लगा था । जबकि वर्ष 1986 - 87 में धान के अन्तर्गत 33.1 प्रतिशत और गेहूँ के अन्तर्गत 36.3 प्रतिशत भाग लगा था । यह स्पष्ट है कि धान की तुलना में गेहूँ के क्षेत्रफल में तीव्रता से वृद्धि हुई है । वर्ष 1986 - 87 के आँकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि दाल वाली फसलें -- अरहर, चना तथा मटर के उत्पादन पर भी बल दिया जाने लगा है । मुद्रादायिनी फसलों के अन्तर्गत गन्ना, आलू तथा तिलहन प्रमुख हैं । किन्तु जहाँ एक ओर आलू एव तिलहन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, वहीं गन्ना के उत्पादन क्षेत्र में कमी आई है । वर्ष 1961 में गन्ना के अन्तर्गत 1.5 प्रतिशत क्षेत्रफल था जबकि वर्ष 1986 - 87 में यह केवल 0.9 प्रतिशत रह गया । इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ने की खेती विपणन की दृष्टि से लाभकारी नहीं है । जबकि आलू के अन्तर्गत लगा हुआ क्षेत्र वर्ष 1961 तथा वर्ष 1986 - 87 में 0.6 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत हो गया है । तिलहन

सारिणी संख्या 5-13 प्रतापगढ़ जनपद में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल हे०/प्रतिशत

खाद्यान्न की फसलें	1901	1951	1961	1986-87
धान	15155 85 78	66896823 68	77263826 68	109650833 18
गेहूँ	24824810 78	2565888 88	2733789 58	120216836 38
जौ	41421817 88	53917818 58	52237818 18	848682 68
ज्वार	1478086 38	1164084 08	902083 18	594880 68
बाजरा	1121184 88	17044085 88	1919686 68	1673485 08
मक्का	82080 38	217980 78	236380 88	258981 88
अरहर	-	-	-	1688885 18
मूंग उर्द	-	-	-	617182 98
चना	27308811 78	2348588 08	2334688 18	1297684 08
मटर	-	-	-	466681 48
अन्य खाद्यान्न की फसलें	83037835 78	71769824 68	61738821 58	237480 88
कुल खाद्यान्न फसलों का योग	216556893 08	274588894 08	272499894 38	309998893 68
मुद्गदायिनी फसलें				
गन्ना	4923 82 18	4368 81 58	4181 81 58	2819 80 98
आलू	-	1386 80 58	1624 80 68	5441 81 88
तिलहन	1125 80 48	347 80 18	394 80 18	1497 80 58
अन्य मुद्गदायिनी फसलें	10194 84 38	11410 83 98	10067 83 58	1130683 48
कुल मुद्गदायिनी फसलों का योग	17142 87 48	1743185 968	1726685 998	2106386 48
कुल फसलों का योग	237988100 08	2920208100 08	2887648100 08	3310338100 0

स्त्रोत . प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हेण्ड बुक 1961

का क्षेत्र वर्ष 1961 तथा 1986 - 87 में 0.1 प्रतिशत में बढ़ कर 0.5 प्रतिशत हो गया। विगत 26 वर्षों (1961 - 87) में खाद्यान्न के अन्तर्गत लग क्षेत्र की तुलना में मुद्रादायिनी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत लगा हुआ क्षेत्र 94.3 प्रतिशत (1961) से घटकर 93.6 प्रतिशत (1986 - 87) रह गया। और इस बीच मुद्रादायिनी फसलों के अन्तर्गत लगा हुआ क्षेत्र 5.97 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गया। किन्तु फिर भी मुद्रादायिनी फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र की यह वृद्धि नगण्य है।

लघु क्षेत्रीय फसल प्रतिरूप के विश्लेषण के लिये विकास खण्ड स्तर पर वर्ष 1986 - 87 के ऑकड़ों को सारिणी सख्या 5.14 तथा मानचित्र 5.7 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। स्पष्ट है कि सभी विकासखण्डों में धान एवं गेहूँ के अन्तर्गत लगा क्षेत्र अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक है। जिन विकास खण्डों में धान की तुलना में गेहूँ की खेती अधिक हो रही है उनमें सदर, लक्ष्मणपुर, मानधाता, सडवा चन्द्रिका, सागीपुर, कुन्डा, शिवगढ तथा आसपुर देवसरा है। शेष सात विकास खण्डों (कालाकाकर, बाबागज, बिहार, रामपुरखास, पट्टी, गौरा तथा मगरौरा) में धान की खेती अधिक होती है। खाद्यान्न की फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों का महत्व जिन विकासखण्डों में बढ़ा है उनमें सदर, सडवा चन्द्रिका, साँगीपुर, शिवगढ, मानधाता मुख्य है। फसल में विविधता की प्रक्रिया प्रारम्भ होगयी है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

फसल गहनता फसल गहनता शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं सकल बोया गया क्षेत्र का अनुपात होता है। इससे क्षेत्र विशेष के भूमि उपयोग तथा उत्पादकता का स्पष्टीकरण होता है। इसका परिकलन अधोलिखित सूत्र के द्वारा किया जाता है (राम किशोर, 1987)।

$$\text{फसल गहनता} = \frac{\text{स0 बो0 क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बो0 क्षेत्र}} \times 100$$

स0 बो0 - सकल बोया गया

शु0 बो0 - शुद्ध बोया गया क्षेत्र

सरिणी संख्या 5 14 प्रतापगढ जनपद में विकास खण्डवार फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत 1986-87

धान	गेहूँ	जौ	ज्वार	बाजरा	मक्का	अन्य धान	उर्द	मूँग	चना	मटर	अरहर	खद्यान्न			तिलहन	गन्ना	आलू	तम्बाकू	अन्य फसल
												रू	किलो	ग्राम					
सदर	107	289	66	35	138	04	13	22	13	14	125	916	05	03	13	--	--	63	
लक्ष्मणपुर	287	376	34	17	80	00	07	25	08	15	60	941	03	03	06	-	-	38	
मानघाता	288	388	19	11	78	01	10	19	10	14	50	918	03	08	28	00	43		
स0 चन्द्रिका	122	284	56	42	116	01	15	38	08	18	100	596	05	10	18	-	-	71	
सागीपुर	255	35	33	59	48	01	17	52	11	68	21	72	954	05	02	12	-	38	
कुण्डा	310	384	40	12	55	00	03	11	06	48	12	44	925	06	01	13	00	55	
कालाकाकर	407	375	17	14	31	00	04	15	12	13	09	38	935	07	03	16	-	39	
बाबागज	470	404	09	10	09	00	02	10	10	11	09	16	960	05	05	13	00	17	
बिहार	442	395	14	05	20	00	03	17	10	15	13	22	954	03	03	20	00	20	
रामपुर	413	385	19	16	21	00	09	21	15	18	14	30	962	03	04	13	00	18	
पट्टी-	369	365	10	10	28	29	04	06	08	27	18	43	912	07	21	16	-	41	
गौरा	409	368	11	05	25	06	02	09	07	23	13	26	905	04	15	20	-	56	
शिवगढ	166	312	52	13	128	12	10	10	07	78	11	126	925	04	06	22	-	43	
मगौरा	372	357	18	09	39	03	08	09	05	37	35	44	916	06	03	13	-	51	
आसपुर देवसरा	364	388	05	18	08	60	02	08	10	23	07	22	927	03	26	18	-	26	
जनपद	331	363	26	06	50	18	08	18	11	40	14	51	936	05	09	16	00	34	

स्रोत जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 1988

विकसित खण्ड स्तर पर फसल गहनता का तुलनात्मक प्रारम्भ सारिणी 5 15 में प्रस्तुत है । इन दो वर्षों (1974-80 व 1986-87) के फसल गहनता से स्पष्ट है कि केवल सदर विकासखण्ड को छोड़कर शेष अन्य विकासखण्डों में फसलगहनता में पर्याप्त वृद्धि हुई है । दोनों के अन्तर से यह भी प्रतीत होता है कि कुछ विकासखण्डों में उदाहरण के लिये बिहार (27.4 प्रतिशत), आसपुर देवसरा (22.3 प्रतिशत) तथा कालाकाकर (20 प्रतिशत) में फसलगहनता में 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई । लक्ष्मणपुर, पट्टी, गौरा, बाबागंज, मगरौरा, मडवा चन्द्रिका मानधाता तथा कुन्डा विकासखण्डों में फसलगहनता में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है । रामपुरखास तथा शिवगढ़ एवं सागीपुर विकासखण्डों में फसलगहनता की वृद्धि की दर 10 प्रतिशत से कम है केवल सदर विकासखण्ड में ही ऐसा है जहाँ पर फसलगहनता में लगभग 30 प्रतिशत का ह्रास हुआ । सारिणी 5 15 में प्रस्तुत दो विभिन्न वर्षों के फसलगहनता के अन्तर प्रतिशत को मानचित्र पर प्रस्तुत किया गया (चित्र संख्या 5 15) है। जिले के फसल गहनता पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि जनपद स्तर पर फसल गहनता वर्ष 1961 में 124 से बढ़कर 1986-87 में 148 हो गयी है किन्तु फसलगहनता की सीमा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है । फसलगहनता की वृद्धि के लिये सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि अत्यावश्यक है ।

फसलोत्पादन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के अनेक प्रयत्न किये गये जिसमें चावल, गेहूँ, दाल, तिलहन तथा मुद्गादायिनी फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । सारिणी संख्या 5 16 में प्रतापगढ़ जनपद में प्रमुख फसलों के उत्पादन का विवरण प्रस्तुत है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि विगत सात आठ वर्षों में चावल एवं गेहूँ के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई । चावल के उत्पादन में लगभग 60.0 प्रतिशत की वृद्धि तथा गेहूँ के उत्पादन में लगभग 93.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई । किन्तु जौ, ज्वार, बाजरा तथा अन्य खाद्यान्न की फसलों के उत्पादन में गिरावट आई है । स्पष्ट है कि मोटे अनाज वाली फसलों का महत्व कम होता जा रहा है । दालों के उत्पादन में भी कमी आई है । किन्तु उर्द, मूँग तथा मटर के उत्पादन में वृद्धि हुई है । तिलहन

सारिणी सख्या 5 15 प्रतापगढ जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर फसलउहनता

विकासखण्ड का नाम	1979-80	1986-87	अन्तर	अन्तर प्रतिशत
मदर	135	131	-4	2 96
लक्ष्मणपुर	125	144	+19 0	15 2
मानधाता	135	153	+18 0	13 0
सडवा चन्द्रिका	121	134	+13 0	10 74
सर्गीपुर	138	139	+1 0	0 72
कुण्डा	124	137	+13 0	10 48
कालाकाकर	135	162	+27 0	20 0
बाबागज	134	160	+26 0	19 4
बिहार	124	158	+34 0	27 4
रामपुरखास	140	148	+8 0	5 7
पट्टी	132	153	+21 0	15 9
गौरा	136	159	+23 0	17 0
शिवगढ	123	134	+11 0	8 94
मगरौरा	134	149	+15 0	11 19
आसपुर देवसरा	134	164	+30 0	22 38
जनपद	134	148	+14 0	10 45

सारिणी सख्या 5 16 प्रतापगढ जनपद मे मुख्य फसलों का उत्पादन (मी० टन)

फसल	1978-79	1986-87
चावल	92284	146705
गेहूँ	107422	207164
जौ	25590	10358
ज्वार	6513	6408
बाजरा	20034	14177
मक्का	1818	1838
अन्य खाद्यान्न	3115	1815
कुल खाद्यान्न	256780	388465
उर्द	830	2268
मूँग	265	1635
चना	11188	11148
मटर	3144	3938
अन्य दालें	682	10
कुल दालें	41939	36054
तिलहन		
लाही सरसों	315	306
अलसी	33	72
तिल	17	27
मूँगफली	25	6
मुद्रादायिनी		
गन्ना	90133	62071
आलू	1110176	91401
तम्बाकू	45	20

स्रोत जिला माह्यकीय पत्रिका 1980, 1988

जली फसलों के अन्नगत अन्नसी और तिल का अड़क-शोष अन्य फसलों के उत्पादन में कमी हुई है ।

मुद्रादायिनी फसलों, मुख्य रूप से गन्ना, आलू एवं तम्बाकू के उत्पादन में कमी आई है ।

सिंचाई साधन तथा सिंचाई गहनता कृषि की उत्पादकता तथा विविधता में सिंचाई के साधनों का विशिष्ट स्थान है । स्पष्ट है कि कृषि की परिवर्तनशीलता अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 38 (1) प्रतिशत भाग सिंचित था । किन्तु तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप तथा कालान्तर में पाचवी, छठी एवं सातवीं योजनाओं के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है । सन् 1986-87 में कुल बोये गये क्षेत्र का 62.0 प्रतिशत भाग सिंचित था (सारणी 5.17) । सिंचाई के कई साधन हैं । किन्तु जो चार साधन प्रमुख हैं उनमें नहर, नलकूप, कुएँ एवं तालाब का विशेष महत्व है । सन् 1979-80 में नहरों की कुल लम्बाई 1055.6 कि० मी० थी जो 1986-87 में बढ़कर 1685 कि० मी० हो गयी है । ये नहरे मुख्यरूप से शारदा सहायक परियोजना का अंग हैं । चार सिंचाई योजनाएँ भी चलाई गई हैं । किन्तु शक्ति के अभाव में उनका लाभ नहीं लिया जा सका । नलकूपों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है । सन् 1979-80 तथा 1986-87 में राजकीय तथा निजी नलकूपों की संख्या क्रमशः 113 तथा 17511 से बढ़कर 155 तथा 27761 हो गयी है । निजी नलकूपों की संख्या में जिस गति से वृद्धि हुई उससे न केवल किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सिद्ध होती है, अपितु कृषि में सिंचाई के महत्व का स्पष्टीकरण भी होता है । परम्परागत सिंचाई के साधन उदाहरण के लिये कुएँ, रहट तथा पम्पिंग सेटों की संख्या में कमी आई है । पक्के कुएँ 31580 (1979-80) से घटकर 20118 हो गये हैं । इसी बीच रहट की संख्या 13 से 6 तथा पम्पिंग सेटों की संख्या 1577 से घटकर 823 हो गयी है । सिंचाई के विभिन्न साधनों की संख्या में काफी प्रकार का उतार चढ़ाव आया है । उदाहरण के लिये 1986-87 में नहरों एवं नलकूपों के द्वारा क्रमशः 59.2 प्रतिशत तथा 36.7

प्रतिशत भाग सिंचा गया है । कुएँ एवं तालाबों का योगदान 33 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत रहा है । सिंचाई के अन्य साधनों का योगदान केवल 0.3 प्रतिशत रहा है । यदि हम 1979-80 के आकड़ों से इसकी तुलना करें तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि कुँआ, तालाब और इसी प्रकार के अन्य परम्परागत सिंचाई के साधनों का महत्व धीरे धीरे घट रहा है (सारिणी सख्या 5.18 से 5.20) ।

विकासखण्ड स्तर पर नहर, नलकूप, कुआँ, तालाब तथा सिंचाई के अन्य साधनों द्वारा की जाने वाली सिंचाई का तुलनात्मक विवरण सारिणी सख्या 5.20 में प्रस्तुत किया गया है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि नहर एवं नलकूपों के प्रभाव में व्यापक वृद्धि हुई । सिंचाई की गहनता को विकासखण्ड स्तर पर प्रदर्शित करने के लिये अधोलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है (रामकिशोर) ।

$$\text{सि० स० सूत्र} = \frac{\text{स० सि० क्षेत्रफल} \times 100}{\text{शु० स० क्षेत्रफल}}$$

जिसमें सि० = सिंचित

स० = सघनता

सू० = सूचकांक

शु० = शुद्ध

स० = सकल

सिंचाई गहनता को सारिणी सख्या 5.21 द्वारा दर्शाया गया है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि 1979-80 तथा 1986-87 के अन्तराल में सिंचाई गहनता में वृद्धि हुई । इन दो समयों के मध्य सिंचाई गहनता के अन्तर वृद्धि को मानचित्र (सख्या 5.8) द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इस मानचित्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्डों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है

प्रथम वे विकासखण्ड जहाँ पर सघनता की बढ़ोत्तरी अन्तर प्रतिशत 16 से अधिक है ।

इनके अन्तर्गत केवल कालाकाकर विकासखण्ड आता है ।

सारणी सख्या 5.17 प्रतापगढ़ जनपद में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत

वर्ष	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हेक्टर)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हेक्टर)	प्रतिशत
1951	230253	87554	38 0
1961	238104	95278	40 0
1979-80	222160	130361	58 7
1986-87	224685	140089	62 0

स्रोत जिला जनगणना पुस्तिका 1961

जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1980, 1987

सारिणी सख्या 5 18 प्रतापगढ जनपद मे सिंचित साधनों की सख्या

	1979-80	1986-87
नहरों की लम्बाई (कि० मी०)	1055 6	1685
राजकीय नलकूप	113	155
पक्के कुए	31580	20118
रहट	13	6
पम्पिंग सेट	1577	823
निजी नलकूप	17511	21761

स्रोत जिला साख्यकीय पत्रिका 1980, 1987

**सारिणी संख्या 5.19 प्रतापगढ जनपद में विभिन्न साधनों द्वारा
सिंचित क्षेत्र (प्रतिशत)**

वर्ष	1979-80	1986-87
नहर	45 7	59 2
नलकूप	38 4	36 7
कुए	14 0	3 3
तालाब/झील	1 7	0 6
अन्य	0 2	0 2

स्रोत जिला साख्यकीय पत्रिका 1980, 1987

सारणी संख्या 5 20 प्रतापगढ़ जनपद में विकास खण्डवार विभिन्न सड़कों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत (1979-80, 1986-87)

विकास खण्ड का नाम	नहर		नलकूप			कुएँ			तालाब			अन्य	
	1979-80	1987-87	1979-80	1986-87	1979-80	1979-80	1986-87	1979-80	1979-80	86-87	79-80	86-87	
सदर	12 7	19 9	55 4	69 8	31 8	9 5	0 1	0 0	-	0 8			
लक्ष्मणपुर	50 3	66 5	27 1	25 6	20 7	7 6	1 4	0 3	0 5	-			
मानवाता	38 3	55 4	44 4	41 7	15 6	2 5	1 0	0 3	0 7	0 1			
स0 चन्द्रिका	2 0	2 2	62 3	86 1	35 6	10 3	0 0	0 1	0 1	1 3			
सांगीपुर	32 0	61 7	25 6	26 0	40 5	11 9	1 9	0 1	0 0	0 3			
कुण्डा	80 8	92 3	16 0	6 9	3 3	0 3	0 1	0 5	-	-			
कालाकाकर	82 9	94 2	12 9	5 6	3 3	0 2	0 9	0 0	-	-			
बाबागज	78 6	91 5	17 1	7 0	1 0	0 2	3 1	1 3	0 2	-			
बिहार	68 6	89 2	34 9	9 5	3 0	0 3	2 9	0 4	0 6	0 6			
रामपुरखास	65 7	84 3	29 4	14 9	4 5	0 8	0 9	0 0	-	-			
पट्टी	31 4	35 9	57 6	62 5	8 8	1 2	2 2	0 3	0 3	0 2			
गौरा	35 8	49 3	52 9	44 5	8 2	1 9	3 1	4 3	0 0	0 0			
शिवगढ	14 7	13 7	61 4	18 7	23 5	7 5	0 4	0 1	0 3	0 0			
मगरोरा	26 8	36 2	46 3	7 9	12 8	2 2	4 8	0 8	0 0	0 0			
आसपुर देवसरा	29 1	37 2	56 2	61 5	12 6	1 2	1 6	0 1	0 5	0 0			

स्रोत जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1980, 1987

सारणी सख्या 5 2। जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर सिचाई गहनता

विकासखण्ड का नाम	1979-80	1986-87	अन्तर प्रतिशत
सदर	102	104	2 0
लक्ष्मणपुर	103	112	8 7
मानघाता	114	118	3 5
सडवा चन्द्रिका	119	109	8 4
सागीपुर	104	103	1 0
कुण्डा	108	114	5 6
कालाकाकर	105	140	33 3
बाबागज	104	116	11 5
बिहार	103	118	14 6
रामपुरखास	108	112	3 7
पट्टी	110	116	5 5
गौरा	110	122	10 9
शिवगढ	104	108	3 8
मगरौरा	108	108	-
आसपुर देवसरा	107	118	9 3

श्रोत जिला साख्यकीय पत्रिका 1980, 1987

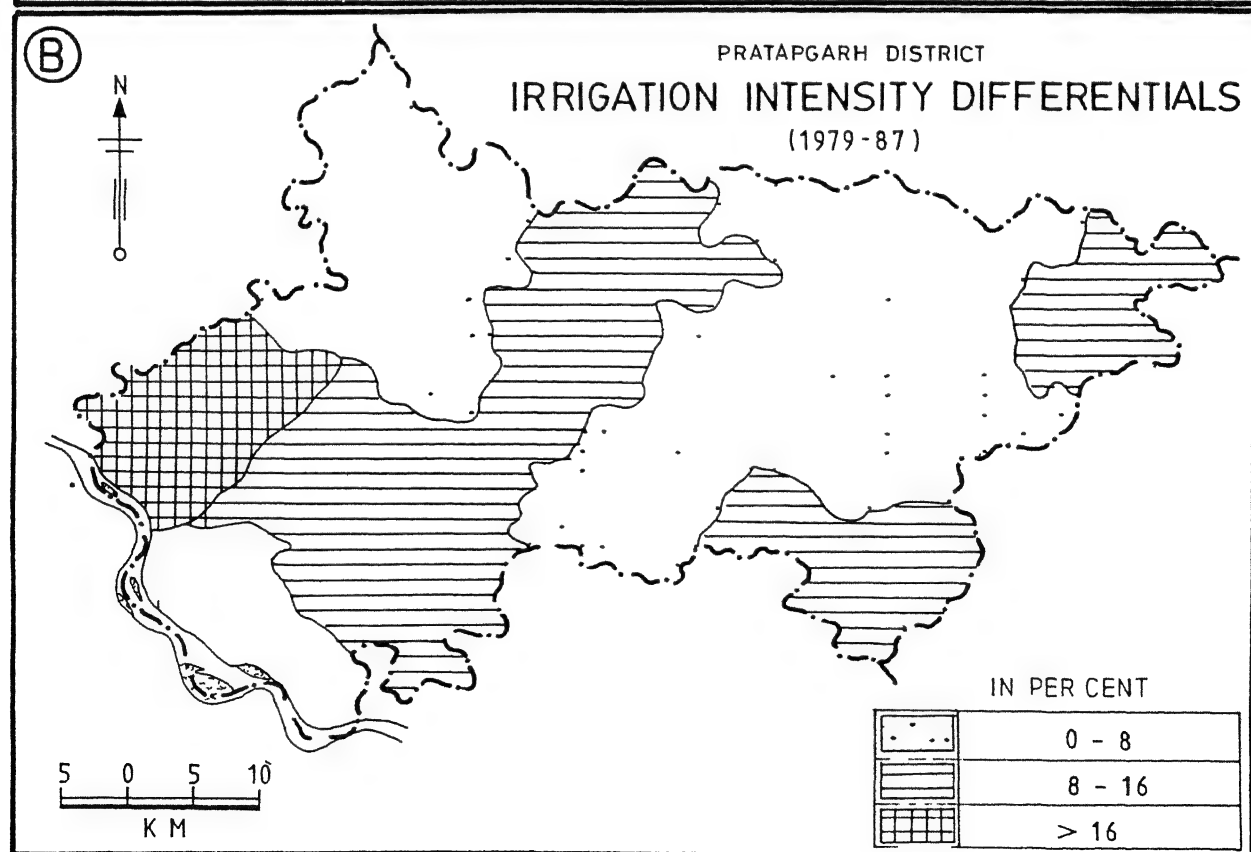
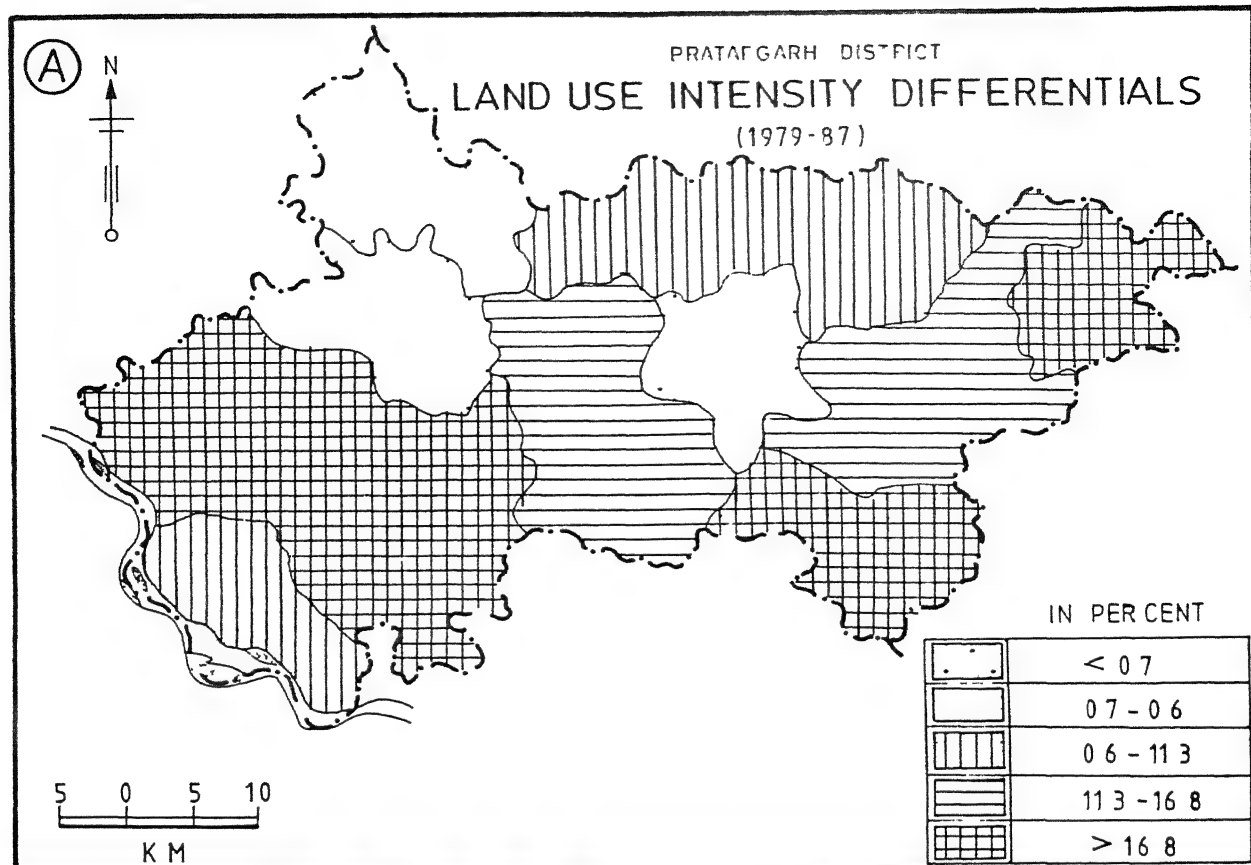


Fig.5.8

द्वितीय वे विकासखण्ड जहाँ पर सघनता का बढोत्तरी अन्तर प्रतिशत 8 से 16 के बीच है। इनके अन्तर्गत आसपुर देवसरा, गौरा, बिहार, बाबागज तथा सडवा चन्द्रिका विकासखण्ड आते हैं ।

तृतीय वे विकासखण्ड जहाँ सिचाई सघनता की बढोत्तरी का अन्तर प्रतिशत 8 से कम है। इसके अन्तर्गत सदर, मानधाता, सागीपुर, कुन्डा, रामपुरखास, पट्टी तथा शिवगढ विकासखण्ड आते हैं ।

सामाजिक - आर्थिक रूपान्तरण सहसम्बन्ध उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अधोलिखित सकल्पनाओं का परीक्षण सह सम्बन्ध विधि के आधार पर किया गया है, ये सकल्पनाये इस प्रकार हैं -

1. ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ धान एवं गेहूँ (जो खाद्यान्न की मुख्य फसलें हैं) के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है ।
2. ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि एवं वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।
3. प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायिक वर्गों में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत तथा ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि में भी महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।
4. साक्षरता प्रतिशत तथा ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि में महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।
5. भूमि उपयोग गहनता तथा सिचाई गहनता में महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।
6. धान के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र तथा विकास खण्डों में सेवाकेन्द्रों में महत्वपूर्ण सह सम्बन्ध है ।
7. गेहूँ के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र एवं विकास खण्डों में सेवाकेन्द्रों की संख्या में महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।
8. वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र एवं विभिन्न विकासखण्डों के सेवा केन्द्रों की संख्या में सह सम्बन्ध है ।

इन सकल्पनाओं के परीक्षण के लिये कार्यक्रम पर आधारित सह सम्बन्ध का परिकलन किया गया है तथा टी टस्ट

का प्रयोग कर 95 प्रतिशत सम्भावना का आधार मानकर प्रामाणिकता परीक्षण किया गया है । सह सम्बन्धों का परिकलित परिणाम सारिणी सख्या 5 22 तथा सह सम्बन्धों के प्रतिरूपा का परिणाम रेखा चित्रा (सख्या 5 10) द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इस परिकलन से अधोलिखित तथ्य स्पष्ट होते है

1 यह सत्य है कि ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि तथा धान एवं गेहू के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है क्योंकि उनमें से प्रत्येक का सह सम्बन्ध 0.5 है जो 95 प्रतिशत की सम्भावना पर प्रामाणिक है । यह सम्बन्ध इस बात का द्योतक है कि जनसख्या में वृद्धि के साथ धान गेहू के क्षेत्रफलों में वृद्धि हो रही है ।

2 द्वितीयक सकल्पना प्रामाणिक प्रतीत होती है क्योंकि ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि के साथ वार्षिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि दोनों का सह सम्बन्ध 0.5 है । यह इस बात का द्योतक है कि अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है । चतुर्थ सकल्पना केवल आन्तरिक रूप से ही उचित प्रतीत होती है ।

3 प्राथमिक, द्वितीयक, तथा तृतीयक वर्गों में लगी हुई कार्यरत जनसख्या एवं ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि के सह सम्बन्ध क्रमशः 0.03, 0.12, तथा 0.24 है जो प्रामाणिक सह सम्बन्ध नहीं है ।

4 ग्रामीण जनसख्या वृद्धि के साथ साक्षरता प्रतिशत में भी वृद्धि हो रही है क्योंकि उनका सह सम्बन्ध 0.4 है किन्तु ये भी प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता है । तत्पि यह है कि जनसख्या की वृद्धि की साक्षरता प्रतिशत की गति से अधिक है ।

5 भूमि उपयोग गहनता तथा सिंचाई गहनता अन्योन्नित से सह सम्बन्ध (0.86)

6 छठी सकल्पना कि धान के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा सेवाकेन्द्रों की सख्या में प्रामाणिक सह

**सारिणी सख्या 5 22 विकास स्तर पर चुने हुये सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण
चर और सहसम्बन्ध**

क्रम सं०	सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण चर	कोटिक्रमानुसार सह-सम्बन्ध
01	धान के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत 0 5
02	गेहू के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत 0 5
03	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत 0 5
04	प्रार्थमिक वर्ग में कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत 0 5
05	द्वितीयक वर्ग में कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत 0 12
06	तृतीयक वर्ग में कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत 0 24
07	साक्षरता प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत 0 4
08	भूमि उपयोग गहनता प्रतिशत	सिचाई गहनता प्रतिशत 0 86
09	धान के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	विकासखण्ड में सेवाकेन्द्रों की सख्या 0 8
10	गेहू के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	विकासखण्ड में सेवाकेन्द्रों की सेवा 0 2
11	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	विकासखण्ड में सेवाकेन्द्रों की सख्या 0 5

स्रोत परिकलन पर आधारित

सम्बन्ध है, सत्य है, क्योंकि यह 0.8 है इससे स्पष्ट है कि धान की खेती के उत्पादन से, सेवाकेन्द्रों के विकास को बल मिला है ।

7 सातवीं सकल्पना खरी नहीं उतरती क्योंकि गेहूँ के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्रफल तथा सेवाकेन्द्रों की संख्या में यद्यपि घनात्मक (0.2) सम्बन्ध है किन्तु यह प्रामाणिक नहीं है ।

8 आठवीं सकल्पना प्रामाणिक प्रतीत होती है क्योंकि वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र एवं सेवाकेन्द्रों की संख्या में घनात्मक सह सम्बन्ध (0.5) है । स्पष्ट है कि जैसे जैसे क्षेत्र में वाणिज्य से सम्बन्धित फसलों का प्रचलन बढ़ रहा है वैसे वैसे सेवाकेन्द्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

उपरोक्त निष्कर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो न केवल अधिवास तंत्र में होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं अपितु ये अधिवास तंत्रों को सुसंगठित करने में नीति निर्धारण के स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं । अध्ययन क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, और इन परिवर्तनों से सेवा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

भूमि सुधार एवं भूस्वामित्व के वितरण का प्रतिरूप

भूमि सुधार एवं भूस्वामित्व के वितरण का प्रतिरूप अधिवासों के सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अधिवासों का मुख्य आर्थिक आधार कृषि है और कृषि उत्पादन का मुख्य आधार भूमि है । इसलिये भूमि के स्वामित्व का प्रतिरूप तथा भूस्वामित्व को संगठित करने के लिये जो भी प्रयत्न समय समय पर किये जाते हैं उनका अधिवासों की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है । यह उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र में मुगलकाल से पूर्व भूराजस्व अथवा भूमि सुधार का कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिलता है । किन्तु शेरशाह एवं सम्राट अकबर द्वारा किये गये प्रशासकीय एवं भूराजस्व निर्धारण के प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं (डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1980) । अध्ययन क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन बदोबस्त सम्पन्न हुये । प्रथम बदोबस्त अक्टूबर 1860 में प्रारम्भ हुआ, द्वितीय जुलाई सन् 1892 तथा तृतीय अक्टूबर 1922 में सम्पन्न हुये । इन बदोबस्तों का मुख्य उद्देश्य भूमि की क्षमता के आधार पर

राजस्व निर्धारण करना, बिचवालीया प्रथा को समाप्त करना, बटाई प्रथा में सुधार लाना तथा खेत पर काम करने वालों का अधिक से अधिक संरक्षण पदान करना था ।

स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून एक्ट, 1950 की व्यवस्था कर भूस्वामित्व के बिखराव को समेट कर उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया

1. भूमिधर जिसको पूर्णरूप से भूमि पर स्वामित्व प्राप्त है तथा अपनी सम्पत्ति को हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है। इनको पैतृक स्वामित्व भी प्राप्त है ।
2. सीरदार यह वे किसान हैं जिनका पैतृक अधिकार प्राप्त है किन्तु भूमि का स्थान्तरण नहीं कर सकते हैं । यदि चाहे तो दस गुना राजस्व जमाकर भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं ।
3. असामी यह वे किसान थे जो वन, भूमि, रहन भूमि व बगीचे की भूमि का उपयोग कर सकते हैं किन्तु उनको पैतृक अधिकार नहीं था । उन्हें भूमि से बेदखल किया जा सकता है ।

सन् 1971 में अध्ययन क्षेत्र में 110400 भूमिधर थे जो 36029 हेक्टर भूमि पर खेती करते थे । सीरदार की संख्या 165500 थी और उनके अधिकार क्षेत्र में 65693 हेक्टर भूमि थी । सन् 1953 में उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम की व्यवस्था की गयी है । जिसका उद्देश्य बिखरी हुयी तथा छोटी कृषि सीमाओं को पुनः गठित करना था । इसका कार्यान्वयन सन् 1970 में हुआ (डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1980) । सन् 1960 में भूमि सीमा निर्धारण के लिये तथा बड़े कृषकों से भूमि लेकर छोटे किसानों अथवा सीमान्त कृषकों में वितरित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार **भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1960** की व्यवस्था की है जिसका कार्यान्वयन अध्ययन क्षेत्र में जनवरी 1961 में प्रारम्भ हुआ ।

इन विभिन्न भूमि सुधार के अधिनियमों के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र का भूस्वामित्व तथा भूमि सीमा पूर्णरूपेण प्रभावित हुई । सारिणी संख्या 5.23 में प्रतापगढ़ जनपद में क्रियात्मक

सारिणी सख्या 5 23 प्रतापगढ जनपद मे क्रियात्मक जोतों की संख्या

वर्ष	1951	1961	1977	1980-81
0 - 2 है०	65323 (69 1)	67881 (68 2)	363200 (93 7)	392616 (94 4)
2 - 4 है०	16763 (17 7)	17325 (17 4)'	18596 (4 8)	12814 (3 1)
4 - 10 है०	12134 (12 8)	13783 (13 8)	5139 (1 3)	10258 (2 5)
10 है० अधिक	381 (0 4)	595 (0 6)	442 (0 2)	-- --
	94601 (100 0)	99584 (100 0)	387372 (100 0)	415688 (100 0)

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961 जिला साख्यकीय पत्रिका 1978

जाती की संख्या और उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल का तुलनात्मक विवरण प्रदर्शित किया गया है । इस सारिणी में स्पष्ट है कि क्रियात्मक जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल में पर्याप्त विषमता पायी जाती है साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सीमान्त कृषकों की संख्या बहुत अधिक है । अध्ययन क्षेत्र में 83 प्रतिशत सीमान्त कृषक हैं जिनके पास 46 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है । 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर तथा 3 से 5 हेक्टेयर के बीच 11 3, 3 1 तथा 1 8 कृषक हैं जबकि उनके द्वारा अधिकृत भूमि का क्षेत्रफल क्रमशः 24 प्रतिशत, 12 4 प्रतिशत तथा 10 0 प्रतिशत है । लगभग 7 0 प्रतिशत कृषक ऐसे हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि है और उनके द्वारा अधिकृत भूमि भी कुल भूमि का 7 0 प्रतिशत है । सारिणी संख्या

में स्पष्ट है कि सन् 1951, 1961, 1971 तथा 1980-81 में भूमि के सीमान्तीकरण में वृद्धि हुई है । भूमि का यह सीमान्तीकरण जहाँ एक ओर उपज को प्रभावित करता है वहीं दूसरी ओर प्रवास को बल देता है । अधिकांश क्रियात्मक जोतों का आकार सीमान्त से कम है । अतः नई कृषक पद्धति का भी लाभ नहीं मिल पाता । फलतः बड़े पैमाने पर कृषि जनसंख्या नगरों की ओर पलायन हो रही है । इस प्रकार की प्रवासी जनसंख्या नगरों में मुख्य रूप से अनौपचारिक वर्ग की अर्थव्यवस्था में कार्यरत है । उदाहरण के लिये उनमें से अधिकांश लोग रिक्शा चालक, ठेला चालक, पान अथवा चाय की दुकान पर या इसी प्रकार अन्य कार्यों में लगे हुये हैं किन्तु इस पलायन से निश्चित रूप से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है । बेला प्रतापगढ़ की बढ़ती हुई आबादी इसका उदाहरण है । दूसरी ओर बड़े अथवा मध्यम वर्ग के जोतों वाले कृषक अपनी भूमि बटाई पर देकर अथवा बेचकर स्थानीय कस्बों में प्रसन्नता का प्रयत्न कर रहे हैं । कुन्डा, पट्टी तथा अन्तू इसके मुख्य उदाहरण हैं । ये लोग मुख्यतः होटल, चाय व पान की दुकान, कपड़े की दुकान, चूना तथा सीमेंट इत्यादि की दुकानें स्थापित कर रहे हैं । यह प्रवृत्ति इस लिये है कि इस वर्ग के कृषक वास्तविक अर्थों में कभी भी कृषक नहीं रहे हैं बल्कि वे जमींदार अथवा बिचवालिया जमींदार रहे हैं । इधर जनसंख्या प्रवास के कारण खेतों पर काम करने वाले मजदूरों की कमी हो रही है । अतः इस वर्ग के कृषकों के लिये कृषि-भूमि प्रबंध कठिन होता जा रहा है । विकास खण्ड स्तर पर भूमिस्वामित्व वितरण प्रतिरूप प्रदर्शित किया गया है (चित्र 5 9) । इस स्तर

RELATIONSHIPS AMONG SELECT SOCIO ECONOMIC VARIABLES AT BLOCK LEVEL (PRATAPGARH DISTRICT)

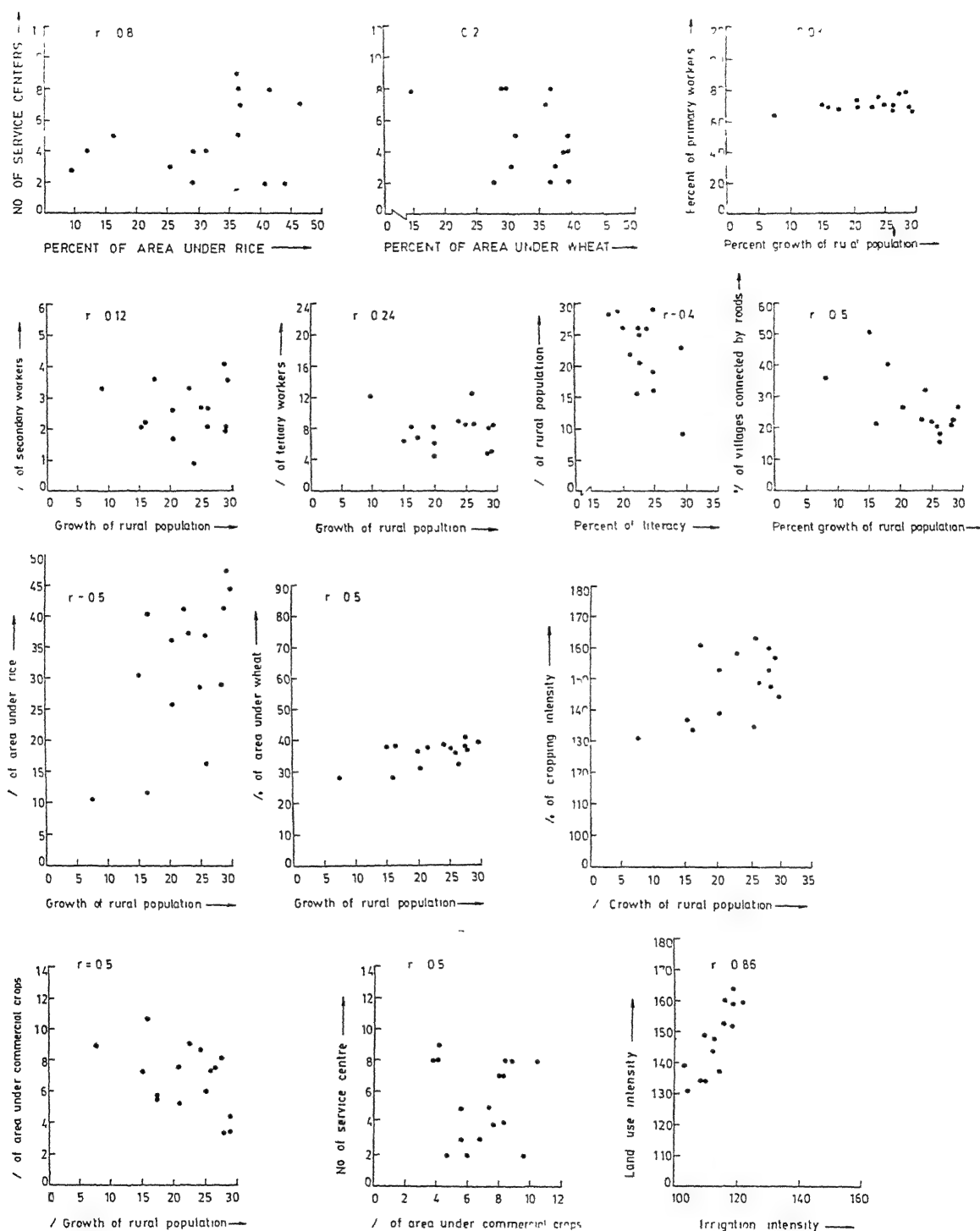


Fig 5.10

पर भी सीमान्त कृषकों का वर्चस्व स्पष्ट है क्योंकि प्रत्येक विकासखण्ड में 80 से 88 प्रतिशत जोतें । हैक्टर या उससे भी छोटी है ।

उपर्युक्त सामाजिक व आर्थिक कारकों के परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अगले अध्याय में अध्ययन क्षेत्र की विकास विषमताओं का निरूपण किया गया है ।

REFERENCES

- 1 Chandna R C and Manjit S (1980), Introduction to Population Geography, Concept New Delhi, p. 96
- 2 Clark, J I. (1972), Population Geography, Second Edition, Oxford and New York Pergamon
- 3 Davis, K (1952), The Population of India and Pakistan, New Jersey Princeton
- 4 Envedi, G Y (1964) Geographical Types of Agriculture, Applied Geography in Hungary, Budapest
- 5 Jones, H R (1981), A Population Geography, London and New York Harper and Row
- 6 Kishore, R. (1987) Micro Level Planning of Musafir Khana Tahsil, District Sultanpur, U.P unpublished Ph D. Dissertation University of Allahabad.
7. Misra, H.N (1990), Tertiarization of Indian Towns . A Study of the Process of Urban Growth in a Developing Region, Proceedings of the I.G.U Commission on Urban Geography, China.
8. Misra, H.N (1984), Urban System of a Developing Economy, Allahabad . I.I.D.R. and also in 1988 New Delhi : Heritage Publishers

- 9 Nevill, H.R (1904), Pratapgarh District Gazetteer, Allahabad Government Press.
- 10 Ramchandran, H (1980), Village Cluster and Development, New Delhi Concept
- 11 Raza, Moonis (1981), Urbanization and National Development in Honzo M (edit), Urbanization and National Development, Singapore Maruzen Asia.
- 12 Shafi, M. (1960), Measurement of Agricultural Efficiency of Uttar Pradesh, Economic Geography, vol. 19, No 36, No 4, pp 296-305
- 13 Shafi, M. (1972), Measurement of Agricultural Productivity of the Great Indian Plains, The Geographers, vol. 19, No. 1, pp. 4-13.
- 14 Stamp, L.D. (1962), The Land of Britain : Its use and Misuse 111rd Edition London Longmans.

अध्याय 6

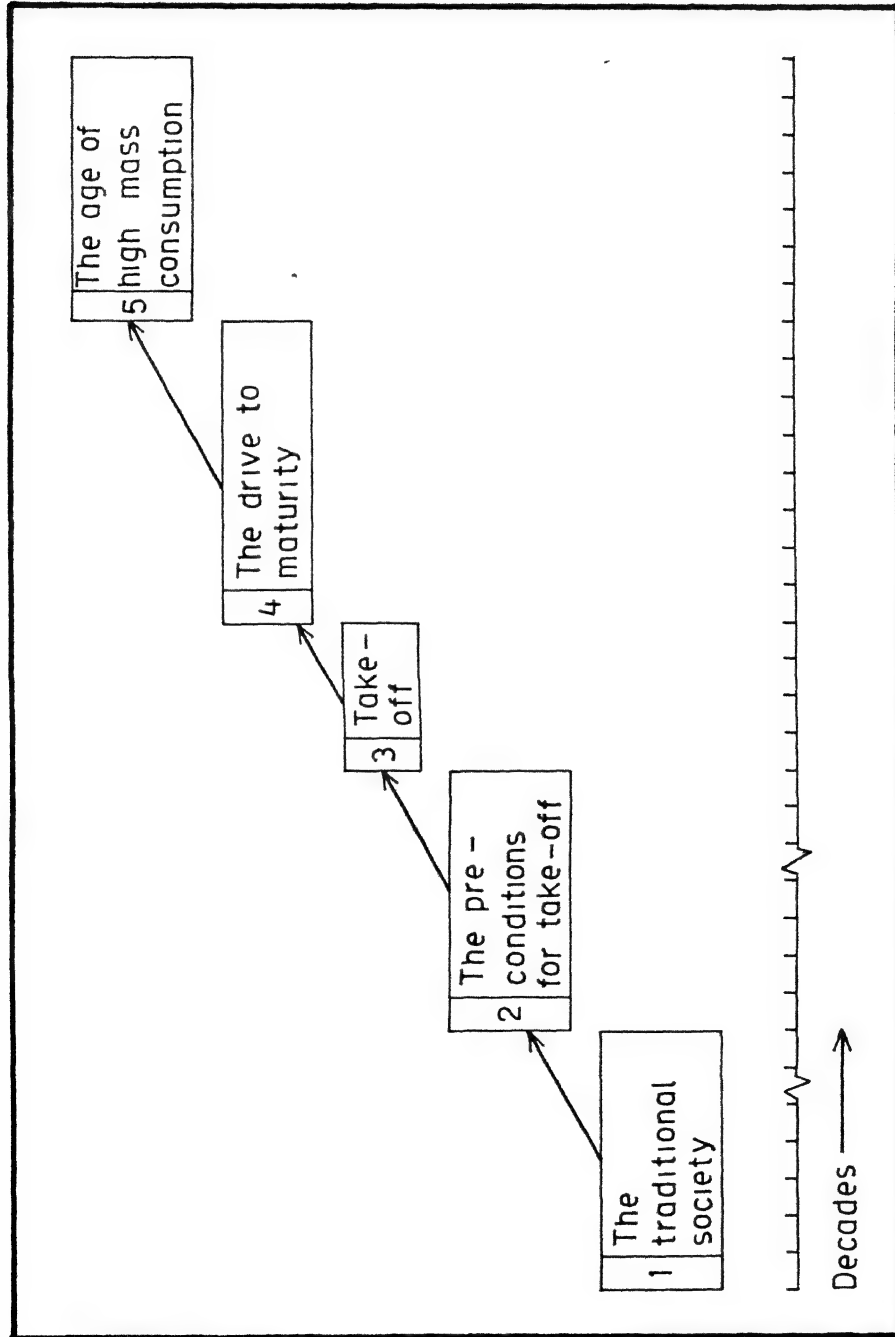
विकास विषमता प्रतिरूप

विगत अध्याय में अधिवासों में होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों को अध्ययन क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है । अध्ययन क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से स्थानिक विकास विषमता उद्भूत हुई है । प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के स्थानिक विकास विषमता के प्रतिरूप का अध्ययन किया गया है ।

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

सामाजिक - आर्थिक विकास की प्रक्रिया सर्वत्र समान नहीं होती है । अतः स्थानिक, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर विकास की विषमता बढ़ती जाती है । ये विशेषताएँ ग्राम व नगरीय स्तर पर भी दिखायी पड़ती हैं । विषमताओं की मापने के कई सूचकांक समय समय पर प्रयोग में लाये गये हैं तथा विषमता के प्रतिरूप को स्पष्ट करने के लिये भूगोलवेत्ताओं ने महत्वपूर्ण प्रयत्न किया है । अर्थशास्त्रियों ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की व्याख्या भी की है । विकास विषमता प्रतिरूप को विभिन्न सिद्धान्तों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय (इन्दु मिश्रा, 1991) है । अतः इन माडलों के मूल तत्वों को संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत करना समीचीन होगा ।

रस्टो का आर्थिक विकास सिद्धान्त रस्टो महोदय का सिद्धान्त, जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1955 में किया था (कीबुल 1967) मुख्य रूप से नवीनताओं पर बल देता है । यह माडल प्रादेशिक विषमताओं को स्पष्ट करने के साथ ही एक प्रदेश में समय के अन्तराल पर बढ़ती हुई सम्पन्नता में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है । रस्टो ने आर्थिक विकास को पाँच अवस्थाओं में विभक्त किया है (चित्र संख्या 6 ।)



THE ROSTOW MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT
(From R J Chorley and P Haggett, Models in Geography, Methuen)
Fig 6.1

1. प्रथम अवस्था में एक ग्रहियादी समाज की कल्पना की गई है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है और वह भी जीविका निर्वाह स्तर पर। सम्भावित ससाधनों का पता नहीं लग पाया है।
2. द्वितीय अवस्था वह अवस्था है जिसमें आर्थिक वृद्धि तेजी से प्रारम्भ हो जाती है। व्यापार का विस्तार होता है और बाह्य प्रभाव के कारण परम्परागत तकनीकों के साथ-साथ आधुनिक विधियों का भी श्रीगणेश हो जाता है।
3. तृतीय अवस्था "टेक ऑफ" अथवा ऊपर उठने की अवस्था है। प्राचीन परम्पराएँ पूरी तौर पर नवीन परम्पराओं से आच्छादित हो जाती हैं और आधुनिक औद्योगिक-समाज का जन्म हो जाता है। अनेक औद्योगिक इकाइयाँ उद्भूत हो जाती हैं तथा राजनैतिक एवं सामाजिक संस्थाएँ परिवर्तित होने लगती हैं और स्वयं-पोषी वृद्धि प्रारम्भ हो जाती है।
4. चतुर्थ अवस्था में औद्योगिक समाज का सुसंगठन हो जाता है। पूँजी का न्यास बढ़ने लगता है। जैसे-जैसे नई इकाइयाँ विकसित हो जाती हैं, कुछ औद्योगिक इकाइयाँ समाप्त हो जाती हैं।

मिरडल का क्युमुलेटिव कांजेशन मॉडल मिरडल महोदय ने 1956 में "क्युमुलेटिव कांजेशन मॉडल" प्रस्तुत किया (चित्र संख्या 6.2)। इनके अनुसार प्रादेशिक विषमताएँ आर्थिक विकास का अत्यन्त स्वाभाविक परिणाम हैं। विपणन शक्ति इस विषमता को प्रभावित करती है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को बिना हानि पहुँचाये कभी भी विकसित नहीं हो सकता। जैसा कि

चित्र से स्पष्ट है, मुख्य रूप से आर्थिक उन्नति उन स्थानों पर होती है जहाँ पर कि कच्चा माल और शक्ति के साधन सरलता से उत्पन्न होते हैं। एक बार जब विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तो वहाँ पर सचयी कारक कार्य करने लगते हैं। केन्द्रोपसारित बल तथा गुणक प्रभाव भी कार्य करने लगते हैं जिसके फलस्वरूप विकासशील औद्योगिक इकाइयों द्वितीयक औद्योगिक इकाइयों को जन्म देने लगती हैं। सामाजिक इकाइयों इस प्रक्रिया को सम्बल प्रदान करती हैं। इस श्रृंखला क्रम तथा प्रक्रिया के फलस्वरूप स्वयंपोषी आर्थिक वृद्धि होने लगती है। निर्धन क्षेत्रों से केन्द्रीय प्रदेशों की ओर ससाधनों के आकर्षण को मिरडल ने "बैकवाश इफेक्ट" की सज्ञा दी तथा अभिवर्धित केन्द्रीय प्रदेश से फेलने वाले सम्भावित विकास को उन्होंने "स्प्रेड इफेक्ट" की सज्ञा दी। इस प्रकार उन्होंने तीन स्थितियों का वर्गीकरण किया है

1. प्राथमिक औद्योगिक स्थिति जब कि प्रादेशिक विषमताये न्यूनतम होती है।
2. द्वितीय स्थिति जिसके अन्तर्गत सचयी कारक सर्वोत्कृष्ट होते हैं एवं एक प्रदेश विशेष अन्य प्रदेश की तुलना में आगे बढ़ रहा है। इस स्थिति में ससाधनों के वितरण में असन्तुलन बढ़ने लगता है।
3. तृतीय स्थिति वह है जिसमें कि निस्तारण प्रभाव के कारण स्थानिक विषमताये कम होने लगती है।

मिरडल महोदय के इस माडल की कटु आलोचना हुई है क्योंकि यह बहुत ही अधिक गुणात्मक और वास्तविकता से परे है। किन्तु फिर भी विकसित और विकासशील राष्ट्रों के

अन्तर को स्पष्ट करने में इस माडल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है (कीबुल, 1967) ।

फ्रीडमैन का केन्द्र सीमान्त माडल . यह माडल 'विकास विषमता प्रतिरूप तथा उनके कारणों का भी संक्षिप्त उल्लेख करता है । इनके अनुसार विश्व को गतिशील प्रदेश, द्रुतगति में बढ़ने वाले अथवा स्थानिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है । इस प्रतिरूप के अन्तर्गत पांच विशिष्ट कटिबन्ध देखे जा सकते हैं (फ्रीडमैन, 1966)

- 1 **केन्द्र प्रदेश** यह वह भाग है जहाँ पर कि नगरीय औद्योगिकरण, उच्च स्तरीय तकनीक, विविध ससाधन, श्रम तथा जटिल आर्थिक संरचना एवं उच्च वृद्धि पर केन्द्रित है ।
- 2 **अग्रोन्मुख मध्यम प्रदेश** यह वह प्रदेश है जो केन्द्र के चारों ओर परिधि के रूप में फैला हुआ है और केन्द्र से प्रभावित है । इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर ससाधनों का बहुतायात से उपयोग हो रहा है । जनसंख्या प्रवासित हो रही है और आर्थिक वृद्धि अचर है ।
- 3 **साधन सम्पन्न सीमान्त प्रदेश** यह वह भाग है जहाँ पर कि नये अधिवास विकसित हुये हैं तथा वृद्धि की सम्भावना है । नये खनिज ससाधनों का विकास और शोषण प्रारम्भ है ।
- 4 **निम्नोन्मुख प्रदेश** यह केन्द्र से दूर अंतिम सीमा वाले प्रदेश है जहाँ पर कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्षीणकाय है तथा कृषि का उत्पादन न्यूनतम है । यहाँ पर प्राथमिक

- ससाधन पूर्णतौर पर समाप्त हो गये है । फ्रीडमैन के अनुसार विश्व की विषमता का यही दृश्य है । बृहद नगरीय प्रदेश विकसित होने लगते है तथा यातायात की सुविधा और जटिल होने लगती है ।

5 पचम अवस्था मे उपर्युक्त चतुर्थ अवस्था की परिस्थितियों चरम सीमा पर होती है । उत्पादन की प्रचुरता बढ जाती है एव व्यवसाय मे तकनीकी व्यवसाय की वृद्धि होने लगती है, भौतिक सुख - सुविधा की वृद्धि के साथ ससाधनों का वितरण सामाजिक कल्याण के कार्य मे होने लगता है ।

यह सिद्धान्त पूजी निर्माण की विधि की व्यवस्था तो करता है, किन्तु इन पाचों अवस्थाओं मे सम्बन्ध को स्थापित करने वाले तन्त्र की व्याख्या नहीं करता । किन्तु फिर भी यह स्पष्ट है, और विकसित देशों के विश्लेषण मे बहुत अर्थयुक्त है । विकासोन्मुख देशों मे क्या यही प्रक्रिया कार्य करती है यह विचारणीय प्रश्न है । निश्चित रूप से तृतीय विश्व के कई देश प्रथम तीन अवस्थाओं के अन्तर्गत ही आते है (हैमन्ड, 1982) ।

ध्रुव /केन्द्र विकास सिद्धान्त अधिवास तत्र एव विकास मे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । इसी पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखकर विकास केन्द्र सकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ है । यद्यपि इस सकल्पना की कठोर आलोचना हुयी है । किन्तु फिर भी तृतीय विश्व के विकास की विचारधारा मे आज के सन्दर्भ मे विकास केन्द्र सकल्पना सबसे महत्वपूर्ण एव शक्तिशाली सकल्पना है । पेराउक्स महोदय (1955) द्वारा प्रतिपादित विकास ध्रुव विकास सिद्धान्त मुख्य रूप से आर्थिक सिद्धान्त है और अस्थानिक है । किन्तु सन् 1966 मे वोडविली ने इस

सकल्पना का न केवल अनुवाद किया अपितु भौगोलिक सकल्पना के रूप में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया । कालान्तर में इस विचारधारा का नियाजकों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला । भारतवर्ष जैसे देशों में तो इसे एक वैचारिक दर्शन और क्रियात्मक भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है जिनमें जानसन (1970), आर० पी० मिश्रा (1978), हरमनसन (1971), कुर्कलिनस्की (1971), मोसली (1974) इत्यादि के कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इस सिद्धान्त की मुख्य विचारधारा यह है कि विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया से ही विकास सम्भव है । यदि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र में विकासकेन्द्र होंगे तो अपने द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक सुविधाओं के द्वारा आस पास के क्षेत्रों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे । अन्तर - प्रादेशिक एवं ग्रामीण - नगरीय विषमता को दूर करने में इस सिद्धान्त को अनेक भूगोल वेत्ताओं ने बिल्कुल रामबाण के रूप में प्रस्तुत किया है ।

ऐसा समझा जाता है कि विकास केन्द्र, बाजार केन्द्र का पदानुक्रम मिलकर विकास की एक ऐसी शृंखला उत्पन्न करेगा जिससे कि प्रादेशिक विकास को गति मिलेगी (मिश्रा, 1984) । किन्तु इस सिद्धान्त की कटु आलोचना हुई । विभिन्न स्तर पर अधिवास केन्द्रों की स्थापना में लगने वाला धन कहाँ से मिलेगा ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह भी मूल प्रश्न है कि यदि इस प्रकार के केन्द्रों की आवश्यकता है तो वह स्वयं क्यों उत्पन्न नहीं होंगे । अधिवासों का विकास प्रादेशिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संरचना पर आधारित है, और जब तक उस प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या की आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं होगी कि वह इन केन्द्रों में स्थित विभिन्न प्रकार की सेवाओं को आश्रय दे सके, इस प्रकार के सेवाकेन्द्र

कभी भी विकसित नहीं होंगे । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के केन्द्रों की उत्पत्ति एवं विकास माग और आपूर्ति पर आधारित है । इसके अतिरिक्त विकास ध्रुव सिद्धान्त "टाप-टाऊन माडल" को प्रश्रय देता है जिसमें विकास की सकल्पना ऊपर से नीचे की ओर की गयी है ।

विकास केन्द्र से मिलती जुलती कई अन्य सकल्पनाएँ भी हैं जिनमें कि छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगर पर आधारित विकास तथा झुरमुट अथवा एग्लोपालिटन सकल्पनाएँ मुख्य हैं । छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों के विकास के संदर्भ में दत्ता (1981), राडनेली (1983), तथा मिश्रा (1936) के कार्य उल्लेखनीय हैं । इस सकल्पना के अनुसार प्रादेशिक विकास के लिये बड़े नगरों की तुलना में छोटे नगरों का विकास यदि किया जाय तो विकास की गति मध्यम तीव्र होगी ।

ग्रामीण झुरमुट अथवा एग्लोपालिटन सकल्पना का विकास फ्रीडमैन तथा ड्रगलाश (1976) एवं रामचन्द्रन (1980) ने प्रस्तुत किया । यह सकल्पना स्टूर एवं टेलर (1980) के अनुसार "बाटम - अप रणनीति" है जिसमें यह सकल्पना की गयी है कि विकास का विकेन्द्रीकरण लघुस्तर पर आवश्यक है और यह इसी रणनीति के अन्तर्गत सम्भव है ।

सीमांकन सूचकांक एवं विधियाँ

इन माडलों का मुख्य उद्देश्य विकसित, अर्द्धविकसित, विकासशील तथा पिछड़े हुये प्रदेशों में व्याप्त एवं उत्तरदायी प्रक्रियाओं को विश्लेषित करना है । सन् 1970 के आसपास जब भूगोल में समाज कल्याण एवं क्षेम सम्बन्धी आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ तो भूगोलविदों ने विषमता प्रतिरूप को सीमांकित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया । इनमें ड्रेवनासकी (1970), हार्वे

(1972), स्लेटर (1975), स्मिथ (1977, 1979), स्टूर एंव टाड (1977) का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । सन् 1961 की जनगणना से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर अशाक मित्रा (1965) ने सर्वप्रथम जनपद स्तर पर विकास को नापने का प्रयत्न किया । नाथ (1979) ने प्रान्तीय स्तर पर प्रादेशिक विभेद शीलता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । राव (1973) ने सन् 1960 एवं 1970 के मध्य उत्पन्न हुई विषमता का नापने का सफल प्रयोग किया है । सुन्दरम् (1983) ने भी भारतवर्ष में जनपद स्तर पर विकास की विभेद-शीलता प्रदर्शित कर विकसित, विकासशील एवं पिछड़े क्षेत्रों को सीमांकित किया । इस प्रकार का प्रयत्न केवल शोक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है । अपितु योजना की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि वे क्षेत्र जो कि विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सीमांकित कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है ।

सीमांकन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है । इसमें साधारणतम तकनीक से लेकर अत्यन्त उच्च स्तरीय विधियों का प्रयोग किया गया है । सामान्य रैंकिंग, "जी स्कोर", सामूहिक सूचकांक तथा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट विधियाँ प्रमुख हैं । विभिन्न विधियों के साथ साथ विविध प्रकार के चरों का भी प्रयोग किया गया है । सामान्यतः एक से अधिक चर प्रयोग में लाये गये हैं । चरों का चुनाव समय समय पर बदलता रहा है । प्रारम्भ में "बाल मृत्युदर" को ही विकास का सूचक माना जाता था । यदि मृत्युदर अधिक है तो विकास कम है और यदि कम है तो देश अधिक विकसित है । संयुक्त राष्ट्र सघ ने "जीवन स्तर" को महत्वपूर्ण सूचकांक के रूप में विकसित किया । जीवन स्तर को एक सामूहिक सूचकांक के रूप में विकसित किया गया जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, व्यवसाय की

स्थिति, यातायात की सुविधा, उपभोग एवं बचत, आवास, वस्त्र, आमाद - प्रमोद के अवर, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव की स्वतंत्रता जैसे आयाम सम्मिलित थे । वास्तविकता यह है कि विकसित तथा अविकसित अवस्थाओं के मध्य कई स्थितियाँ हैं जिनका निरूपण पूर्णरूपेण सम्भव नहीं है । विकास की स्थिति कई आयामों से प्रभावित होती है जो आर्थिक, जनार्किक, सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी है । कुछ विद्वानों ने माहत्वा शिक्षा, रोजगार के अवर, प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध पय जल की उपलब्धता और आवास की स्थिति का सम्मिलित कर विकास का विषमता प्रतिरूप मापने का प्रयाग किया है । विकास का व्यक्तित्व बहुआयामी है और इसको कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र में विकास विषमता मापन

अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक - आर्थिक विकास की विभेद शीलता को प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश्य उसे विकसित अर्द्धविकसित, विकासशील एवं अविकसित वर्गों में विभक्त करना है । पस्तुत अध्ययन में कुल 21 चरों का चुनाव किया गया है । यह चर अधोलिखित हैं

- 1 जनसख्या का घनत्व, 1981
- 2 लिंग अनुपात वर्ष, 1981
- 3 जनसख्या वृद्धि, 1971-81
- 4 साक्षरता प्रतिशत, 1981
- 5 कर्मचारों का प्रतिशत, 1981
- 6 अकर्मचारों का प्रतिशत, 1981

- 7 नगराय जनसंख्या का प्रतिशत, 1981
- 8 सड़क का घनत्व प्रति 1000 जनसंख्या, 1986-87
- 9 सड़क से जुड़े गावों का प्रतिशत, 1986-87
- 10 विद्युतीकृत गावों का प्रतिशत, 1986-87
- 11 कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, 1986-87
- 12 मुद्रादायिनी फसलों का प्रतिशत, 1986-87
- 13 फसलगहनता का प्रतिशत, 1986-87
- 14 शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत, 1986-87
- 15 प्रति हेक्टेयर पर रासायनिक खाद का उपयोग कि० ग्रा०, 1986-86
- 16 प्रति व्यक्ति उत्पादन कि० ग्रा०, 1986-87
- 17 प्रति व्यक्ति भूमि का उपयोग हे०, 1986-87
- 18 प्रति हजार जनसंख्या पर जू० बे० स्कूल, 1986-87
- 19 प्रति हजार जनसंख्या पर डाकघर, 1986-87
- 20 प्रति हजार जनसंख्या पर बाजार, 1986-87
- 21 प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल, 1986-87

इन चरों का सह-सम्बन्ध विकास खंड स्तर पर कम्प्यूटर पर एस पी एस एस प्रोग्राम की सहायता से ज्ञात किया गया है । वह सह-सम्बन्ध (सारिणी संख्या 6।) रेखांकित किये गये हैं जिनका सिग्निफिकेट लेवल 99 प्रतिशत है । इसको ज्ञात करने के लिये टी - टेस्ट का उपयोग किया गया है, जिसका सूत्र इस प्रकार है

इस सूत्र से यह प्रतीत होता है कि कुल ऐसे 20 सह-सम्बन्ध हैं जो 99 प्रतिशत "कानाफडेन्स लिमिट" पर "सिग्निफिकेंट" हैं । इन 20 सह-सम्बन्ध से अधोलिखित निष्कर्ष निकलते हैं

- (1) जनसंख्या के घनत्व तथा प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि तथा प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि में घनात्मक सह-सम्बन्ध (0.83) है । किन्तु प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन एवं जनसंख्या घनत्व में ऋणात्मक सह-सम्बन्ध (0.66) है । स्पष्ट है कि जनसंख्या घनत्व एवं खाद्यान्न आपूर्ति में अन्तर है ।
- (2) लिंग अनुपात तथा सड़क के घनत्व में ऋणात्मक सह-सम्बन्ध है जिससे स्पष्ट होता है कि नगरीय अधिवासों की तुलना में ग्रामीण भाग में सड़कों का समुचित विकास नहीं हुआ है ।
- (3) जनसंख्या वृद्धि तथा विद्युतीकृत गावों के प्रतिशत में नकारात्मक सह-सम्बन्ध (0.70) है । ठीक इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि एवं प्रति हेक्टेयर उर्वरक के उपयोग में भी नकारात्मक (0.66) सह-सम्बन्ध है । इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि के आधुनिकीकरण पर बल नहीं देता है ।

(4) जनसंख्या की वृद्धि एवं सिंचित भूमि का घनात्मक (72) सह-सम्बन्ध इस बात का द्योतक है कि कृषि में सिंचाई साधनों का उपयोग बढ़ रहा है ।

(5) साक्षरता तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगी जनसंख्या प्रतिशत का सह-सम्बन्ध घनात्मक (64) है । यह इस बात का सूचक है कि साक्षरता वृद्धि के साथ जनसंख्या का प्रवास होने लगता है और साथ ही साथ कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगी जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगता है । यह मुख्य रूप से तृतीयक (टर्शियरी) प्रकार के व्यवसाय की वृद्धि का द्योतक है । साक्षरता प्रतिशत तथा सड़क के घनत्व में घनात्मक (65) सह-सम्बन्ध है । इससे यह प्रतीत होता है कि नगरीय आवासों का सड़क यातायात, ग्रामीण अधिवासों के यातायात की अपेक्षाकृत अच्छा है । यह निष्कर्ष संख्या 2 का पूरक है ।

(6) यह महत्वपूर्ण है कि साक्षर जनसंख्या और प्रति हेक्टेयर उर्वरक के प्रयोग में घनात्मक (75) सह-सम्बन्ध है । साक्षर किसान ही कृषि आधुनिकीकरण में विश्वास रखते हैं । इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि साक्षरता और प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि भूमि में नकारात्मक (75) सह-सम्बन्ध है ।

(7) प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन और साक्षरता में नकारात्मक (85) सह-सम्बन्ध है ।

(8) कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगी कार्यशील जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति कृषिकृत भूमि (63) के मध्य नकारात्मक सह-सम्बन्ध है यह अपने आप में स्पष्ट है ।

- (9) नगरीय जनसंख्या तथा सड़क यातायात के मध्य सह -सम्बन्ध (76) महत्वपूर्ण है ।
- (10) ऐसा प्रतीत होता है कि नगरीय जनसंख्या उर्वरक के प्रयोग में आगे है क्योंकि इनके दोनों के बीच का सह - सम्बन्ध धनात्मक (88) है । आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण की यह प्रक्रिया सड़क घनत्व तथा प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग से पुन स्पष्ट होती है क्योंकि इसके बीच का सह-सम्बन्ध 63 है ।
- (11) फसलगहनता तथा सिंचित कृषि भूमि का धनात्मक सह-सम्बन्ध (87) है । यह इस बात का द्योतक है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है । जैसे जैसे सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे फसल गहनता बढ़ती जाती है ।
- (12) प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग तथा प्रति व्यक्ति कृषिकृत भूमि एवं प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में धनात्मक सम्बन्ध है । इनका सह-सम्बन्ध क्रमशः 65 तथा 63 है। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि एवं प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन का सह-संबन्ध 87 है ।
- (13) प्रति एक हजार जनसंख्या पर स्कूल तथा जनसंख्या का सम्बन्ध ऋणात्मक (69) है । इससे स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थाओं एवं जनसंख्या वितरण में उचित तालमेल नहीं है ।

विकास वितरण प्रतिरूप

उपर्युक्त चरों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न विकास खंडों को उनके विकास स्तर

के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया गया है । यह वर्गीकरण नियोजन में सहायक सिद्ध हो सकता है । तथा कम विकसित अथवा अर्धविकसित विकास खण्डों को निर्धारित कर वहाँ विशेष योजनाएँ चला कर उनको एक निश्चित स्तर पर लाया जा सकता है । विकास स्तर को निर्धारित करने के लिये उपर्युक्त 21 चरों को "लीनियर माडल" के आधार पर "जी स्कोर" का प्रयोग कर कुल स्कोर के आधार पर विकास का पदानुक्रम निर्धारित किया गया है । "जी" स्कोर का सूत्र इस प्रकार है

"जी स्कोर" के योग के आधार पर विकास खण्डों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है

1. अविकसित विकास खण्ड (0-15) इस वर्ग के अन्तर्गत मगहोरा एवं गौरा विकास खण्ड हैं जिनका सूचकांक 0-15 के बीच है । ये ऐसे विकास खण्ड हैं जहाँ विकास गति धीमी है तथा सुविधाओं का अभाव है ।
2. विकासशील विकास खण्ड (15-20) इस वर्ग के अन्तर्गत आसपुर देवसरा, सागीपुर, बिहार, शिवगढ़, बाबागंज, नडवा चन्द्रिका, मानधाता एवं कालाकांकर विकास खण्ड आते हैं । इनका विकास सूचकांक 15 से 20 के बीच है । इन विकास खण्डों में भी सामाजिक-आर्थिक तंत्र एवं सुविधायें अपेक्षाकृत अविकसित हैं ।

3 मध्यम स्तरीय विकास खण्ड (20 से 25) इसके अन्तर्गत लक्ष्मणपुर, कुन्डा, रामपुर एवं पट्टी विकास खण्ड स्थित है। इन विकास खण्डों में सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं का वितरण अपेक्षाकृत ठीक है। इन विकास खण्डों में विकास की गति तीव्र होने के कारण यहाँ पर जीवन स्तर अन्य दो वर्गों की तुलना में अच्छा है।

4 उच्च स्तरीय विकास खण्ड (25 से अधिक) इस वर्ग के अन्तर्गत प्रतापगढ़ विकास खण्ड है जिसमें कि सामाजिक व आर्थिक सुविधाओं का विवरण सर्वोत्कृष्ट है।

मानचित्र संख्या 6 3के विश्लेषण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विकास मुख्य रूप से अध्ययन क्षेत्र के केन्द्रीय भाग में केन्द्रित है। इसमें प्रतापगढ़ विकास खण्ड मुख्य है। सम्भवतया प्रतापगढ़ नगर की स्थिति ने विकास को केन्द्र भाग में ही अपने स्थिति कि चारों ओर सीमित कर रखा है। कुन्डा एवं रामपुर खास विकास खण्ड इसके अपवाद है। किन्तु सामान्यतया केन्द्र की तुलना में सीमान्त क्षेत्रों में विकास गति धीमी है। योजनाबद्ध विकास में इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा और केन्द्र से सीमान्त प्रदेश की ओर विकास के आयाम को गति देने के लिये नीति स्तर पर प्रयास करना होगा।

REFERENCE

1. Drenowski, J (1970). Studies in the Measurement of Levels of living and welfare, U.N.R.I.
2. Dutta, S.S. (1981). India's Urban future: Role of Small and medium towns, Jl. of the Institute of Town Planning, India.
3. Friedmann, J. (1966), The Urban-Regional Frame for National Development International Development Review.
4. Friedmann. J. and Doughloss, (1976) Agropolitan Development Towards a New Strategy for Regional Development in Asia, Proceedings of the Seminar on Growth Pole Strategy and Regional Development in Asia, UNCRD Nagoya, 337-387
5. Johnston, E.A.J (1970), The Organization of Space in Developing Countries, Cambridge (Mass) : Harvard University Press.
6. Keeble, D. (1967), Models of Economic Development in R.J. Chorley and P. Haggett (1967), Models in Geography, London : Methuen.
7. Kuklinski, A. and R. Petrella (eds) (1971) Growth and Regional Policies the Hague : Mouton
8. Hammond, C.W. (1982), Elements of Human Geography, London

: George Allen & Unwin.,

9. Harvey, D. (1972). Social Justice and the City, London : Edward Arnold.
10. Harvey, D. (1972), Limits to capital, London : Basil Blackwell.
11. Harmensen, Tormod (1971), Spational Organization and Economic Development Mysore : Int. of Dev. Studies.
12. Nath, V. (1970), Regional Development in Indian Planning, Economic and Political Weekly, Annual number, (January)
13. Misra, H.N. (1984) Urban System of a Developing Economy, Allahabad : I.I.C R.
14. Mitra, A. (1965), Level of Regional Development in India, New Delhi : Government of India.
15. Misra, H.N. (1986), Rae Bareli, Sultanpur and Pratapgarh Districts, Uttar Pradesh, North India, in Jorge Hardoy et al (ed) Small and Intermediate urban centres : Their role in national and regional development in the third world, London: Hodder and Stoughton.
16. Misra, Indu (1991), Human settlement system and Regional

. George Allen & Unath.,

- 9 Harvey, D. (1972). Social Justice and the City, London : Edward Arnold
10. Harvey, D. (1972), Limits to capital, London : Basil Blackwell.
- 11 Harmensen, Tormod (1971), Spational Organization and Economic Development Mysore • Int. of Dev Studies.
12. Nath, V. (1970), Regional Development in Indian Planning, Economic and Political Weekly, Annual number, (January)
13. Misra, H.N. (1984) Urban System of a Developing Economy, Allahabad : I.I.C.R.
14. Mitra, A. (1965), Level of Regional Development in India, New Delhi : Government of India.
- 15 Misra, H.N. (1986), Rae Bareli, Sultanpur and Pratapgarh Districts, Uttar Pradesh, North India, in Jorge Hardoy et al (ed) Small and Intermediate urban centres : Their role in national and regional development in the third world, London: Hodder and Stoughton.
16. Misra, Indu (1991), Human settlement system and Regional

Development in Allahabad District : The Problems and Policies, D. Phil. Dissertation, Allahabad University.

17. Misra, R.P. et al (1978), Regional Planning and Development, New Delhi : Vikas.
18. Moseley, M.J.A. (1974), Growth Centres in spatial planning, Oxford : Pergman Press.
19. Perroux, F. (1955), La Nation de Croissance Economique Applique Nos. 1 & 2 as quoted in Misra, R.P. et al 1978) above.
20. Rao, S.K. (1973), A Note on Measuring Economic Distances between Regions of India, Economic and Political Weekly, 28 (April).
21. Ramchandran, H. (1980), Village cluster and Development, New Delhi : Concept.
22. Rondinelli, E.A. (1983), Secondary cities in Developing Countries : Policies for Diffusing urbanization Beverly Hills: Sage Publication.
23. Slater, E. (1975), Underdevelopment and Inequality, Progress in Planning, 4, 97-167
24. Stohr, W. and Todtling, F.(1977), Spatial Equity - Some

Antitheses to Current Regional Development doctrine, Papers of the Regional Science Association, 38, 33-53

25. Smith, E.M (1979), Where the Grass is Greener - Living in an Unequal world, Baltimore :The John Hopkins University Press.
26. Sundaram, K V. (1983), Geography of Under-development, New Delhi Concept
27. Smith, E M (1979), Human Geography : A welfare approach, London • Edward Arnold
28. Stohr, W. and P.R F. Taylor (1980), Development from Above and Below, London . John Wiley

अध्याय 7

निष्कर्ष तथा नीतिपरक सस्तुतियों

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य एक लघु-स्तरीय प्रदेश की यथास्थिति पुनर्विलोकन तथा विश्लेषण करना है । इसके लिए एक जनपद का चुनाव किया गया है । यद्यपि कि जनपद एक प्रशासनिक इकाई है, किन्तु सरकारी स्तर पर लघु स्तरीय नियोजन की यह सर्वमान्य इकाई है । शोध की मुख्य आधार भूमि मानव अधिवास तन्त्र का विश्लेषण है क्योंकि मानव अधिवास किसी भी क्षेत्र के कार्यात्मक एवं सगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके विश्लेषण से उद्भूत निष्कर्ष क्षेत्रीय नियोजन में महत्वपूर्ण निवेश का कार्य करते हैं । प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं

- 1 मानव अधिवास तन्त्र का विश्लेषण करना ।
- 2 मानव अधिवास के सामाजिक - आर्थिक आधारों के रूपान्तरण में लगे हुये प्रक्रमों को स्पष्ट करना ।
- 3 सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण से उद्भूत विकास विषमता के प्रतिरूप का सीमांकन एवं विश्लेषण करना ।
- 4 मानव अधिवास व क्षेत्रीय सगठन संबंधी कुछ नीतिपरक सस्तुतियों का उल्लेख करना ।

अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिणपूर्व अंचल में स्थित प्रतापगढ़ जनपद है जो 3730 वर्ग कि० मी० क्षेत्र पर विस्तृत है । प्रमुखतया समतल धरातल वाला यह क्षेत्र अत्यन्त सघन बसा हुआ है । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 18,86,833 थी, जो सन् 1991 में बढ़ कर 22,11,253 हो गयी । जनसंख्या का घनत्व 1981 और 1991 में क्रमशः 525 व 929 था । जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है जो 2185 गाँवों में निवास करती है । केवल 7 अधिवास ऐसे हैं जिन्हें नगरीय अधिवास का दर्जा प्राप्त है । क्षेत्रीय पर्यावरण के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मिट्टी, जलवायु, तथा अन्य भौतिक संसाधन, कृषि अर्थव्यवस्था को मूल रूप से बल प्रदान करते हैं । वनों का क्षेत्रफल कम हो रहा है अथवा वनों का क्षेत्रफल अत्यन्त अल्प (0.1%) है, जो निश्चय ही पर्यावरण के सन्तुलन को

चुनौती दे रहा है । जल ससाधन भी कम है, और जो है, उनका समुचित प्रबन्ध नहीं हो पाया है । खनिज सम्पत्ति का भी अभाव है । अतः भूमि पर और इसलिये मिट्टी पर बोझ बढ़ा है जिम्मे भू-क्षण की प्रक्रिया तेज हो चली है ।

जनसंख्या का अधिकांश भाग 500 - 1000 तथा 1000 - 2000 तक के आबादी के अधिवासों में आबाद है । उल्लेखनीय है कि छोटे आबादी वाले अधिवासों की संख्या घट रही है । निरन्तर आबादी बढ़ने के कारण छोटे अधिवास बड़े अधिवासों के क्रम में शामिल हो रहे हैं । उनका स्थानिक वितरण प्रमुख रूप से समान है । जनसंख्या एवं कार्यों के आधार पर सेवा केन्द्रों का विश्लेषण क्षेत्र में पदानुक्रम संकल्पना का पूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करता है । किन्तु कोटि - आकार नियम की तुलना में जेफरसन महोदय का "प्राथमिक नगर सिद्धान्त" अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि बेला प्रतापगढ़ जो जनपद का मुख्यालय तथा प्रमुख नगरीय इकाई है, का आकार दूसरे क्रम पर स्थित कण्डा नामक नगरीय इकाई से चार गुना बड़ा है और उत्तरोत्तर विकास के कारण बढ़ने की यह प्रक्रिया अबोध गति से चल रही है । सेवा केन्द्र स्तर पर उनकी जनसंख्या और कार्यात्मक इकाईयों तथा कार्यात्मक प्रकारों के सह - सम्बन्ध का विश्लेषण इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ - साथ कार्यात्मक इकाईयाँ और कार्यात्मक प्रकारों में वृद्धि होती है । यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो सामान्य निष्कर्षों से भिन्न प्रतीत होता है और इस बिन्दु पर अधिक गहराई से विचार करने की आवश्यकता है । यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं (कार्यात्मक इकाईयों तथा कार्यात्मक प्रकार) का वितरण किसी निर्यात क्रम में नहीं हुआ है । यही कारण है कि स्थानिक संगठन ढीला है ।

सामाजिक - आर्थिक कारकों के विश्लेषण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक रूपान्तरण में गति आई है । चाहे नगरीकरण हो, शिक्षा हो, कृषि हो अथवा अन्य किसी प्रकार का व्यवसाय हो - बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है । परिवर्तन मुख्यतया विकास - नीतियों के फलस्वरूप हुए हैं । ये नीतियाँ ग्रामीण विकास, औद्योगिक

कृषि विकास से सम्बन्धित है । इन विकास की नीतियों से उद्भूत परिवर्तन से अध्ययन क्षेत्र में (अन्य क्षेत्रों की भांति) विषमता उत्पन्न हुई है जोकि विकास खण्ड स्तर पर 22 चरों का सह-सम्बन्धों के विश्लेषण एवं उनके रेखिक रूपान्तरण से किये गये सीमांकन से स्पष्ट है । किन्तु यहाँ पर भी विकास की प्रक्रिया पुण्जीभूत होने के का स्पष्ट उदाहरण दिखलाई पड़ता है । अधिकांश विकास केवल बेला प्रतापगढ़ अथवा सदर विकास खण्ड में केन्द्रित है और सीमान्त क्षेत्र अब भी विकास की भाग दौड़ में काफी पीछे है । केन्द्र सीमान्त परिधि मॉडल और "विकास केन्द्र मॉडल" की उपयोगिता को ओर अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में देखना होगा ।

इस सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र में विकास की दिशा को गति देने के लिये अधोलिखित बिन्दुओं को नीति स्तर पर देखना होगा ।

1. लघुस्तरीय नियोजन में अधिवास संबंधी नीति का होना परमावश्यक है, क्योंकि वे ही क्षेत्र की स्थानिक व कार्यात्मक संगठन को सम्बल प्रदान करते हैं । इसके लिए यह आवश्यक है कि यह अधिवास तंत्र की सकल्पना के अन्तर्गत हो । जिसका मुख्य उद्देश्य अधिवासों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध की स्थापना करना है ।

अध्ययन क्षेत्र के अधिवास एवं सेवाकेन्द्रों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नीतिपरक अथवा स्वतंत्र सेवाओं (कार्यात्मक इकाईयों तथा उनके प्रकार) का वितरण किसी नियम अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं हुआ है । आवश्यकता इस बात की है कि वे सभी अधिवास, जहाँ पर किसी सेवा के लिए मध्यम जनसंख्या सीमा अथवा न्यूनतम जनसंख्या सीमा उपलब्ध है वहाँ पर उस सेवा को स्थापित किया जाय । अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए जनसंख्या सीमा सारिणी संख्या 7.2 में प्रस्तुत है । नीतिपरक कार्यात्मक इकाईयों के वितरण में जनसंख्या का थ्रेसहोल्ड आधार का कार्य कर सकता है । अच्छा तो यह होगा कि प्रत्येक एक हजार आबादी वाले अधिवासों की सेवाओं के वितरण में प्राथमिकता दी जाय ।

2. अध्ययन क्षेत्र का मुख्य आर्थिक आधार कृषि है । धान, गेहूँ, दालें एवं मुद्गादायिनी तथा वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, किन्तु फिर भी सिचाई के

साधन, उर्वरक और प्रोन्नत किस्म के बीज को उपलब्ध करा कर कृषि संरचना में महत्वपूर्ण एवं द्रुत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । इसके लिये "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध धन का प्रयोग भी किया जा सकता है ।

- 3 भूमि सुधार सम्बन्धी नियमों का और कड़ाई से परिपालन आवश्यक है । जोतों की संख्या के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसका वितरण अत्यन्त असमान है । अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त कृषक की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । जोतों के वितरण की असमानता को यदि कम करने का उपाय किया जाय तो निश्चय ही विकास विषमता क्षेत्रीय स्तर पर तथा व्यक्तिगत स्तर पर कम हो जायेगी तथा प्रति व्यक्ति आय के साधन और अधिक सुरक्षित हो जायेंगे ।
- 4 लघु, मध्यम एवं बृहत्त औद्योगिक इकाईयों के अध्ययन (सारिणी संख्या 7 ।) से स्पष्ट है कि इनका विकास खण्ड स्तर पर वितरण अत्यन्त असमान है । सदर विकास खण्ड इस दृष्टि से अधिक लाभान्वित हुआ है । इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक मध्यम इकाई वाला उद्योग तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु औद्योगिक इकाई के केन्द्र स्थापित किये जायें । इससे जहाँ एक ओर व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन होगा, वहीं पर दूसरी ओर शिक्षित बेरोजगार युवकों का नगरीय केन्द्रों की ओर प्रवर्जन रुकेगा । यह उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र जनसंख्या प्रवास का बहुत ही सक्रिय क्षेत्र है क्योंकि रोजगार के अवसर बहुत कम हैं
- 5 यह भी आवश्यक है कि विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक गांव में सुदृढ़ "ग्रामीण विकास परिषद" की नियमित स्थापना की जाय । वर्तमान इकाईया बहुत क्रियाशील नहीं दिखाई पड़ती । यह ग्रामीण परिषद गांवों के विकास में सक्रिय सहयोग कर सकती है

सारिणी स० 7 । जनपदमे विकास खण्डवार औद्योगिक इकाईयाँ

विकास खण्ड का नाम	1979-80				1984-85			
	संख्या	वृहत उद्योग व्यक्ति	लघु उद्योग संख्या	व्यक्ति	वृहत उद्योग स० व्य०	लघु उद्योग स० व्य०		
सदर	-	-	36	98	2	723	47	151
लक्ष्मणपुर	-	-	1	3	-	-	12	42
मान मन्थ	-	-	2	7			07	24
स० चोन्दका	-	-	2	7			09	30
नारीपुर	-	-	2	6			12	38
कुन्डा	-	-	18	65			08	38
कालाकाकिर			06	20			11	44
बाबागज			02	07			17	71
विहार			01	03			09	33
रामपुरग्राम			06	21			08	29
पट्टी			12	40			24	91
गौरा			05	17			14	67
शिवगंज			10	36			22	77
मगरोरा			02	07			03	39
आसपुर देवसरा			04	14			07	25
ग्रामीण योग	-		99	351	2	723	210	799
नगरोय	4	126	86	308	4	107	147	598
जनपद	4	126	185	659	6	830	357	1397

**सारिणी सख्या 7.2 प्रतापगढ जनपद के अधिवासों में पायी जाने वाली
सेवाओं में मध्यम जनसख्या सीमा**

क्रम सख्या	सेवाये	मध्यम जनसख्या सीमा
01	प्राइमरी स्कूल	962
02	जूनियर हाईस्कूल	2529
03	हाईस्कूल	1120
04	इन्टर कालेज	1512
05	डिग्री कालेज	2663
06	चिकित्सालय	1114
07	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1027
08	परिवार कल्याण केन्द्र	1031
09	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	1150
10	औषधालय	1031
11	डाकघर	1027
12	तारघर	1292
13	बस स्टेशन	1027
14	बैंक	3157
15	बाजार	1027
16	पुलिस स्टेशन	1848

स्रोत परिकलित

6 आकड़ों की कमी के कारण पर्याप्त एवं आवश्यक सूचना सामग्री अनुपलब्ध है । प्रत्येक विकास खण्ड में "डेटा बैंक " बनाने की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः ये कार्य भी नीति के अन्तर्गत किया जाना चाहिये ।

यह टी कुछ महत्वपूर्ण सदर्भ है, किन्तु यह पूर्ण नहीं है । इस दिशा में ओर अधिक शोध की आवश्यकता है ।

SELECTED BIBLIOGRAPHY

1. Ackerman, Edward A (1958), Geography as a Fundamental Research Discipline, University of Chicago, Department of Geography research paper No 53
2. Ahmad, E (1952), Rural Settlement Types in Uttar Pradesh, A.A.A.G. Vol. 42
3. Ahmad, E (1953) Village Survey, Ind. Geog. JI, Vol 28 No. 182.
4. Ahmad, E (1962) Indian Village Patterns, Geog. Outlook, Vol 3, No. 1.
5. Ahmad, E (1976), Some Aspects of Indian Geography, Allahabad . Central Book Depot.
6. Alam, S.M. (1965), Hyderabad-Secunderabad : A study in Urban Geography, Bombay Allied publishers
7. Alam, S.M. (1972), Metropolitan Hyderabad and Its region : A strategy for development, New Delhi : Allied Publishers.
8. Berry, B.J.L. and Garrison, W.L., (1958), A note on Central Place Theory and the Range of a good, Economic Geography, Vol. 34, PP 304-11.
9. Berry, B.J.L. and Garrison, W.L. (1958), The Functional Bases of the Central Place Hierarchy, Economic Geography, Vol. 34, PP 145-54.
10. Berry, B.J.L. (1967), Geography of Market Centres and Retail Distribution, Englewood Chiffs : Prentice - Hall.
11. Berry, B.J.L. (1973), The Human Consequences of Urbanization London . Macmillan.

12. Bhagat, Bibhe (1982), Spatial System of Class II Towns of U.P., D.Phil Dissertation (Unpublished), Allahabad University.
13. Boudeville, T.R., (1966), Problems of Regional Economic Planning Edinburgh University Press.
14. Beguin, H., (1979), Urban Hierarchy and the Rank-Size Distribution, Geographical Analysis, 2
15. Bennett, R.J. (1981), Quantitative Geography and Public Policy, London Routledge & Kegan paul.
16. Bhat, L.S. et al. (1976) Micro Planning A case study of karnal area, Haryana · R.B. Publications
17. Bhoosan, B.S. (1981), Towards Alternative Settlement Policy, New Delhi : Heritage-
18. Breese, G. (1963), Urban Development Problems in India, A.A.A.G., 53, 253-265.
19. Brush, J E (1953), The Hierarchy of Central Places in South Western Wisconsin, Geog. Rev. 43, 380-402
20. Brush, J E. and Bracey, H.E. (1955), Rural Services Centres in South Western Wisconsin and Southern England, Geog. Rev. 45, 559-69.
21. Christaller, W. (1966), Central Places in Southern Germany (Translated by C.W. Baskin) New Jersey : Engle wood cliffs.

22. Chisholm, M. and Manners, G. (eds) (1973), Spatial Policy Problems of the British Economy, London Cambridge University Press.
23. Clark, J.I., Population Geography Second Edition, Oxford and New York Pergamon
24. Comeron, G. and Wingo L. eds (1970), Cities and Regions, Edinburgh Oliver and Boyd
25. Davis, Kingsley (1973), Cities, Their Origin, Growth and Human Impact, Readings from Scientific American, San Francisco W.H. Freeman.
26. Dickinson, R.E. (1932), The Distribution and Function of the Smaller Urban Settlements of East Anglia, Geography, 17, 19-31.
27. Drewnowski, J. (1970), Studies in the Measurement of Levels of living and welfare, UNRI.
28. Drewnowski, J (1974), On Measuring and Planning the Quality of Life, The Hague . Monton.
29. Davis K. (1951), The Population of India and Pakistan, New Jersey : Princeton
30. Dacey, M.F. (1962), Analysis of central place and Point Patterns by a Nearest Neighbour method, Lund studies in Geography, Series B, Human Geography, 24, 55-75.
31. Dacey, M.F. (1966), Population of Places in a Central place Hierarchy, J. of Reg. Science, 6, pp. 27-33.

32. Dutta, S S. (1981), India's Urban Future · Role of Small and Medium Towns, Jl. of the Institute of Town Planners, India, 106, p. 1-7.
33. Dwivedi, R.L. (1963), Origin and Growth of Allahabad, Ind.Geog. Jl. 38, 16-32.
34. Dwivedi, R.L. (1964), Delimiting the umland of Allahabad, Ind. Geog. Jl. 39, 123-139
35. Dwivedi, R.L (1965), Demographic Features of Allahabad city, Geog. Rev. Ind., 27, 163-188
36. English, Paul ward and Mayfield, Robert C. eds (1972), Man, Space and Environment, New York : Oxford University Press.
37. Enyedi, G.Y. (1964), Geographical Types of Agriculture, Applied Geography in Hungary, Budapest.
38. Farooqi, Z (1987), Spatial system of class IV Towns of U.P. D. Phil dissertation, Allahabad University.
39. Friedman, J. and Alonso, U. eds (1964), Regional Development and planning : A Reader, Cambridge
Massachusetts, M.I.T. Press
40. Friedman, J., (1966), The Urban Regional frame of national development, International Development Review.
41. Friedman, J., (1972), A general theory of Polarised development in N.M. Hansen (ed.) Growth Centres in Regional Economic Development, New York.

42. Friedman J., and Doughloss, (1976), Agripolitan Development, Towards a new strategy for Regional development in Asia, Proceedings of the Seminar on Growth Pole strategy and Regional Development in Asia UNCRD, Nagoya, pp. 337-387
43. Friedmann, J., (1988), The Strategy of Deliberate Urbanisation, AIP Journal.
44. Galpin, G. J., (1915), The Social Anatomy of an Agricultural Community, Research bulletin Agricultural Experiment Station University of Wisconsin Madison, Vol 34.
45. Ghosh, B.N., (1955), Fundamentals of population Geography, New Delhi • Sterling Publication.
46. Hansen, N.M. (1974), Public Policy and Regional Economic Development : the experience of nine western countries Cambridge Massachusetts . Ballinger.
47. Harvey, D., (1969), Explanation in Geography, London Edward Arnold.
48. Harvey, D , (1972), Social Justice and the city, London Edward Arnold
49. Harvey, D., (1972), Limits of capital, London : Basil Blackwell.
50. Harvey, D., (1974), What kind of Geography for what kind of public policy ? Transactions, Institute of British Geographers, 63, 18-24.

51. Harvey, D., (1976), The Marxist Theory of the State ·
Antipode 8 (2) 80-9
52. Haggett, P , (1977), Geography : A modern synthesis, New
York Harper Row.
53. Hardoy, J.E. and Satterthwaite, D. (1981), Shelter, Need
and Response, New York John Wiley & Sons.
54. Hammond, C.W. (1982), Elements of Human Geography,
London · George Allen & Unwin.
55. Hermansen, Tormod (1971), Spatial Organization and
Economic Development, Mysore Int. of Dev. Studies.
56. Hirschman, A.O. (1969), The Strategy of Economic
Development, New Haven Yale University Press.
57. Hoselitz, B.F. (1959), Cities of India and their problems, A
Review Article, A.A.A.G. 49, 223-231.
58. James, Preston (1972), All possible Worlds, Indianapolis
odyssey Press
59. Jefferson, M. (1931), Distribution of the World's City Folks
A study in Comparative Civilization, Geog. Rev. 21,
446-465.
60. Jefferson, M. (1939), The Law of Primate City, Geog. Rev.
29, 226-232.
61. Johnston, E.A.J. (1970), The Organization of Space in
Developing Countries, Cambridge, Mass : Harvard University
Press.

62. Johnston, R J. (1980), City and Society, London Penguin.
63. Johnston, R.J. (1983), Texts, Actors, and higher Managers, Judges, Bureacrats and the Political Organization of Space, Political Geography Quarterly, 2,3-20
64. Johnston, R.J (1987), Geography and Geographers, London : Edward Arnold.
65. Jones, H.R. (1981), A Population Geography, London and New York Harper and Row
66. King, L.J. (1969), A Quantitative Expression of the pattern of Urban Settlements in selected Areas of United States, Ambrose, P (ed), Analytical Human Geography, London Longmans, pp. 89 - 102.
67. Kuklinski, A. and R. Petrella (eds), (1971), Growth Poles and Regional Policies, The Hague Mouton.
68. Kuklinski, A R.(ed) (1972), Growth Pole and Growth Centres in Regional Planning, Mouton : Paris.
69. Kuklinski, A.R (ed) (1975), Regional Development and Planning, International Perspectives, The Netherlands.
70. Lanegran, David A. and Palm, Risa (1978), An Invitation to Geography, 2d ed New York . Mcgraw Hill
71. Kayastha, S.L. and Prasad, J. (1978), Approach to area Planning and Development strategy : A case study of Phulpur Block, Allahabad district, N.G.J.I., Vol. 24

72. Kayastha, S.L. and Singh, R B (1980), Emerging dynamics of Integrated Rural development, N.G.J.I., Vol. 26 No.3 & 4
73. Kayastha, S L. and Singh, B.N. (1981), Spatial Strategy for Integrated Rural area development A case study of Ghazipur Tahsil (U.P.), India, N.G.J.I , Vol. 27 No. 1 & 2
74. Kumra, V.K. (1980), Environmental Pollution and Human Health A Geographical study of Kanpur City, N.G.J.I., 26, 1 & 2, 60-69
75. Keeble, D. (1967), Models of Economic Development, in R.J. Chorley and P. Hagget (1967), Models in Geography, London Methuen.
76. King, L.J. and Clark, G.L. (1978), Government Policy and Regional Development, Progress in Human Geography, 2, 1-16.
77. Losch, A. (1954), The Economics of Location, (Translated by W H. Waglam & W.F. Stölper) New Haven Yale University Press.
78. Mabogunje, A.L. (1981), Rural development in Nigeria Problems, Policies and issues, in Misra, R.P. (edit) Rural development : National Policies and Experiences, Maruzen Asia.
79. Mayfield, R.C. (1967), A central Place Hierarchy in Northern India, Quantitative Geography Pt. 1. Economics and Cultural Topics, Illinois PP. 120-66.
80. Misra, H.N. (1975), The Size and Spacing of Towns in the Umland of Allahabad, The Geogr , 22

81. Misra, H.N. (1976), Hierarchy of Towns in the Umland of Allahabad, Dec. Geogr., 14, 34 - 47.
82. Misra, H.N. (1977), Empirical and Theoretical Umlands, Allahabad A case study, Geog. Rev. Ind., 39, 312 - 319.
83. Misra, H.N. (1980), Genesis of Small and Intermediate Towns in the Mid - Ganga Valley, Analyt. Geog., 2, 19-28.
84. Misra, H.N. (1981), Rural Roots of Urban Poor : A case study of Informal Sector in an Indian City, in Misra R.P. (edit), Rural Development and National Policies and Experiences, Singapore : Maruzen Asia, 211 - 229.
85. Misra, H.N. (1982), Human Settlement System and Regional Development in a developing Economy : A case study of a Micro-region in North India, in Kammeir, H.D. (etall) (1984) Equity With Growth ? Planning Perspectives for Small Towns in Developing Countries, Bangkok . AIT.
86. Misra, H.N. (1984), Urban System of a Developing Economy Allahabad : IIDR and also in 1988, New Delhi : Heritage Publishers.
87. Misra, H.N. (edit) (1987), Rural Geography, Heritage : New Delhi.
88. Misra, H.N. (1988), Bhutan : Problems and Policies, Heritage : New Delhi.
89. Misra, H.N.(1982) Spatial System of Small and Intermediate Towns, The Geographer, Vol. 27, No.2

90. Misra, H.N. (1981) Simulating the Spatial Pattern of Class II Towns of U.P. Geographical Outlook, Ranchi
91. Misra, H.N. (1990) Reflections on Indian Urban Geography, Trans. Institute of Indian Geographers, Vol. 12, No. 2, 1990.
92. Misra, H.N. (1989) Traditional and Contemporary Paradigms of Urban Geography, Annals, NAGI 1989, Vol. 19, No.1.
93. Misra, H.N. (1988) Dynamics of Population in Rae Bareilly, Sultanpur and Pratapgarh Districts, The Geographer, Vol. 35, No. 1, 1988, pp. 43-53.
94. Misra, H.N. (1987) Role of Small and Intermediate Towns : A Conceptual Frame, The Indian Geographical Journal Vol. 62, 1987.
95. Misra, H.N. et al (1987) An Evolutionary Model of Service Centres in a Slow Growing Economy in Misra, H.N. (edit) Rural Geography, Heritage, New Delhi, 1987, pp. 232 - 245.
96. Misra, H.N. (1987) Habitat and Health in an Indian Village in Misra, H.N. (edit), Rural Geography, Heritage, New Delhi, 1987, pp. 191-202.
97. Misra, H.N. (1986), A Model of Economic Base and its application to the Towns of Uttar Pradesh in P D Mahadev (edit), Urban Geography, Heritage : New Delhi, 1986.
98. Misra, H.N. (1983) Ruralization of Indian Cities A Study in Process of Penetration of Rural Functions in Urban Areas of Slow Growing Economics, Urban India, Vol.3, No 3, 1983

and also in K V Sundram, (edit), Geography and Planning, Concept, New Delhi

99. Misra, H N (1983) Informal Sector in Indian Cities .. Case Study of Rickshawpullers, Transaction Institute of Indian Geographers, Vol 5, 1983.
- 100 Misra, H.N. & Chapman, G P. (1991), Pattern of Growth of India's Class I Cities, Ceoforum (U.K.), Vol. 22, 1991
- 101 Misra, H.N. (1990) Housing and Health in Three Squatter Settlements in Allahabad, India (Chapter Four) in Jorge E. Hardoy et al (ed) Housing and Health in Third World Cities Earthscan, London, 1990.
102. Misra, H.N. (1968) Popular Settlements in the City of Allahabad, Cities - The International Journal of Urban Policy (U.K.), Vol 5, No.2, 1988.
103. Misra, H.N. (1986) Rae Bareli, Sultanpur and Pratapgarh Districts, (U P.), Northern India (Chapter 5) in Hardoy, J.E and Sattarthwate, D. (ed) Small and Intermediate Urban Centres : Role in National and Regional Development in theThird World, Hodder & Stoughton, London, 1986.
- 104 Misra, H N. (1986), Technology Transfer and Change . The Case of Three Districts in U.P., Commission on International Division of labour and Regional Development, International Geographic Union, Zaragoza (Spain), 1986.

105. Poverty, Economic Stagnation and Diseases in Uttar Pradesh (Chapter 8) in Tulchin, Joseph, S. (ed) Habitat, Health and Development, Lynne Rienner Publisher, Colorado (U.S.A.), 1986.
106. Misra, H.N. (1984) Human Settlement System and Policy Implications for Regional Development in Developing Economy : in Kammeir H.D. et. al (ed) Planning Perspectives for Small Towns in Developing Countries : AIT, Bangkok, 1984
107. Misra, H.N. (1983) Rural-Urbans in Sudan . A Case Study of Gozira Ekistics - An International Journal of Human Settlement (Greece), Vol. 300, 1983
108. Misra, H.N. (1980) Towards an Alternative Settlement Policy : The Case of India (Mimeo) UNCRD Nagoya, 1980.
109. Misra, R.P. (1971), The Diffusion of Information in the Context of Development Planning, Lund Studies, Series B in Human Geography, No. 27.
110. Misra, R.P. et. al. (1978) Regional Planning and National Development, New Delhi . Vikas.
111. Misra, R.P. et. al (1974), Regional Development Planning in India : A New Strategy, New Delhi : Vikas.
112. Misra, R.P. (edit) (1979), Habitat Asia : Issues and Responses, Vol. 1-3, New Delhi . Concept.
113. Misra, R.P. et. al. (1980), Multi-Level Planning and Integrated Rural Area Development in India, New Delhi . Heritage.

114. Misra, R.P. (1981), Humanizing Development, Singapore Maruzen Asia.
115. Misra, R.P. (1985), Development Issues of Our Time, New Delhi : Concept.
116. Misra, R.P.(1990), District Planning : A Hand book, Concept New Delhi
117. Mitra, A., (1965), Level of Regional Development in India, New Delhi . Government of India.
118. Myrdal, G. (1957), Economic Theory and Under Development, London.
119. Nath, V., (1970), Regional Development in Indian Planning, Economic and Political Weekly, Annual Number, January, pp. 240-260.
120. Nevill, H.R (1904), Pratapgarh : A District Gazetteer, Allahabad : Govt. Press.
121. Perroux, F., (1950), Economic Space . Theory and Application, Quart. Jl. of Economics.
122. Perroux, F., (1955), La Notion de Croissance, Economique Applique Nos. 1 & 2.
123. Preston, R.E. (1971), The Structure of Central Place Systems, Eco. Geog. 47, '2, 136 - 155.
124. Ramesh, A., (1964), Origin and Evolution of Ootacamund, N.G.J.I, 10, 16 - 28.

125. Rao, V L S P., (1961), The Problems of Metropolitan Region Geographer's Point of View, Jl. of the Inst. of Town Planners, India, 25-26
126. Rao, V L.S P , (1964), Towns of Mysore State, Bombay / Asia Publishing House
127. Rao, V L S.P., (1966), Urban Telangana Ekistics, 21
128. Rao, S K , (1973), A Note on Measuring Economic Distances between Regions of India, Economic and Political weekly, 28 April.
129. Ramchandran, H , (1980), Village Cluster and Development, Concept New Delhi.
130. Raza, M., (1980), Regional Development in Historical Perspective, Pariyojan, Vol. 1 No. 1.
131. Richardson, H W. (1973) Regional Growth Theory, London Macmillan.
132. Raza, M. et al (1981), India - Urbanization and National Development, in Honzo, M. (ed), Urbanization and Regional Development, Maruzen Asia : Singapore
133. Rondinelli, D.A. (1983), Secondary Cities, in Developing Countries : Policies for Diffusing Urbanization, Sage Publication . Beverly Hills.
134. Salter, Christopher L. (1971) The Cultural landscape Belmont, California Duxburg Press wooldridge, Sidney w. and East w. gordon of geography, New York - Putman.

135. Shukla, L.R. (1957), Rural Development Alternatives in India, Faizabad District A Case Study, Unpublished D Phil thesis University of Allahabad
136. Singh U. (1958), Demographic Structure of Allahabad N.G.J.I. 4, 163 - 188
137. Singh, U. (1960) Evolution of Allahabad, N.G.J.I. 4 109-129
138. Singh, R.L. (1955), Evolution of Settlements in Middle Ganga Valley N.G.J.I. No. 2.
139. Singh R.L. et. al (ed) (1975), Readings in Rural Settlement Geography, Varanasi . N.G.J.I.
140. Singh, L.R. (1958), Rural Settlements in the Terai Region of U.P., Nat. Geogr. Vol 3
141. Singh, L.R. (1958), The Role of Geographers in Town Planning, Nat. Geogr. 1
142. Singh J. (1971), Rural Settlements Types and Patterns in Baghelkhand, Madhya Pradesh, India, N.G.J.I. Vol 17, No.4.
143. Singh, K.N. (1981), Spatial Analysis of Rural Settlements and their Types in Lower Ganga Ghaghra Doab, N.G.J.I. Vol 27 No 3 & 4.
144. Singh, O.P., (1971), Relationships of Rank Size and Distribution of Central Places in Uttar Pradesh, Nat. Geogr., 6, 19-30.

145. Sinha, Usha (1983), Service Centres and their Role in the Diffusion of Agricultural Innovations in Karchhana Tehsil of Allahabad District, Unpublished D Phil Thesis, University of Allahabad.
146. Slater, D. (1975), Underdevelopment and Spatial inequality, Progress in Planning, 4, 97 - 167.
147. Stohr, W and Todtling, F., (1977), Spatial Equality - Some antitheses to current regional development doctrine Papers of the Regional Science Association, 38, 33 - 53.
148. Stohr, W and Taylor, D R F , (1980), Development from Above and Below, London John Wiley.
149. Stamp, L D. (1962) The land of Britain, its Use and Misuse, 111rd Edition, London Longmans.
150. Shafi, M (1960), Measurement of Agricultural Efficiency of Uttar Pradesh, Economic Geography, Vol. 36, 4 pp. 296-305.
151. Shafi, M., (1972), Measurement of Agricultural Productivity of the Great Indian Plain, Geography, Vol. 19, No. 1, pp. 4 - 13.
152. Smith, D.M. (1977), Human Geography : A welfare Approach, London Edward Arnold.
153. Smith, D.M., (1979), Where the Grass is Greener - Living in an Unequal world, Baltimore The John Hopkins University Press.
154. Stewart, C.T , (1951), The Size and Spacing of Cities, Geog. Rev., 48, 222 - 245.

155. Sundararam, K.V., (1977), Urban and Regional Planning in India, New Delhi - Vikas.
156. Sundararam, K.V., (1983), Geography of under-development New Delhi - Concept.
157. Tiwari, A.K. (1982), Spatial Aspects of Rural Development in Indian Desert, The Geographer, Vol. 29, No. 2, 26 - 35.
158. Tiwari, P.S., (1968), Functional Pattern of Towns in Madhya Pradesh, N.G.J.I. 14, 41 - 54
159. Trewartha, G.T., Chinese Cities - Origin and Functions, A.A.A.G. 42 - 69 - 93
160. Ullman, E.L., (1941), Theory of Location for Cities - The American JI. of Sociology, Vol. 46, 853 - 64
161. Ullman, E.L., and Machael F.D., (1960) The Minimum requirement approach to the Urban Economic base Reg. Sci. Assn. Papers and Proceedings, pp. 175 - 194
162. Von, Thunen H. (1826), Deriso-lernte State in Beziehung Hug Landwirts Chaft and National Konomic, Rostock Translated by Warteburgh C.M. As Von Thumen's Isolated State, London - Oxford University Press.
163. Woodcock, R.G. and Bailey, M.J., (1978), Quantitative Geography, Macdonald and Evan - Plymouth.
164. Zelinsky, Wilbur (1973), The Cultural Geography of the United States, Englewood Cliffs - New Jersey - Prentice Hall.
165. Zipf, G.K. (1949), Human behaviour and Principle of least effort New York - Addison - Wesley Press.

परिशिष्ट 1

भारतवर्ष की जनसंख्या वृद्धिदर तथा मृत्युदर

1911-20	48.1	48.6	19.4	20.0
1921-30	46.4	36.3	26.9	26.6
1931-40	45.2	31.2	32.1	31.4
1941-50	50.9	27.4	32.4	31.7
1951-60	41.7	22.8	41.9	40.6
1961-70	41.2	19.0	46.4	44.7
1971-80	37.2	15.0	50.9	50.0
1981-86	33.2	12.2	55.6	56.4

परिशिष्ट 2 प्रतापगढ़ जनपद में लिंग अनुपात

वर्ष	जनपद प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	भारत
1901	1045	937	972
1951	1059	910	946
1961	1062	909	941
1971	1016	879	930
1981	1016	886	935

स्रोत प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैंड बुक 1961,
भारतीय जनगणना 1961, 1971, 1981

विकासखण्ड के नाम	1961	1971	1981
सदर	1094	999	986
लक्ष्मणपुर	1122	1071	1045
मानधाता	1040	1067	1031
स० चन्द्रिका	1212	1061	1036
सागीपुर	1120	1013	1004
कुन्डा	1045	940	985
कालाकाकर	965	968	980
बाबागज	1036	1032	1013
बिहार	1051	1019	988
रामपुरखास	1056	1018	1004
पट्टी	1068	1021	1045
गोरा	1088	1050	1035
शिवगढ	1096	1062	1040
मगरोरा	1057	1035	1023
आसपुरदेवसरा	1038	933	1027

वर्ग	1961	1971	1981	
कृषक	69 3	61 6	55 65	प्रार्थमिक व्यवसाय
कृषक मजदूर	17 5	26 0	28 84	" "
उत्खन्न मछली पालन पशुपालन, वृक्षारोपण	0 14	0 9	-	" "
पारिवारिक उद्योग	5 4	3 4	2 9	द्वितीयक व्यवसाय
गैर पारिवारिक उद्योग	0 5	1 0	-	" "
व्यापार तथा वाणिज्य	2 1	2 4	-	" "
परिवहन एवं सेवाएँ	0 64	0 4	-	तृतीयक व्यवसाय
अन्य सेवाएँ	4 0	5 0	13 6	" "

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961-81

वर्ष	1970-80	1984-85
बृहत उद्योग	4	6
दैनिक कार्यरत व्यक्ति	126	830
लघु उद्योग	185	347
दैनिक कार्यरत व्यक्ति	659	1397

जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1980, 1987